

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

27 मार्च, 1982

खण्ड 1, अंक 11

अधिकृत विवरण

भानिवार, 27 मार्च, 1982

विशय सूची

	पृष्ठ संख्या
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(11)1
वाक आउट	(11)6
वर्ष 1982-83 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(11)7
वाक आउट	(11)24
वर्ष 1982-83 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(11)24
बैठक का समय बढ़ाना	(11)59
वर्ष 1982-83 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(11)60

हरियाणा विधान सभा

भानिवार, 27 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन,
सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव
राम सिंह)

ने अध्यक्षता की।

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब वर्ष 1982-83 के बजट पर जनरल डिस्कान डिज्यूम होगी। (गोर एवं विघ्न)

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, मेरी एक सबमिशन है। स्पीकर साहब, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि श्री बलदेव तायल की जो वनमैन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की लीकेज के बारे में आपने राव रामनारायण की चेयरमैनशिप में एक स्पेशल कमेटी इंस्टीच्यूट की थी उसकी रिपोर्ट 23 तारीख को हाउस में पेश होनी चाहिए थी लेकिन वह रिपोर्ट हाउस में नहीं आई है। वह रिपोर्ट हाउस में कब तक पेश कर दी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष: मैं इस बारे में सोमवार को 4.00 बजे अपनी रूलिंग दूंगा।

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा और आपकी रूलिंग को चाहूंगा। मैं किसी बुरी भावना से किसी सदस्य के खिलाफ कुछ भी नहीं कहूंगा। स्पीकर साहब, हाउस की जितनी भी कमेटियों बनी हुई हैं। उनकी रिपोर्ट जो आपके पास आ चुकी है उनको हाउस में पेरा किया जाये। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि लीडर आफ दि हाउस इस मामले के बीच में न आये। किसी भी कमेटी ने पता नहीं क्या रिपोर्ट लिखी है। लेकिन स्पीकर साहब, जिन कमेटियों की रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है। उनको आप हाउस के सामने पेरा कर दें। जो भी रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है यदि आप उनको 30-3-82 से पहले हाउस में पेरा नहीं करेंगे तो हम यह समझेंगे कि सरकार उन रिपोर्टों को हाउस में पेरा होने में रूकावट डाल कर आपकी कुर्सी का मिसयूज करने की कोशिश में लगी हुई है।

श्री अध्यक्ष: मेरे पास मिस्टर गर्ग से संबंधित प्रिविलेज कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी मैंने उसको ब्लोक कर दिया है।

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मेरी आपसे बार बार प्रार्थना है कि आपके पास जो रिपोर्ट आ चुकी है उनको हाउस में पेरा कर दिया जाये।

श्री हीरा नंद आर्य: स्पीकर साहब, हम यह जानना चाहते हैं कि प्रिविलेज कमेटी की तरफ स्वामी आदित्यवे । और चौधरी संत कंवर के बारे में रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है या नहीं ? अगर आ चुकी है तो वह रिपोर्ट हाउस में कब तक पे । की जायेगी?

श्री अध्यक्ष: प्रिविलेज कमेटी की तरफ से मेरे पास एक रिपोर्ट आई है यह मुझे ध्यान नहीं है कि वह किस मामले से संबंधित है ।

श्री हीरा नंद आर्य: स्पीकर साहब, जिन कमेटियों की रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है वे कम से कम हाउस में तो पे । हो जानी चाहिए । (गोर व विघ्न)

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, जिन कमेटियों का बिजनैस पूरा हो गया है ओर अपनी रिपोर्ट आपको दे दी है, वे रिपोर्ट्स हाउस में पे । होनी चाहिए । जिन जिन कमेटियों की रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है वे हाउस में पे । की जाये ।

श्री अध्यक्ष: प्रिविलेज कमेटी की तरफ से एक रिपोर्ट मेरे पास कल या परसों आई है मैं उसको एग्जामिन करूंगा । (गोर व विघ्न)

श्री हीरा नंद आर्य: स्पीकर साहब, मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है । अतः वह रिपोर्ट हाउस में कब तक आ जायेगी ।

श्री अध्यक्ष: आर्य साहब, मेरे पास एक रिपोर्ट आई है। मुझे ध्यान नहीं है कि वह रिपोर्ट किसके बारे में है। Every report that has been sent to me will come before the House.

श्री हीरा नंद आर्य: स्पीकर साहब, बहुत सी कमेटियों की रिपोर्टें तैयार हो चुकी हैं और आपके पास आ चुकी हैं। लेकिन सरकार उन रिपोर्टों को हाउस में पेश होने में डिले करवाना चाहती है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि सारी रिपोर्टों को हाउस में पेश किया जाये ताकि उन पर बहस हो सके।

श्री अध्यक्ष: आर्य साहब, सरकार को यह पता भी नहीं होगा कि कौन सी रिपोर्ट आ चुकी है और कौन सी रिपोर्ट नहीं आई है।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मैंने आपकी सेवा में एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया था। वह नोटिस आपकी सेवा में मैंने 17 तारीख को दिया था। मैंने उसमें कहा है कि स्वामी आदित्यवेश ने अपने दौरे में डबल ट0ए0, डी0ए0 लिया है। लेकिन आज 10 दिन हो गये हैं वह मोशन अभी तक हाउस में पेश नहीं हुआ है।

Mr. Speaker: I had referred it for detailed examination of position about the alleged claiming of T.A. & D.A. by Swami Aditya Vesh. उसमें बड़ा लैथी काम है। इस बारे में, मैं अपनी रूलिंग मंडे को 4.00 बजे दूंगा।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, सबोर्डिनेट लैजिस्ले इन कमेटी की रिपोर्ट आपको बहुत पहले दे दी गई थी। वह हाउस में आ जानी चाहिए थी। वह रिपोर्ट हाउस में कब तक आ जायेगी?

Mr. Speaker: It will come on the 30th.

स्वामी आदित्यवे तः स्पीकर साहब, मेरा व्यवस्था का प्र न है और मैं आपकी रूलिंग भी चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधान सभा का जितना भी कार्य है वह सारे का सारा पहले अंग्रेजी में किया जाता है ओर उसके बाद में उसका अनुवाद हिन्दी में किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से भी लगातार यह को ि त रही है कि हरियाणा विधान सभा का ज्यादा से ज्यादा कार्य हिन्दी में हो। मैं इस बात की भी सराहना करता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने भी इसकाम में अपना सहयोग दिया है। लेकिन आज तक हरियाणा राज्य के सभी विभागों का तमाम काम अंग्रेजी में ही होता है। जितने भी हिन्दी भाशी राज्य है उन्होंने अपना सारा काम मूलतः लीगल कार्य भी हिन्दी में करना भुरु कर दिया है लेकिन उसका अनुवार अंग्रेजी में हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं आप अपने आदे त के द्वारा सरकार को इस बात के लिये प्रेरित करें कि वह अपना मूल कार्य हिन्दी में करे और उसका अनुवाद बे तक अंग्रेजी में कर दे लेकिन मूल कार्य हिन्दी में होना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप

इस काम के लिये 15 अगस्त तय कर दे और उसके बार हरियाणा राज्य का सारा काम हिन्दी मे होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी इस बारे मे मेरी रूलिंग यह है कि यहां पर हिन्दी, इंगलि ा और पंजाबी तीन जुबानों का इस्तेमाल हो सकता है। मैं आपकी तरफ से हिन्दी भाशा को सबसे ज्यादा महत्व देने की कोि ा ा करता हूं। जहां तक लीडर आफ दि हाउस का सवाल है, उन की तरफ से गवर्नमेंट को डायरेक् ांज है कि हिन्दी भाशा को ज्यादा से महत्व दिया जाये । यह बात तो लीडर आफ दि अपोजी ान भी मानते है कि मैंने हिन्दी भाशा को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया है। लेकिन मेरा एक और भी विचार है कि इस काम मे ज्यादा जल्दवाजी नही करनी चाहिए। इस काम को ज्यादा फोर्स करने से कोई और रूकावट भी पैदा हो सकती है।

श्री जय नारायण वर्मा: महर्शि दयानंद यूनिवर्सिटी के बी0ए0, एम0एस के विद्यार्थियों ने नवम्बर, 1981 मे एकेडेमिक डिग्री पूरी कर ली थी। उन्हे 6 महीने के लिये हाउस जौब (इनटर्न िप) के लिये भेजा जाता है । लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी और सरकार के विवाद के कारण उन्हें हाउस जौब पर नही भेजा गया । सभी छात्र परे ान है। वे न तो सर्विस कर सकते है और न ही अपनी प्रैक्टिस कर सकते है। सरकार इस मामले को तुरंत तय करे ताकि उन्हें परे ानियों से बचाया जा सके।

श्री अध्यक्ष: आप लिख कर दीजिये। मैं उसको एग्जामिन करूंगा।

श्री मूल चंद जैन: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सी०एम० साहब का और सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि परसों डिमांडज फारा ग्रांटस पर बहस भुरू होगी। लेकिन स्पीकर साहब, आप यह सुन कर हैरान होंगे कि चंद डिपार्टमेंट्स के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ मार्च 1981 तक की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट भाया नहीं हुई है। मैं इस मामले में यह गलती एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट की तरफ से कहूँ या किसी और की तरफ से कहूँ लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से मार्च 1982 तक की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट भाया नहीं हुई है। स्पीकर साहब, यह लापरवाही इसी साल से नहीं हो रही पिछले साल भी यह लापरवाही हुई थी। पिछले साल मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को इस बारे में चिट्ठी लिखी थी कि किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट भाया नहीं हुई है। इसके लिये कायदा कानून यह है कि सैक्रेटरीज आफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी। जो साल 31-3-81 को खत्म हुआ उस साल की रिपोर्ट सितम्बर तक आनी चाहिए थी। लेकिन स्पीकर साहब, आप हैरान होंगे कि 1978-79 की रिपोर्ट अब आ रही है और 1979-80 की रिपोर्ट भी अब आ रही है। स्पीकर साहब, मैं पार्लियामेंट का मੈबर रहा हूँ।

पार्लियामेंट ने मिनिस्टर को रिपोर्ट दे दी हो और मिनिस्टर उस रिपोर्ट को दबा कर बैठ गये हो। मैंने इस साल भी चीफ सैक्रेटरी साहब को चिट्ठी लिखी लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब चीफ सैक्रेटरी मुझे देंगे इस बात का भी मुझे भाक है। स्पीकर साहब, इसके अलावा अभी हाउस के सामने यह मामला आया कि सरकार कमेटियों की मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्टों को हाउस में पे 1 होने में रूकावट डाल रही है। स्वाभाविक बात तो यह होती है कि प्रजातंत्र प्रणाली में जो भी रिपोर्ट है, वह हाउस के सामने पे 1 होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट है, सर्बोडीनेट लैजिस्ले 1न कमेटी की रिपोर्ट है या दूसरी कमेटियों की रिपोर्टस है, वे सभी हाउस में पे 1 होनी चाहिए। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है इसलिये मैं इस तरफ आपका ध्यान आकर्शित करना चाहता था।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजल लाल): स्पीकर साहब, अभी बाबू जी ने बोलते समय सरकार पर यह इल्जाम भी लगा दिया कि सरकार जान बूझकर रिपोर्ट पे 1 नहीं होने दे रही। जैन साहब काफी सीनियर मैनबर है, कई बार मंत्री मंत्री भी रह चुके हैं। मैं जैन साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने कभी ठीक समय पर कोई रिपोर्ट पे 1 की थी। ऐसे कामों में समय तो लगता ही है।

श्री मूल चंद जैन: यदि हमने चोरी की है तो क्या आप भी वही चेरी करेंगे?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख होता है जब ये बीच में बोलते हैं। किस समय बाबू जी या इनके दूसरे साथी बोलते हैं तो उस समय हमारा कोई साथी नहीं बोलता लेकिन जब भी मैं बोलने के लिये खड़ा होता हूँ तो ये बीच में बोलने लग जाते हैं। (गोर) मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपके समय में ठीक समय पर रिपोर्ट आ जाती थी ? किसी भी रिपोर्ट को पे 1 करने में क्या आपको समय नहीं लगता था?

श्री मूल चंद जैन: मैं तो सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि क्या यह हकीकत नहीं है कि रिपोर्ट हाउस में पे 1 होनी चाहिए। (गोर)

चौधरी भजन लाल: हम कब कहते हैं कि रिपोर्ट हाउस में पे 1 नहीं होनी चाहिए।

श्री मूल चंद जैन: जिस समय मैं फाईनैस मिनिस्टर था, मेरे से पहले भी आप मिनिस्टर रहे हैं और बाद में भी रहे हैं। यदि आप मेरी जगह होते हैं तो क्या आप वाक आउट नहीं करते?

चौधरी भजन लाल: बाबू जी मैं तो आपकी गार्ड्रैंस पर ही चलता हूँ। (गोर)

श्री अध्यक्ष: बाबू जी का यह कहना कि जो रिपोर्ट्स हैं वह हाउस में आनी चाहिए। लेकिन सी० एम० साहब तो ह्यूमन नेचर कम्पेयर कर रहे थे। मुख्य मंत्री जी तो यह कह रहे थे कि क्या बाबू जी के समय में रिपोर्ट समय पर हाउस में आया करती

थी। सी० एम० साहब रिपोर्टों को पे 1 करने की अपनी तरफ से पूरी को 1 1 कर रहे हैं। (गोर) मैं भी मानता हूँ कि यह डिमांड की डिस्क 1न के लिये बहुत जरूरी है। इस संबंध में, मैं गवर्नमेंट से रिकवैस्ट करता हूँ कि इस प्रकार से सभी रिपोर्ट हाउस में सर्क्यूलेट होनी चाहिए ताकि मेंबर साहेबान को डिमांडज की डिस्क 1न करने के लिये मौका मिल सके।

चौधरी भजन लाल: हम पूरी पूरी को 1 1 कर रहे हैं कि सभी प्रकार की रिपोर्ट हाउस में पे 1 हों।

डा. मंगल सैन: अभी स्पीकर साहब, आपने बजा फरमाया है कि मनुष्य का स्वभाव तुलना करना होता है। स्पीकर साहब, आप तुलना चाहे बे 1क कर ले। (गोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, मैं तुलना नहीं कर रहा। सी० एम० साहब कर रहे हैं।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि सभी प्रकार की रिपोर्ट हाउस में पे 1 होनी चाहिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, आपनु फरमाया है कि जितनी भी रिपोर्टें आ चुकी हैं वे सभी हाउस में पे 1 हो जायेगी। स्पीकर साहब, मेरी आप से एक रिकवैस्ट बहुत जरूरी है कि डिमांड की डिस्क 1न के लिये जब तक पूरे फैंक्टस और फिगरज नहीं आ जाते तब तक उन पर डिस्क 1न करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिये आप सरकार को आदे 1 दे कि डिमांडज प

डिस्कान से पहले पहले रिपोर्टस हाउस में आ जानी चाहिए। रिपोर्टस आने के बाद ही उन पर डिस्कान होनी चाहिए। इसलिये आप से मेरी रिकवैस्ट है कि इन रिपोर्टस को साइकलोस्टाईल कापी या प्रिंटिंग कापी हाउस में डिस्कान से पहले पहले पे 1 हो जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: सरकार की तरफ से यह आवासन दिया गया है कि वे सर्क्यूलेट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे।

श्री हीरा नंद आर्य: स्पीकर साहब, इनमें धांधली करने के सिर्फ चार ही दिन रह गये हैं। इनसे रिपोर्टस पे 1 नहीं होगी, ये सभी रिपोर्टस पे 1 नहीं होंगी, ये सभी रिपोर्टस हमें ही पे 1 करनी पड़ेगी। (गोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डा० साहब, हयुमन नेचर की बात कह रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पी०ए०सी० की रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट मेरे आने से पहले 6-7 साल पीछे की चल रही थी लेकिन अब ये सभी रिपोर्टस 2-3 साल पीछे की ही रह गई है। पिछले 2-3 साल की रिपोर्टस को छोड़ कर पी०एस०सी० कमेटी ने सारा काम कर लिया है।

वाक आउट

श्री भले राम: स्पीकर साहब, हमें भी यहां पर रोजाना वाक आउट करते समय भार्म आती है। आप भी सोचेंगे कि हम यहां पर हमें 11 हरिजनों की ही बातें करते रहते हैं। स्पीकर साहब, हरिजनों का रिजर्वे इन का कोटा कहीं पर भी पूरा नहीं हो रहा है। मैं आप को बताना चाहता हूं कि अभी पिछे फूड एण्ड स्प्लार्इ डिपार्टमेंट के अंदर इंसपैक्टरों की पोस्टें भरी गई है लेकिन वहां पर भी रिजर्वे इन कोटे को पूरा नहीं किया गया। इन्ही बातों को देखते हुए हमें सरकार की नुकताचीनी करने पर विव 1 होना पड़ता है। * * * * *

* * * *

श्री अध्यक्ष: यह रिकार्ड न किया जाये।

श्री भले राम: यदि आद हमें बोलने नहीं देते और सुनना भी नहीं चाहते तो मैं विरोध करता हुआ वाक आउट करता हूं।

(इस समय श्री भले राम सदन से वाक आउट कर गये)

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टस पर डिस्क इन होना बहुत जरूरी है। इस पर बहस के लिये हमने नोटिस भी दिया हुआ है। यदि इन रिपोर्टस को हाउस के अंदर डिस्क इन के लिये रखेंगे तभी इन पर बहस हो सकेगी। जो टाईम हाउस का इस समय फिक्स हुआ है, उसके अंदर हम

इन सभी विशयों पर पूरी तरह से बहस नहीं कर सकेंगे। इसलिये मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग दोबारा बुला ले। स्पीकर साहब, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि इस बात के लिये सारे मैनबर एजिटेडिट है कि राम नवमी की छुट्टी होनी चाहिए। इसलिये आप एक दिन का समय भी हाउस का बढ़ा दे। रामनवमी की छुट्टी के बाद सै 1 न 5 अप्रैल और 6 अप्रैल तक बढ़ा लिया जाये ताकि रिपोर्टों को टेबल पर रखने का कोई फायदा हो सके और उन पर डिस्क 1 न भी हो सके वरना उनको टेबल पर रखने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि समय की कमी के कारण मैनबर साहेबान बहस में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।

श्री अध्यक्ष: मैंने अपोजी 1 न को साथ में ले कर के गवर्नमेंट से रिकवैस्ट करके हाउस का समय 3 दिन बढ़ाया था। तीन सिटिंग नहीं बल्कि चार सिटिंग बढ़वाई थी। इसलिये सै 1 न दिनांक 29-3-82 को प्रातः 11 बजे से लेकर भाम 6.00 बजे तक का होगा। इस प्रकार से कुल चार सिटिंगज बढ़ाने का फैसला दोनों साइडस की राय से किया गया था। अब बिजनैस एडवाइजरी कमेटी के फैसले को रिव्यू करना ठीक नहीं है। अब यह मैटर क्लोज होता है। इस पर और बहस नहीं होगा अतः अब जीरो आवर समाप्त होता है।

वर्ष 1982-83 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष: चौधरी रिजक राम जी अब बजट पर अपनी डिस्कान रिज्यूम करेंगे।

चौधरी रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, कल आपकी मेहरबानी से टाईम मिलने पर मैं बजट के बारे में अपने विचार प्रकट कर रहा था। मैंने ऐसा कहा था कि विरोधी दल के साथियों को सरकार के कार्यक्रम पर, उनकी उपलब्धियों या कमियों पर नुक्ताचीनी करने का पूरा अधिकार है लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से लेकर आज तक जो कार्यवाही हुई उसके बारे में मुझे कुछ दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस दौरान सरकार की नीतियों पर रचनात्मक नुक्ताचीनी न करके केवल जाति लांछन ही लगाए गए हैं। मैं समझता हूँ कि यह सदन जाति लांछन लगाने के लिये उचित स्थान नहीं है। (विघ्न) स्पीकर साहब, रावी व्यास के पानी का वितरण के बारे में बाबू मूलचंद जैन जी ने काफी जोरदार भावों में नुक्ताचीनी की। स्पीकर महोदय, मैं एक बात अपने विरोधी दल के नेता के नोटिस में लाना चाहता हूँ। माननीय सदस्य स्वामी आदित्यवेरा जी ने उसके बारे में अपने विचार रखे और जो हालात थे उनका सही जायजा सदन के सामने रखा। मैं समझता हूँ बाबू मूलचंद जैन जी और दूसरे साथी, उन्होंने जो विचारधारा रखी है उस पर ठण्डे दिल से गौर गौर फारमायेंगे रावी व्यास के पानी के वितरण का झगड़ा कोई आज से नहीं है बल्कि 9-10 साल से यह झगड़ा हमारे और पंजाब के दरम्यान चल रहा है। इस दौरान बाबू मूलचंद जी मानेंगे कि चौधरी

चरणसिंह भी जनता पार्टी की सरकार रही, जिसमे हम भी शामिल थे और दूसरे साथ भी शामिल थे लेकिन इस बारे मे कोई फैसला नहीं हुआ। आखिर दे आ की मोहतरिम नेता श्रीमती इंदिरा गांध जिनके बारे मे कोई यह नहीं कह सकता कि उन्हे हरियाणा के लोगो के साथ सहानुभूति नहीं है, हमदर्दी नहीं है, वे हरियाणा के हकूक की रक्षा के लिये उत्सुक नहीं हे, ने ही यह काम किया। उन्होंने वही फैसला कराया जो सुप्रीम कोर्ट मे चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने कहा था। चौधरी देवी लाल की सरकार ने 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी के लिये सुप्रीम कोर्ट मे मांग की थी। सारी मजबूरी होते हुए भी, पंजाब के हालात और दे आ के हालात ठीक न होते हुए भी, प्रधान मंत्री ने अपना फैसला दिया। इसके बावजूद भी अगर ये कहें कि हमारी सरकार ने इसमे कोई कमजोरी दिखाइ है या कोई दूसरी बात की है, मुनासिब नहीं। पंजाब के हालात को आप देखें वहां विरोधी दल जो पाट्र अदा करते है उसके पिरणामस्वरूप दिल्ली की सरकार कई बार अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाती है। (विघ्न) स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा बाबू मूलचंद जैन जी से पूछना चाहता हूं कि पानी के वितरण के सिलसिले मे विरोधी दलों ने जो भूमिका निभाई है उसके बारे मे ये रो पानी डाले। उन्होंने पानी को हासिल करने के लिये क्या क्या कदम उठये वे हाउस को बता दे। अगर उन्होने कोई कदम उठाये हो तो हम मानेंगे। स्पीकर साहब, यहां नुक्ताचीनी की गई है कि यह सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। स्पीकर साहब, जैसा मैने कल कहा था, इस असैम्बली

मे हमें भी और इन सबको भी लाने वाली जनता पार्टी थी। हम सब उसमें शामिल थे। चौधरी देवी लाल जी उसके मुख्य मंत्री रहे, चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी इरीगे एंड पावर मिनिस्टर रहे हमारे मुख्य मंत्री जी भी उसमें मंत्री रहे, डा० मंगल सैन जी कभी उस सरकार में और कभी दूसरी सरकार में मंत्री रहते रहे। इदसलिये इन सब बातों के लिये किसी एक पार्टी पर इल्जाम तारा ि करना मुनासिब नहीं है। यह भी नहीं है कि जो विरोधी दल में बैठे हैं वे किसानों के या गरीबों के ज्यादा हमदर्द हैं और जो इधर बैठे हैं वे दू मन हैं सामान्य तोर पर हम सब उन्हीं घरानों से ताल्लूक रखते हैं। हम सब उनकी कठिनाईयों और गरीबी को जानते हैं। (विघ्न) स्पीकर साहब, हम सभी देहातों में पैदा हुए हैं। हम देहात की गरीबी के हालात से अनजान नहीं हैं। (विघ्न) * *

* * *

खाद्य एवं पूर्ति मंत्री (श्री लछमन सिंह): * * *

* *

चौधरी रिजक राम: * * * *

*

श्री अध्यक्ष: यह रिकार्ड न किया जाये।

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि हम सब देहात में पैदा हुए। हम देहात की गरीबी के हालात से अनजान नहीं हैं। मैं यह बात मानने के लिये तैयार हूँ कि कुछ घराने इस देश में पिछले तीस बत्तीस साल में अब य बहुत अमीर

हुए है। सन् 1975-76 में 20 घरानों की जो सम्पत्ति थी वह 5511 करोड़ थी लेकिन आज उससे भी दूगुनी हो गई और दूसरी तरु देहात में आज भी गरीबी की रेखा के नीचे 50 फीसदी के गरीब लजोग है। ऐसे लोग भी देहात में हैं जिनके बच्चे जब कभी अमीर घरों में ब्याह भादी होती हैं कुत्तों के साथ बिना कपड़ा और पैरों में जूता पहले अमीर आदमियों के जूठे टुकड़ों की इंतजार में रहते हैं। सर्दियों में वे लोग रुई नहीं खरीद सकते बल्कि जहां पंजु बंधते हैं वहां वे पंजुओं के साथ उनकी गर्मी में रात गुजारा करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं दावे के साथ कहता हूं कि बाबू मूलचंद जी भी ठंडे दिल से अगर सोचे तो यह भी महसूस करेंगे कि ऐसे गरीब लोग को इस सरकार ने राहत दी है। इस सरकार के समय में वाटर कॉर्मिज पक्के हुए, त्र बल्ड बैंक से कर्जा मिला। क्या बाबू मूलचूद जैन जी वित्त मंत्री के तौर पर और श्री विरेन्द्र सिंह जी इरीगे एण्ड पावर मिनिस्टर के तौर यह कह सकते हैं कि जो जमीदारों के खाल पक्के होने का कोई पैसा नहीं लिया। उन्हें माफी दे दी और उससे ऊपर के जितने भी किसान थे उनके लिये पचास परसेंट रियायत लगायी थी कि जितने भी खाल पक्के होंगे, उस पर जो खर्चा होगा यह सारा पैसा किसानों से वसूल किया जायेगा लेकिन फिर भी सरकार ने रियायत दी। जब बल्ड बैंक वालों को पता लगा और उनकी टीम यहां चण्डीगढ़ में आयी तो उन्होंने एतराज किया कि आप इस पैसे को माफ नहीं कर सकते और नहीं आप रियायत दे सकते हो। हमने वल्ड बैंक की टीम के सामने किसानों के हालात रखे। हमने कहा कि सन्

1961 में 16 फीसदी ऐसे किसान थे जो पांच एकड़ तक के भू स्वामी थे लेकिन 1979 में 73 परसेंट ऐसे किसान थे जो पांच एकड़ से भी कम के भू स्वामी थे। उनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक या दो बीघे के बिसवेदार हैं एक मील का खाल पक्का करने में एक लाख रुपये कसे ज्यादा खर्च होता है। इतने छोटे छोटे किसान इस पैसे को नहीं दे सकते। अंत में वर्ल्ड बैंक ने जो आपत्ति उठायी थी वह वापिस ली।

स्पीकर साहब, चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी बड़े फारवर्ड हैं अगर इससे कोई मजाक भी करे तो ये हंसते रहते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब तो कभी कभी तयारी भी चढ़ा लेते हैं लेकिन वे इन से कुछ भी नहीं कहे फिर भी हंसते रहते हैं। मैं चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि उनकी सरकार के टाईम जब चौधरी देवी लाल जी मुख्य मंत्री थे, क्या उस समय यह फैसला नहीं हुआ था कि अगर कोई भी माइनर बने, या एक्सटेन्ड हो तो आधा खर्चा जहाँ भी पानी जाता है वहाँ के किसानों को देना पड़ता था। ऐसा किसानों के साथ ऐग्रीमेंट किया हुआ था।

श्री अध्यक्ष: आप वाइंड अप करे। आप सारी बातें कह चुक हैं। (गोर व व्यवधान)

चौधरी रिजक राम: अभी खत्म करता हूँ। स्पीकर साहब, इस खर्चे के विषय में हमने फैसला किया है कि कोई नयी माइनर बनानी पड़े या बढ़ानी पड़े तो सारा खर्चा सरकार के जिम्मे होगा।

मैंने अपने टाईम पर पांच छ महीने में 35-36 माईनर्ज को मंजूर किया था। एक बात और भी अर्ज करना चाहता हूँ कि उस बात का न वजीर खजाना ने जिक्र किया है और न ही गवर्नर साहब के ऐड्रेस में जिक्र आया है। इस सरकार ने या मुख्य मंत्री ने ऐसे काम भी किये हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनका जिक्र इनमें आना चाहिए था। चौधरी गया लाल जी ने बोलते हुए कहा कि हरियाणा का बीटा घी दिल्ली में बहुत ज्यादा जाता है जो बहुत ही पापुलर है। इस सरकार ने घी को बाहर भेजने का भी प्रबंध किया है। यह बहुत ही अच्छा काम किया। स्पीकर साहब, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि हमारे मुख्य मंत्री और दूसरे मंत्रियों ने लोग के घर घर जा कर राहत देने की कोशिश की है।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब पांच मिनट आप कल बोले थे और आप भी आपको बोलते हुए 20 मिनट हो गये। दूसरे सदस्य भी बोलना चाहते हैं, इसलिये आप वाइंड अप करें।

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, आप भी देखते हैं कि जब से यह सैनिक भूरा हुआ है तब से मंत्रियों को बहुत ज्यादा काम हो गया है काम ज्यादा करने की वजह से मंत्रियों के चहरे पर थकावट के चिन्ह नजर आ रहे हैं। कुछ तो काम की वजह से और दूसरे इलैव इन सामने खड़े हैं। मेरा एक सुझाव है कि जो मंत्री बहुत ज्यादा योग्यता रखते हैं, भारिरिक और मानसिक भावित भी जिनकी सुरक्षित है ओर जिन्हे पूरा काम करने का

अवसर नहीं मिला है, उनके बारे में मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने ज्यादा काम किया है उन्हें थोड़े दिन के लिये आराम करने दें और जिन मंत्रियों और मंत्रियों को ज्यादा दिमागी काम करने का मौका नहीं मिला है। उन्हें मौका दे।

श्री अध्यक्ष: मुझे तो सभी मंत्रियों के चेहरो पर रौनक दिखाई दे रही है।

चौधरी रिजक राम: मैं आपकी एक बात से तो सहमत हूँ कि चेहरे पर पूरी रौनक है, लेकिन सब के चेहरो पर नहीं है। चौधरी खुरीद अहमद के चेहरे पर कुछ चंचलता दिखाई देती है। उसका भी एक कारण है। जितनी भी कीमती प्लॉट्स हैं उन्हें वे सिरहाना बना कर सोते हैं। सरदार लछमण सिंह का भी स्वभाव चंचल है लेकिन ऐसा नहीं है। वित्त मंत्री जी का यह खजाना छिन जाये तो लुकमान हकीम भी इलाज नहीं कर सकतां सन् 1980 का इलैक्ट्रान आप लोगों ने देख लिया होगा, उसका क्या असर हुआ। स्पीकर साहब यह राजनीति है। जैसे कोई जब पहाड़ी का चोटी पर चढ़ता है तो उसे हौसला रहता है लेकिन चोटी पर चढ़ने के बाद उसे नीचे जरूर देखना चाहिए ताकि उसे घमण्ड न हो जाये। इसलिये राजनीति में भी यही बात है उसे नीचे की ओर भी देखते रहना चाहिए। स्पीकर महोदय, जो मैंने पहले यह कहा है कि जिन्होंने ज्यादा काम किया है, वह उनको मौका न देकर दूसरो को मौका दे, यह चीफ मिनिस्टर साहे पर लागू नहीं होता। इन्होंने तो हरियाणा में स्थायी सरकार दी है। इनकी योग्यता से

बाबू मूलचंद जी भी इनकार नहीं कर सकते। जब भी जरूरत पड़ती है, हमारी पार्टी के सदस्य अनुपासन को देखते हुए ओर प्राइम मिनिस्टर के प्रति श्रद्धा रखते हुए, इनके साथ है ही, और उधर विरोधी दल की तरफ से भी यह मदद हासिल करने में सफल हो जाते हैं। स्पीकर साहब, एक बात की कमी रह गई। पिछले कुछ अर्से में केरल और आसाम में जो सरकारें बनीं, वे ज्यादा देर तक नहीं टिकी रह सकीं। मुझे मालूम नहीं, ऐसी हालत में वे लोग हमारे मुख्य मंत्री जी की योग्यता को क्यों भूल गये। अगर उनको वहां पर मौका देते तो उनको पता चलता। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री महोदय के बारे में एक अपील करना चाहूंगा इलैक यान तो बेतक वह लड़े या न लड़े लेकिन इनकी योग्यता को देखते हुए इनको रिजर्व कोटे में रख दिया जाये। जहां कहीं पर सूबे में हल चल दिखाई दे, वहां पर इनको भेज दिया जाये। स्पीकर साहब, हालात यहां तक भी पैदा हो सकते हैं कि इनकी योग्यता की विवेक में भी जरूरत पड़ जाये। यह हरियाणा का नाम विवेक में भी ऊंचा करेंगे। इससे हमारी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, वाइंड अप कीजिये।

चौधरी रिजक राम: बहुत अच्छी जी! स्पीकर साहब, मेरी एक दो बातें और रह गयी हैं, अगर उनको बोल लेने दें, तो अच्छा होगा! (व्यवधान) मैंने अब तक तो कोई ऐसी बात कही ही नहीं है जो सरकार को खराब लगे। वैसे जहां तक लैजिस्लेटर्ज का ताल्लूक है, उनके हिसाब से एक तरह से तो मुख्य मंत्री जी अच्छे

है। मैं यह बात कोई नुक्ताचीनी के तौर पर नहीं कहता बल्कि एक बात इस बारे में आपके सामने रखना चाहता हूँ। जहाँ तक जनमत के बारे में मेरा विचार है कुछ खुदगामदी लोग व कुछ अफसरान ओवर एनययूजिआस्टिक हो जाते हैं यह असलीयत का पता नहीं लगने देते। जलसे होते हैं उनके भी और वी०आई०पीज० के भी। मेरा कहना यह है कि यह अपनी सी०आई०डी० को और कुछ दूसरे अफसरान को इस बार में बेतक मुकर्र कर ले इन जलसों में, खास तौर पर वी०आई०पीज० के जलसों में पुलिस पटवारी से लेकर डी०सी० तक और दूसरे सब अफसर ट्रक लगाकर हाजरी पूरी करते हैं। (गोम भोम की आवाजें) इसमें भोम की कोई बात नहीं है। इससे इल्यूजन यह होता है कि हमारी बड़ी पापुलैरिटी है। हमारी सरकार की बड़ी पापुलैरिटी है। स्पीकर साहब, संजय गांधी जब 1976 या 1977 में करनाल में आये थे, उस समय भी यही ड्रामा हुआ था। हालांकि उस समय एक साल के लिये लोक सभा की अवधि बढ़ा दी गई थी लेकिन 12-14 लाख के करीब आदमी वहाँ पर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने इकट्ठे किये थे। उसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अमरजैसी हटा दी ओर चुनाव रख दिये जिससे आप भलीभांति परिचित हैं, इसके अलावा एक दूसरी बात मैं और कहना चाहूँगा। गेहूँ की मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं है। इस बारे में इसी हाउस में मुख्य मंत्री जी ने यह फरमाया भी है कि गेहूँ की मूवमेंट पर सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है लेकिन इन्होंने डी०सीज० और एस०पीज० की मीटिंग बुलाई और हरेक जिले का एक लख्य मुकर्र कर दिया कि आपने

इतना प्रोक्योरमेंट करना है। अफसरान ने क्या किया। मैं सोनीपत हल्के का हूँ मुझे वहाँ का पता है बहादुरगढ़ और रोहतक का तो आपको भी इभम होगा उन्होंने सारे बौर्डर्ज को सील कर दिया। किसानों का कोई अनाज नजफगढ़ या दिल्ली तक भी जाने नहीं दिया। वहाँ पर किसान अपना अनाज का भाव 130 रूपये की बजाये 160 से लेकर 190 रूपये तक ले सकते थे। मेरा कहना यह है कि सरकार अपने अधिकारियों को कोई एकस्ट्रा लीगल मैयर्ज लेने के लिये अधिकार न दे। इससे सरकार की बदनामी होती है। उकसा नजला बुर पड़ता है जैसे फ़ैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम कितना अच्छा प्रोग्राम था, लेकिन ओवर एन्थ्यूजिस्टिक अफसरान ने घक्के ाही की ओर उसका नतीजा हमारे सामने है। मैं मुख्य मंत्री जी से इसलिये यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वह स्वयं भी और अपने मंत्रियों द्वारा भी अइफसरान को इस बाम की इजाजत न दे कि वे लोग कोई एकस्ट्रा लीगल कार्यवाही करे। स्पीकर साहब, आज का किसान जगरुक हैं वह अपने अधिकारों के लिये लड़ाई करने के लिये तैयार है और आमदा है। कर्नाटक में, गुजारात में या महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि किसान किस तरह से मरने लग रहे हैं ओर गोलियां खाने लग रहे हैं। आप उनको दबाकर नहीं रख सकते। आज वे अपने अपने अधिकारों के लिये लड़ने के मूड में हैं। यह ठीक है कि प्राईम मिनिस्टर ने 117 रूपये से बढ़ाकर आज गेहूँ की प्रोक्योरमेंट प्राइस 130 रूपये कर दी है लेकिन आज के भा को देखते हुए जबकि सब चीजों के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं, किसान उससे असंतुष्ट हैं। मैं सरकार से

अनुरोध करूंगा कि ट्रैक्टर की कीमत, इनसैक्टीसाईडज की कीमत या खाद की कीमत या दूसरी जितनी भी चीजें उसको प्रयोग करनी पड़ती है, अगर इनकी कीमत का हिसाब लगाये तो पिछले साल गेहूं की कीमत 171-172 से कम नहीं होनी चाहिये थी। मैं यह चाहता हूं कि अगले साले के लिये सरीकार इस चीज को ध्यान में रखते हुए किसान को उसकी उपज को उचित ओर मुनासिब कीमत दिलवाये। इन भावों के साथ मैं आपका भुक्रिया अदा करता हूं। (घंटी) जो बाते मजेदार थी, वह तो आपने कहने नहीं दी, वह चलो फिर कह लूंगा। धन्यवाद।

चौधरी कर्म सिंह (टोहाना): स्पीकर महोदय, 1982-83 के बजट पर मैं भी कुछ बाते कहना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आर्थिक स्थिति इस वक्त हरियाणा प्रदेश की इतनी बिगड़ी हुई है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस समय कुछ लोग ऐसे हैं जो पूंजीपति हैं और ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं और ज्यादातर लोग जो गरीब हैं, वे और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। हरियाणा में अब लोग ज्यादातर 1-2-3-4-5 एकड़ जमीन तक के मालिक रह गये हैं। उनकी हालत इतनी कमजोर है जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता।

अब मैं रावी ब्यास के पानी के बारे में कुछ जिक्र करना चाहूंगा। मेरे से पहले मेरे दूसरे भाइयों ने इस पर बहुत कुछ चर्चा की है। रावी और ब्यास के पानी के बंटवारे के सिलसिले में अखबारों में जो खबर 1-2-1982 और 2-2-1982 को छपी, उसमें

जो फोटो हम देखते हैं, उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, पीछे खड़े हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने हरियाणा के लिये पानी लेने के लिये कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली है। चौधरी बंसी लाल के टाईम पर जितना पानी हरियाणा को देने का फैसला हुआ था अगर उससे कुछ ज्यादा पानी हरियाणा के हिस्से में ले आते हैं, तब तो हम यह मानते कि उन्होंने हरियाणा के हित में कात किया है। इससे यह पता चलता है कि इन्होंने ज्यादा पानी लेने के बारे में ज्यादा काम न करके हरियाणा के साथ बेइंसाफी की है। मैं इस बारे में और ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं करूंगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हफ्ते साल जब ओले पड़े थे तो गवर्नमेंट ने ग्रांट देने की बात कही थी। लेकिन ग्रांट में से गवर्नमेंट के कर्जे के पैसे काट लिये गये हैं और दूसरी बात यह कि यह ग्रांट भी टाईम पर नहीं दी गयी। अगर यह ग्रांट फसल के टाईम पर आ जाती तो उस वक्त गेहूँ जिसका भाव 130 रुपये क्विंटल ओर चारे का भाव 5 रुपये टन था, वे उससे अपने खाने के लिये गेहूँ ओर पशुओं के लिये ज्यादा चारा खरीद लेते। उस वक्त उनको सस्ते ढंग पर चीजें मिल सकती थी। आज जबकि दोबारा ओले पड़ गये हैं, बेचारा किसान कैसे उस नुकसान को पूरा कर सकेगा। स्पीकर साहब, अब मैं बिजली की तरफ अपना ध्यान दिलाना चाहता हूँ। किसी भायर ने कहा भी है—

आता है याद मुझको वह गुजरा हुआ जमाना

चौधरी भजन लाल बहुत सारी बातें कहते हैं लेकिन इनमें मुझको सब कुछ गलत ही नजर आता है। जब चौधरी देवी लाल की सरकार थी तो किसान को बाईस घंटे बिजली मिलती थी और अब सिर्फ दो दिन के बाद पांच घंटे के लिये बिजली मिलती है। हालात यह हैं कि खाना खाने और बच्चों की पढ़ाई के वक्त भी बिजली नहीं आती। हमारे बच्चे बिजली न होने के कारण पढ़ भी नहीं सकते। नाम मात्र की बिजली दी जा रही है। स्पीकर साहब, बिजली बोर्ड के अंदर इतना घोटाला है जिसका कोई हिसाब नहीं। जब राजीव गांधी आदमपुर आए थे तो टोहाना का पी० डब्ल्यू० डी० का एस० डी० ओ० बीस हजार रुपये के फूल आदमपुर ले गया था। स्पीकर साहब, उसने यह बीस हजार रुपया अपनी जेब से तो देना नहीं है। वह तो लोगों से लूटेगा।

स्पीकर साहब, बुढ़ापे की जो पैं न है वह उन बुढ़े आदमियों को मिलनी चाहिए जिनको एक एकड़ आधा एकड़ या दो एकड़ जमीन है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आधा एकड़ से लेकर दो एकड़ जमीन वालों को पैं न मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को काफी तादाद है। लोगों का तभी भला हो सकता है जब इस कैटेगरी के लोगों को पैं न दी जाएगी। स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल जी के जमाने में कोआप्रोटिव बैंक कस सूद चौदह परसेंट से घटाकर ग्यारह परसेंट कर दिया गया था लेकिन इस सरकारने फिर उसको बारह परसेंट कर दिया है। कोआप्रोटिव बैंक से ज्यादातर लोग वे कर्जा लेते हैं जो गरीब हैं।

ऐसा करके उन गरीब लोगो का गला काटा गया है। स्पीकर साहब किसान लोगो को जो खाद दी जला रही है वह बहुत ही घटिया किस्म की है ओर उसका वजन भी बहुत कम होता है मैंने पिछले सै। न मे भी इस बारे मे कहा था किसान को जो खाद दिया जा रहा है वह ठीक नहीं है यहां पर कोफेड का महकमा है मैं तो इस महकमे को कनफेड का महकमा कहता हूं। इस महकमे के अंडर कंज्यूमर स्टोर्ज आते है और इनमे दो लाख रूपये का घोटाला है। स्पीकर साहब, यह तो ऐसी ऐजेन्सी है जिसमे फायदा होना चाहिए था लेकिन बजाए प्रोफिट होने के, घाटा हो रहा है। स्पीकर साहब, मैं पंचायत डिपार्टमेंट के बारे मे भी कहना चाहता हूं। यह बहुत इम्पोर्टेंट महमा है। इसके लिये केवल नब्बे लाख रूपया रखा गया है। नब्बे लाख रूपया तो कुछ भी नहीं होता। अब मैं उद्योग के बारे मे कहना चाहता हूं। सरकार कहती है कि हमने इतने हजार औद्योगिक इकाईया एक साल मे नईग खोली है और अगले साल इतनी इकाईयां ओर खेलेंग लेकिन सरकार यह नहीं देखती कि कितनी इकाईयां खत्म हो रही है। कितनी इकाईयां रजिस्टर हो जाती हे वही गिनती इसके पास रहती है। इस सरकार ने जुहार और खाती जैसे लोगों को भी अपने यहां रजिस्टर कर रखा है और उनको औद्योगिक इकाईयों के तौर पर गिना जा रहा है।

अब मैं परिवहन के बारे मे कहना चाहता हूं। बस अड्डों पर जो दुकानो की नीलामी होती है, उन दुकानो पर लोगो को बहुत बंदा और महंगा माल दिया जाता है। इसकी तरफ

सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्पीकर साहब, रोडवेज को जो स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ती है उसके लिये सरकारी दुकानी होनी चाहिए। इससे दो फायदे होंगे एक तो चीज अच्छी मिलेगी और कम कीमत पर मिलेगी और दूसरे प्राइवेट आदमी का काम खत्म हो जायेगा।

स्पीकर साहब, सुरज कुंड पर राज हंस मोटल बनाया जा रहा है और इस पर पचास लाख रूपया खर्च किया जा रहा है अगर इतना पैसा किसी कालिज में इंजिनियरिंग या साईंस की तरक्की के लिये खर्च किया जाये तो बच्चों का बहुत ज्यादा फायदा हो सता है और देहात के लड़कों और लड़कियों का बहुत भला हो सकता है। स्पीकर साहब, इस समय प्राइवेट मिलिजिज को 95 परसेंट ग्रांट सरकार देती है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सौ परसेंट ग्रांट सरकार इन प्राइवेट कालिजिज को दे तो अच्छा रहे। स्पीकरसाहब, मेरे हल्के में 22-23 तारीख की पंद्रह बीस गांवों में ओलावृष्टि से बहुत दुकसान हुआ है असरकार के वहां पर लोग को जल्दी से जल्दी मुआवजा देना चाहिए। स्पीकरसाहब मेरे हल्के टोहाना में बीस बिस्तर का सिविज हस्पताल बना हुआ है। आबादी के लिहाज से यह बहुत छोटा अस्पताल है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उसको पचास बिस्तर का अस्पताल बना दिया जाये। स्पीकरसाहब 25-2-82 को तलवंडी और हिसार के बीच में एक सपैन गांव है वहां पर एक ऐक्सीडेंट हो गया था और उसमें छः आदमी जो बैकवर्ड क्लासिज से संबंध रखते थे, मारे

गये। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उनको पूरा मुआवजा दिया जाये। वे बहुत ही गरीब लोग है और उनके बच्चे अनाथ हो गये है। स्पीकर साहब, मेरे हल्के मे चार वाटर वर्क्स बंद कर दिया। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उन वाटर वर्क्स पर काम भुरू किया जाये।

श्री रघुनाथ गोयल (कैथल): स्पीकर सहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, 1982-83 का वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पे किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरी कांस्टीचुएँसी के प्रति जो इस सरकार का सौतेला व्यवहार है, स्पीकर सहाब, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब हमारे मुख्यमंत्री ने दल नहीं बदला था और वे जनतापाटी में थे उस समय तीस हजार लोगों के बीच इन्होंने ऐलान किया था कि मैं कैथल को एक अप्रैल को जिला बनाऊंगा। उस वक्त इन्होंने इस काम को करने के लिये पूरा जोर लगाया। उसके बाद वहां के वकील और प्रोफेसर्ज और दूसरे लोग भी इनसे मिले, उनसे भी इन्होंने बार बार वायदा किया कि कैथल को एक अप्रैल को जिला अनाउंस करूंगा लेकिन कैथल को आज तक जिला घोशित नहीं किया गया। स्पीकर साहब, हमारे यहां पचास बैड का एक छोटा या अस्पताल है और इन्होंने यह वायदा भी किया था कि इसको भी सौ बैड का अस्पता बनाया जायेगा लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। सिवाए इनसके कि इन्होंने वायदा कर लिया कि

यह करूंगा और वह करूंगा लेकिन किया कुछ नहीं। मैं समझता हूँ कि यह बात अच्छी नहीं है।

स्पीकर साहब, दूसरी बात यह है कि मेरे हल्के में एक आर० के० कालेज और एक कालेज महिलाओं का इंदिरा के नाम से है। उस महिला कालेज की अध्यापिकाएं चण्डीगढ़ में सी० एस० साहब से मिलने के लिये आई थी उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब से यह कहा कि आठ दस महीनों से उन्हें तन्खाहें नहीं मिली हैं और न उनका जी०पी०एफ० का रूपया ही उनके हिसाब में जमा हुआ है। अध्यापिकाओं ने बताया कि हमारी तनखाहों को कालेज के चंदे के रूप में ले लिया गया है। स्पीकर साहब, कालेज के मैनेजमेंट की तरु से यह कितना अन्याय है और वे लोग दूसरे लोगों से महीनों में 500-500 और 1000-1000 रुपये लेकर के अपना घर का गुजारा चला रहे हैं और वे लोग कर्जई हो गये हैं। इसलिये स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सरकार से विनती करूंगा कि ऐसे कोलेजों को सरकार अपने अधिकार में ले ले जिन कोलेजों में लोगों को तन्खाहें देने के लिये भी फण्डज नहीं हैं ऐसे अध्यापकों को सरकारी खजाने से तन्खाहे मिलनी चाहिए। सरकार को इस तरफ खास तौर से ध्यान देना चाहिए।

इससे अगली बात मैं चीनी मिलों के बारे में कहना चाहता हूँ कि कैथल हल्के में एक भूगर मिल सरकार की तरफ से मंजूर हो चुकी है और लोगो द्वारा तीन लाख के भोयर भी खरीदे जा चुके हैं और इसके लिये 20 किल्ले जमीन सरकार

की रेलवे स्टेसन के पास पड़ी हुई है। लेकिन वहां भूगर मिल नहीं खोली जा रही है। इसलिये वहां पर भूगर मिल को खोलने का प्रबंध किया जाये और वह जीमन भी दिवाई जाये यह हमारे हल्के साथसौतेली मां वाला व्यवहार क्यों हो रहा है। इसलिये सरकार को इस तरफ ध्यान अवश्य देना चाहिए।

इसी तरह से कुरुक्षेत्र में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के बारे में जो 72 सीटें भरी गयी हैं उस बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। दो सालों से इन सीटों पर कोई आदमी वहां का नहीं लगाया गया है। इसी संबंध में एम0डी0 साहब को दो-तीन बार धमकियां भी दी गयी हैं कि हम इस बैंक को तोड़ देंगे और वहां पर लोगों को भर्ती करने के लिये चीफ मिनिस्टर और ठाकुर बीर सिंह जी की तरफ से लिस्टे भी गयी है कि इन इन आदमियों को लगाया जाये और उसी के आधार पर वहां पर आदमियों को रखा गया है। अब तक तो आदमी वहां पर लगे हुए हैं, वे या तो चीफ मिनिस्टर के हैं या फिर ठाकुर बीर सिंह के आदमी हैं और दूसरे सभी जिलों में इस भर्ती से महरूम रखा गया है। इसलिये मैं आपकी मारफत सरकार को यह कहूंगा कि इस तरह का अन्याय बंद करें और सभी जिलों के साथ एक सा व्यवहार करें।

इससे अगली बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि मेरे से पहले मेरे मामा पोहलू साहब भी इस मामले पर काफी कुछ कह चुके हैं कि कैथल के अंदर जो थाना है, उसकी हालात बड़ा खस्ता है। वह गिरा हुआ है। जब जैन साहब वित्त मंत्री थे, तो

मैने उनको वहां पर ले जा करके दिखाया था। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वहां की थाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये सरकार इस तरफ ध्यान दे। जो तहसीलों के आफिस वगैरह है उनकी हालत भी बहुत खराब है। इस तरफ सरकार को खास तवज्जो देनी चाहिए।

इससे आगे अध्यक्ष महोदयखमें हवालात के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि वहां जेल बनाने के लिये मंजूरी आ चुकी है और इसके लिये वहां पर 20 किल्ले जमीन भी एक्वायर हो चुकी है, फिर पता नहीं कि सरकार देरी किस बात की कर रही है। वहां पर एक टूटी फूटी हवालात है उसमें दो टूटी हुई कोठरियां हैं, उसके अंदर 50-50 आदमी एट ए टाइम रहते हैं। आप ही स्पीकर साहब, अंदाजा लगाए कि वे लोग वहीं पर रहते हैं, टट्टी पै गाब भी वहीं पर जाते हैं, किसनी बुरी हालत है उन लोगों की। आखिर वे भी स्पीकर साहब, हमारे जैसे इंसान हैं आप ही सोचिए कि इस तरह से जब उनको रखा जा रहा है जो उनके साथ कितनी ज्यादाती हो रही है। उनके कपड़ों में जूएं तक पड़ जाती हैं और उनको इधर उधर घूमने को भी कोई जगह नहीं है, बस उन्ही दो टूटी फूटी कोठरियों में वे लोग बंद रहते हैं। यह हालत भी मैंने वित्त मंत्री महोदय को दिखायी थी इसलिये आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस ओर जल्दी से जल्दी ध्यान दे ताकि वहां पर जेल की व्यवस्था को सुधारा जा सके।

इसके साथ साथ स्पीकर साहब, मैं अपने इलाके के बारे में एक दो बातें और कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि मेरे इलाके में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ के गांवों का पानी बहुत खराब है जोकि पीने के काबिल नहीं है। इस बारे में स्कीमें भी मंजूर हो चुकी है पर पता नहीं सरकार की तरफ से पुन्डरी, पाई ओर कैथल इन जगहों के साथ सौतेजी मां वाला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां के एम0एल0एज0 अपोजी इन के है इसलिये ऐसा किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि यहां की जनता तो हरियाणा के है निवासी माने जाते है ओर इनके अपने आदमी भी इन इलाकों में बसते है। इसलिये मेरी आपके द्वारा सरकार से दरखास्त है कि इन इलाकों में पीने के पानी की व्यवस्था को सुधारा जाये और जो स्कीमें इन इलाकों में मंजूर हो चुकी है, उनको जल्दी ही कार्यान्वित किया जाये।

दूसरी बात मैं टीचज़ के बारे में कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे है जो ओवर ऐज हो रहे है, पहले उन लोगों को भर्ती किया जाना चाहिए ताकि वे लोग पहले ऐडजस्ट हो जाये।

इसके साथ साथ मैं रावी ब्यास के पासनी के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ कि कैथल के अंदर एस0डी0एम0, डी0सी साहब की कोठियों पर खु़ी मनाने के लिये बिजली लगाई गई है और रोानी की गई है। रावी ब्यास का पानी हरियाणा को मिल गया है। स्पीकर साहब अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं है,

ऐसे ही लोगो को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और उनके आंखो मे धूल झांकने वाली बात की जा रही है और यूं ही इस तरह की लाईटें लगाकर के लोगो का, गरीब किसानों का पैसा बरबार किया जा रहा है। इसलिये सरकार को ऐसी फिजूलखर्ची पर रोक लगानी चाहिए।

इससे आगे स्पीकर साहब, मैं अस्पतालों की हालत के बारे मे कुछ कहना चाहता हूं कि जो अस्पताल है, उनमे कोइ दवाईयां नही हमलती। मैंने पिछली बार भी हैल्थ मिनिस्टर साहब से इस बारे मे कहा था कि इस तरफ ध्यान दिया जाये। साथ ही यह भी बताया था कि जो जो डाक्टर इन अस्पतालों मे लगाये गये है वे काम नही करते तो हैल्थ मिनिस्टर सहाब ने कहा कि मैंने तो ऐसे लोगो को वहां से निकाल दिया था, पता नही चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको फिर क्यों रख लिया।

स्पीकर साहब, मैं अंत मे कैथल की म्यूनिसिपल कमेटी के बारे मे कहकर अपना स्थान लूंगा। स्पीकर साहब, वहां की कमेटी फर्स्ट क्लास कमेटी है लेकिन उस की हालत सुधारने के बारे मे सरकार कोइ ध्यान नही दे रही है। जनता पार्टी के राज्य मे म्यूनिसिपल कमेटियों के इलैक्ट्रान करवाने का प्रस्ताव आया था लेकिन इस सरकारने इन सारे प्रस्तावों को आते ही रद्द कर दिया और अब यह सरकार वहां पर चुनाव करवाना नही चाहती। यह भी एक प्रकार से ज्यादाती है। इस और ध्यान देने का यत्न किया जाना चाहिए। इसलिये स्पीकर साहब, मैं इन कुछ बातों के साथ

आपका धन्यवाद करता हुआ, और इस बजट की निन्दा करता हूँ, अपना स्थान लेता हूँ।

कामरेड भांकर लाल: स्पीकर साहब, पार्टी के लीडर की तरफ से बोलने के लिये मेरा नाम आपके दिया गया है। इसलिये मुझे भी बोलने का मौका दिया जाये। स्पीकर साहब, मैंने केवल पांच मिनट ही लेने है।

श्री अध्यक्ष: कामरेड भांकर लाल जी, आप बैठिये आपको बोलने का समय दिया जायेगा। मैंबर साहेबान जो सदस्य बोल चुके है, मैं उन से दरखास्त करूंगा कि वे अपना नाम न भिजवाए।

कामरेड भांकर लाल: स्पीकर साहब, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, केवल पांच मिनट ही लूंगा।

श्री अध्यक्ष: भांकर लाल जी, आप बैठिये। मैंबर साहेबान अब तक कांग्रेस की तरफ से 15 साहेबान और लोकदल के 10 भारतीय जनता पार्टी के 9 और जनता पार्टी के 3 साहेबान बोल चुके है और कामरेड भांकर लाल जी दो दफा बोल चुके है। पाहलू साहब भी बोलच चुके है इसलिये मैं इन साहेबान से दरखास्त रूंगा कि जो सहोबान बोल चुके है, वे अपना नाम दोबारा न भिजवाएं।

कामरेड भांकर लाल: स्पीकर साहब, मेरी रिकवैस्ट है कि.....(गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भांकर लाल जी, आप कृपा करके बैठ जाइये, बीच में न बोलिये। जिन सदस्यों को यहां पर बोलने का मौका नहीं मिला है, उनको बोलने के लिये मौका दिया जाना चाहिए। अब श्री राजेन्द्र सिंह बोलेंगे।

चौधरी राजेन्द्र सिंह (बल्लभगढ़): अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1982-83 के बजट पर चर्चा चल रही है। और सदन के सभी राजनैतिक दलों के माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं। इस बजट की क्या विशेषता है, क्यों यह बजट इतना महत्वपूर्ण है इसके लिये हमें हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने 14 जनवरी, 1982 को जो महत्वपूर्ण सारे देश को दिया है उसको अगर हम थोड़ा समझ कर चले तो मैं विवास के साथ कह सकता हूँ कि इस बजट का हम अच्छी तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस नये प्रोग्राम में हमारी प्रधान मंत्री जी ने सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो बीस सूत्री प्रोग्राम दिया है जिसमें सभी देशवासियों के लिये विशेष कर कमजोर वर्ग के लिये, गरीबों के लिये समस्त ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति के लिये वर्णन है। इससे सभी देशवासियों को समान अवसर प्राप्त होंगे। इन सब बातों को आधार बना कर जो बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने हमारे सामने रखा है, उससे हम यह कह सकते हैं कि यह बजट बहुत प्रगतिशील बजट है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) यह बजट देश की उन्नति के लिये है, गरीबों की उन्नति और

हरजनो की उन्नति के लिये है। इसी बात के लिये इस बजट की विशेषता कही जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष में के माननीय सदस्यों ने जो इस बजट के अंदर विशेषताएं हैं या जिस दृष्टि से हमारा बजट महत्वपूर्ण है, उन सब बातों को इग्नोर किया है और सरकार पर निराधार लांछन लगाए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने सभी को कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया है उनका कहना है कि जमीन के चप्पे चप्पे से, कारखाने के हर मीन से और हर मजदूर या रिप्ली से हमें पूरा लाभ उठाना है इसलिये वर्ष 1982 को उत्पादक वर्ष घोषित किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय मैं एक बात सदन में आवाज कहूंगा कि यह पहला बजट है जिसमें वित्त मंत्री देहात के लोगों को, गरीब लोगों को और हरिजन लोगों को हमारे हरियाणा के खजाने की चाबी दी है। देहात के सभी लोगों को और गरीब भाइयों को वित्त मंत्री जी ने यह कहा है कि भाई आपका ही यह खजाना है, यह लीजिये हरियाणा के खजाने की चाबी। सारा पैसे पूरी तरह से स्टेट की डिवैल्पमेंट पर खर्च होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय हमारी हरियाणा सरकारने चौधरी भजन लाल जी के नेतृत्व में जो बार बार इनका इसी बात पर बल है कि सदस्य बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं है। बार बार उनका इसी बात पर बल है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूँ कि चौधरी भजन लाल के नेतृत्व में सारे हरियाणा में, सभी वर्गों विशेषकर देहातों के अंदर जो प्रगति हुई है वह वह बहुत ही प्रशंसनीय है। हम अपनी सरकार की जितनी प्रशंसा करें उतनी

थोड़ी है। उपाध्यक्ष महोदय एक और बात में कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के इतिहास में 31 दिसम्बर, 1981 का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन हरियाणा प्रांत को एक नयाजीवन मिला है। पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच एस0वाई0एल0 के पानी का झगड़ा जो चला हुआ था वह इसी दिन हमारी प्रधान मंत्री महोदया जी के आर्ीवाद से हल हुआ है और जीनो प्रांतों की सरकारों ने समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। उसस समझौते के परिणाम स्वरूप हमारे हरियाणा प्रांत को जो एस0वाई0एल0 कापानी मिलना चाहिए था, वह भीघ ही मिलेगा। इसपानी के मिलने के लिये भी समय निश्चित कर दिया है कि दो साल के अंदर अंदर यह पानी हरियाणा के किसानों के खेतों को उपलब्ध होगा। इसकि लिये हम अपनी प्रधान मंत्री जी का जितना भी धन्यवाद करे, वह थोड़ा है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, इस समझौते के लिये हम अपने मुख्य मंत्री जी की प्रार्था किए बगैर भी नहीं रह सकते। हरियाणा प्रांत के वासी कब से इस पानी की तरफ नजर लगाए बैठे थे। अब हमारी सरकारने चौधरी भजन लाल जी के नेतृत्व में भारी प्रयत्न करके हमें यह पानी दिलाया है, यह हरियाणा प्रांत के लिये बहुत फख की बात है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय हमारी सरकार ने किसानों के खालों को पक्के करने का भी एक विशेष प्रोग्राम चलाया हुआ है जिससे हमारे प्रांत के किसानों को बड़ा भारी लाभ पहुंचा है। जैसाकि सभी जानते हैं कि हमारे प्रांत में सिंचाई के लिये पानी कम है और इन खालों में नहरों को पक्का करने के लिये इस बजट में वित्त मंत्री जी ने 25

करोड़ रूपये से भी ज्यादा पैसे रखे है। किसानों के खाल पक्के करने का जो काम है यह बहुत ही सराहनीय काम है। जो पैसा इस वर्ष रखा गया है इससे सभी बचे हुए खाल पक्के हो जायेंगे और हमारे प्रांत की एक भी पानी की बूंद बेकार नहीं जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी प्रधान मंत्री जी के बीस सूत्री प्रोग्राम का एक यह भी सूत्र है कि ज्यादा पेड़ लगाएं जाएं और इस प्रोग्राम पर बल दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने हरियाणा प्रांत में पेड़ लगाने के लिये 33 करोड़ रूपये की भारी रकम रखी है इससे हमारे प्रांत में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी सरकार ने हरियाणा प्रांत में एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। हरियाणा प्रांत में सबसे गरीब और पिछड़ा हुआ इलाका मेवाल का इलाका था और सबसे गरीब आदमी मेवात में थे। यह पहली सरकार है और चौधरी भजन लाल जी पहले मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने मेवात के गरीब लोगों की तरफ ध्यान दिया है और उनकी गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने के लिये मेवात डिवैल्पमेंट बोर्ड का गठन किया है। उपाध्यक्ष महोदय, आज सभी बड़े फख के साथ यह कह सकते हैं कि मेवाल क्षेत्र के अंदर जो डिवैल्पमेंट के काम हो रहे हैं वह हमारी सरकार के लिये बहुत प्रसन्नता का विषय है। उपाध्यक्ष महोदय, आज सभी बड़े फख के साथ यह कह सकते हैं कि मेवाल क्षेत्र के अंदर जो डिवैल्पमेंट के काम हो रहे हैं वह हमारी सरकार के लिये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। उपाध्यक्ष

महोदय, मेवात क्षेत्र के लोगों की अनेकों अच्छी वि. शेषताएं हैं। उनमें सबसे अच्छी विशेषता यह है कि हमारे मेवात भाई मेहनत करने में सारे प्रांत के लोगों से आगे हैं। इस बात के लिये हम लोग उन पर फख्र कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा मेहनत करके जो आदमी रोटी कमाता है तो वह मेवात का रहने वाला ही कमाता है। आपको प्रांत के अंदर जितने भी डिवलपमेंट के काम होते हुए नजर आयेंगे वहां पर आपको मेवात के निवासी ही काम करते हुए नजर आयेंगे। वहां पर आपको मेवात के निवासी ही काम करते हुए नजर आयेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में से करोड़ों रूपया मेवात डिवलपमेंट बोर्ड की तरफ से इस पिछड़े हुए क्षेत्र के लिये खर्च होगा। यह हमारे लिये बहुत ही फख्र की बात है। मेवात के निवासी और विशेषकर फरीदाबाद और गुड़गांव जिले के विधायक वित्त मंत्री जी के और सरकार के बहुत अभारी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी बताया था कि एस0वाई0एल0 का उद्घाटन 8 अप्रैल को हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी करेंगी और दो साल के अंदर अंदर हमें एस0वाई0एल0 नहर का पानी मिल जायेगा। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि एस0वाई0एल0 का हरियाणा प्रांत को जो पानी मिलेगा वह हरियाणा प्रांत की सिंचाई की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के हर कोने में जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे फरीदाबाद और गुड़गांव दोनों जिलों में सिंचाई के लिये पूरी मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जहां सारी

स्टेट का इरीगे इन प्वायंट आफ व्यूज से पानी बनता है उसी हिसाब से हमारे दोनो जिले फरीदाबाद और गुड़गांव की सिंचाई के पानी की आवकता को मदेनजर रखते हुए सारी स्टेट की प्लान बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे फरीदाबाद जिले का गठन गुड़गांव जिले से अलग करके लिया गया है फरीदाबाद जिला बनने के बाद वहां पर कुछ ऐसी आवकताएं हैं और कुछ ऐसी जरूरी डिवैल्पमेंट के काम बाकी हैं जिनके न होने की वजह से फरीदाबाद जिले के लोगों को बड़ा भारी सफर करना पड़ रहा है इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा और सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि फरीदाबाद की सैलन कोर्ट में जितने भी जुडिगियल औफिसर्स बैठते हैं उनके लिये प्रायर्टी बेसिज पर जुडिगियल कम्प्लैक्स बनना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद के 15 सैक्टर में जहां हमारी डिसिट्रिक्ट कोर्ट बनी हुई है वह सैक्टर मार्किट की जगह के अंदर कोई रिफिट कर दी गई है उपाध्यक्ष महोदय, हमने वहां पर देखा है कि छोटे छोटे कमरों के अंदर अदालत की गरीमा पूरी तरह से नहीं रह पाती है और उसके अंदर वकील इस तरह से भरी जाते हैं कि वहां पर अदालत की बजाये बाजार का सा सीन नजर आता है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि फरीदाबाद की कोर्ट के लिये जुडिगियल कम्प्लैक्स प्रायर्टी बेसिज पर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, इस के साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि फरीदाबाद जिले के अंदर कोई भी डिस्ट्रिक्ट लैवल का स्टेडियम नहीं है और न ही कोई डिस्ट्रिक्ट लैवल का होस्पिटल है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि फरीदाबाद जिले में डिस्ट्रिक्ट लैवल पर स्टेडियम और होस्पिटल बनाए जाये। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ हमारे फरीदाबाद जिले का बहुत सा क्षेत्र जमुना नदी के साथ साथ लगता है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र लगता है। उत्तर प्रदेश सरकार दिन रात काम करके अपनी साइड में जमुना नदी के किनारे के साथ साथ एक बड़ा भारी चौड़ा बांध बांध कर उस पर 35 फुट चौड़ी सड़क बना रही है जिसके कारण हमारे फरीदाबाद क्षेत्र के ग्रामीण लोगों को बहुत भारी हानि हुई है। जब बारिश के दिनों में जमुना नदी में बाढ़ आती है तो वह पानी उत्तर प्रदेश की तरफ न फैल कर हमारे हरियाणा के गांवों की तरफ आ जाती है और उससे बहुत नुकसान होता है। हरियाणा के गांवों की सैकड़ों और हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि बाढ़ के कारण कट कर जमुना में चली जाती है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और इस तरफ कोई ठोस कदम उठाये। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि उत्तरी भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स फरीदाबाद में है और वहां पर बहुत तेजी के साथ उद्योग लगाए जा रहे हैं। चूंकि फरीदाबाद बाहर औद्योगिक नगरी है इसलिये वहां पर उद्योग और औद्योगिक कालोनी बसाने के लिये जमीन एक्वायर करने की आवश्यकता है

और जमीन एक्वायर करने के लिये झाड़सैंतली बगैरा गांवो को नोटिस दिए हुए है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां पर किसानो की जमीन बहुत उपजाऊ है इसलिये उन गांवों की जमीन एक्वायर कर ली जाये जोकि पहाड़ी भूमि है और उपजाऊ भी नहीं है। औद्योगिक कालोनी बसाने के लिये पहाड़ी क्षेत्र के गांवों की जमीन एक्वायर कर ली जाये। उपाध्यक्ष महोदय, सारे देा के लोग जानते है कि देा मे देा हरियाणा जहां दूध दही का खानां सारे देा के दूसरे प्रांतों के लोग जब किसी हरियाणवी जवान को देखते है तो यह परजम्पान करते हे कि हरियाणा के लोग भारीरिक दृष्टि से बहुत बहादुर है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे हरियाणवी लोगो की बहादुरी की परम्परा प्राचीन समय से रही है क्योंकि लोगो को खाने के लिये घी दूध बहुत ज्यादा मात्रा मे मिलता है। लेकिन देखने मे यह आया है कि हमारे प्रांत के अंदर गरीब आदमी अपने घर मे गाय या भैंस नहीं रख जायेगे क्योंकि हरियाणा मे चारे की बहुत बड़ी समस्या है। चारे की समस्या इसलिये है क्योंकि जो कम्बाइंड हार वैस्टर है वह खड़ी फसल के अंदर चलता है जिसे कारण अनाज तो किसानो को मिल जाता है लेकिन चारा बहुत मात्रा मे वेस्ट जाता है। हमारे प्रांत हरियाणा के अंदर किसी भी कीमत पर चारा उपलब्ध नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा मे सैंकड़ों फैंक्ट्रियां गत्तों और पेपर्ज की लगी हुई है जिनका रा मैटीरियल भूसा होता है लेकिन हमारे यहां पर भूसे की बहुत ही बड़ी समस्या है। मैं आपके माध्यम से अपने वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि हमारी सराकार को

फसल की कटाई के लिये हाथ से ओर थ्रेसरों से काटने का प्रबंध करना चाहिए। कम्बाईन हारवेस्टर से फसले नहीं काटनी चाहिए। क्योंकि कम्बाईन हारवेस्टर से फसल काटने से काफी भूसा बरबाद हो जाता है। यदि हाथ से फसल काटने का प्रबंध होगा तो भूसा भी अधिक होगा और गरीब लोगों को भी सुविधा होगी। ऐसा होने से हमारे गरीब से गरीब लोग भी दूध वाले पशु पाल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, नैतिक शिक्षा के बारे में भी विपक्ष के साथियों ने जोर दिया है कि हमारे यहां पर नैतिक शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। इस विषय पर सभी साथियों ने अच्छे अच्छे विचार रखे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, बड़ी ही सच्चाई की बात है कि जब तक हम आर्थिक सामाजिक समानता को दूर करने के लिये शिक्षक वर्ग की तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक इस दिशा में आगे बढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। डिप्टी स्पीकर साहब आज नौकरियों के अंदर जितनी भी सिलैबस बन रही है उनके अंदर देहात के बच्चे रह जाते हैं। आपको भी मालूम है कि आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 और एच0सी0एस0 आदि परिक्षाओं में देहात के बहुत ही कम मात्रा में बच्चे आगे आ पाते हैं। इसका एक ही कारण है कि देहात के बच्चों को ठीक प्रकार से शिक्षा नहीं मिल पाती, उनको लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती जिसकी वजह से गांवों के बच्चों नौकरियां प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इस संबंध में सरकार से मेरी प्रार्थना है कि हमारे स्कूल और कॉलेजों के अंदर जो अध्यापक और लैक्चरर हैं, उनकी

जायज मांगें मान कर उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएं ताकि वे मन लगा कर बच्चों को पढ़ा सकें। इसी के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देहात के जो शिक्षक हैं उनको रूरल अलाउंस दिया जाये। जब तक हमारे प्रांत का निर्माता पूरा तरह से सुशिक्षित नहीं होगा उस समय तक नैतिक शिक्षा नहीं आ सकती। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे प्रांत का जो निर्माता है उसको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाये ताकि उनको मनोबल ऊंचा हो और वे दिल लगा कर बच्चों को शिक्षा दे सकें। ऐसा होने पर हमारे देहात के बच्चे भी कम्पीटीशन में आगे आयेगे और उन्हें नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही खुशी की बात है कि चौधरी भजन लाल जी ने जो हमारे जिले की पुरानी मांगें थी वे मान ली हैं। (गोर)

श्री उपध्यक्ष: चौधरी राजेन्द्र सिंह जी आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है। अब आप वाइंड अप कीजिये। (गोर व व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। आप टाईम को चैक कर ले। अभी तक हमारे लोकदल के केवल 10 सदस्य बोले हैं और भारतीय जनता पार्टी के 9 सदस्य बोल चुके हैं। आप इनको ज्यादा समय दे रहे हैं।

चौधरी संत कंवर: डिप्टी स्पीकर साहब, लोक दल के बहुत कम मैनबर बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण करे। मैंने इनको वाईड अप करने के लिये कह दिया है।

चौधरी राजेन्द्र सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, हमारे फरीदाबाद जिले के किसानों की काफी समय से एक मांग चली आ रही थी कि यहां पर एक भूगर मिल होनी चाहिए। अब सारे हरियाणा के अंदर 3 नई भूगर मिल और लगनी है। इन तीन मिलों में से एक भूगर मिल पलवल के अंदर लगाई जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि सदन के अंदर हमारे कुछ माननीय सदस्य ऐसी बात कर देते हैं जो हमारे सब के लिये बड़े भार्म की बात है। इस प्रकार की बातें विशेष कर श्री जगजीत सिंह पोहलू करते हैं। (गोर) वैसे देखा जाये तो ये हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के एक मात्र सदस्य है। (गोर)

वाक आउट

चौधरी संत कंवर: उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे और न ही हमें सुन रहे हैं, न ही हमें बोलने दे रहे हैं। आप लोकदल की पार्टी के साथ ठीक प्रकार का व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इसलिये मैं अपना विरोध प्रकट करते हुए वाक आउट करता हूं।

(इस समय चौधरी संत कंवर सदन से वाक आउट कर गये) (गोर)

वर्ष 1982-83 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी राजेन्द्र सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगो ने विधान सभा को एक राजनीतिक मंच सा बना कर रखा दिया है। यह ठीक है कि राजनीति के अंदर मे मतभेद होते है। हरेक पार्टी के अलग अलग विचार हुआकरते है लेकिन फिर भी इन लोगो को कन्स्ट्रैक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए। जो इन लोगो के अच्छे सुझाव है वे हम मानते भी है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पोहलू साहब की बात का संबंध हे मुझे तो कहते हुए भी भार्म आती है क्योंकि ये यहां पर रोज नए नए सीन क्रिएट करने लग जाते है। बड़े भार्म की बात है कि यहां पर ये लोग कभी कहते है कि यह सरकार जाट विरोधी है, कभी कहते है हरिजना विरोधी सरकार है। (गोर)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: मैं तो अब भी कह रहा हूं कि यह सरकार जाट विरोधी और हरिजन विरोधी सरकार है। (गोर)

चौधरी राजेन्द्र सिंह: क्या इन्होंने ही जाटों का ठेका लिया हुआ है? मैं तो जाट बिरादरी से संबंध नही रखता क्योंकि मैं तो स्वयं आर्यसमाजी हूं। इन लोगो को ऐसी बाते कहते हुए कुछ सोचना चाहिए। (गोर) पोहलू साहब हमारे यहां सदन मे एक * * * * * बने हुए है। (गोर एवं विघ्न) डिप्टी स्पीकर

साहब, मैं अंत में अपने वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

चौधरी टेक राम (मुन्डालखुर्द): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे बोलने का समय दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई दिनों से विपक्ष और पक्ष की ओर से बजट के ऊपर अपने अपने विचार प्रकट किये जा रहे हैं। मैं भी इस बजट का अपना विरोध प्रकट करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर के बारे में कहना चाहता हूँ। आपको भी मालूम है कि हमारे यहां पर 10-15 रारेज से लगातार ओले पड़ रहे हैं। जिस दिन 15 तरीख को हाउस भुरु हुआ था उस दिन भी ओलावृष्टि के संबंध में कई सदस्यों की ओर से काल अटैन्शन नोटिसिज आदि आये थे। चौधरी भजन लाल ने हाउस को आवासन भी दिलाया था कि उनको 400 रुपये प्रति एकड़ तक का मुआवजा दिया जायेगा। जिस दिन सी० एम० साहब ने आवासन दिया था उस के बाद भी 10 दफा ओले पड़ चुके हैं। इस संबंध में मेरी सरकार से अज्र है कि उनको 2000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाये। जब तक किसानों को 2000 रुपये तक का मुआवजा नहीं दिया जायेगा तब तक उनका कोई भला नहीं होगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, सी० एम० साहब की एक और बात देखने में आ रही है, ये रोजाना नए नए पत्थर रख रहे हैं। इन्होंने इतने पत्थर रख दिये हैं कि यदि चौधरी भजन लाल 30 साल तक

भी लगातार मुख्यमंत्री रहे तो भी इन द्वारा रखे गये पत्थरों का काम पूरा नहीं हो सकता। डिप्टी स्पीकर साहब, दो तीन रोज पहले सरकारी पक्ष के एक भाई ने बजट पर बोलते हुए जिक्र किया था कि यहां काफी गवर्नमेंट्स आईं। उन्होंने कहा कि यहां चौधरी बंसीलाल की सरकार आई, चौधरी देवी लाल की सरकार आई और चौधरी भजन लाल की सरकार भी आई। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि चौधरी बंसी लाल ने तो बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत भिवानी के अंदर घंटाघर से जो अनाउसमेंट की थी वह सबके सामने है और चौधरी भजन लाल यने 37 एम0एल0एज0 के साथ कुतुबमीनार के ऊपर से जो अनाउंसमेंट की है वह सारी दुनिया के सामने है और उन्हे यह पता है कि सबसे ज्यादा दल बदल करने वाली सरकार आज हरियाणा मे बैठी है। (विघ्न)

डिप्टी स्पीकर साहब, यह बजट एक स्टंट है। इलैक 11 न मे पैसा खर्च करने के लिये इस बजट मे 19 करोड़ रूपये का घाटा दिखाया गया है डिप्टी स्पीकर साहब, दो चार बाते इसके बारे मे यहां कहना चाहता हूँ कि नैतिकताके बारे मे साहब, दो चार बाते मैं इसके बारे मे यहां कहना चाहता हूँ। नैतिकता के बारे मे यहां सवाल आया । मेरे आदणीय मिनिस्टर गुप्ता साहब गुप्ता सहाब यहां बैठे है। इन्होंने अपनी लड़की की भाादी मे 8 लाख रूपये देने की अनाउसमेंट की है। (विघ्न)

स्थानीय प्र ासन मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी टेक राम जी

बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं । मेरे तो भाादी योग्य लड़की ही कोई नहीं है । इन्हें यह इल्जाम वापस लेना चाहिए ।

चौधरी टेक राम: आपने अपनी भतीजी की भाादी में अनाउस किया था ।

श्री मांगे राम गुप्ता: डिप्टी स्पीकर साहब, अगर मेरी भतीजी की भी कोई भाादी हुई हो तो भी मैं गुनाहगार हूँ । (विधन एवं भाोर) डिप्टी स्पीकर साहब, या तो ये इस बात का जवाब दे या माफी मांगे ।

श्री उपाध्यक्ष: इनके पास इनका कोई जवाब नहीं है ।

वित्त मंत्री (चौधरी खुर गीद अहमद): डिप्टी स्पीकर साहब, उनके रिमार्कस ऐक्सपंज करवा दिये जाये ।

श्री उपाध्यक्ष: ऐक्सपेक्शन की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मिनिस्टर साहब की तरफ से क्लीयरेंस आ गई है । (भाोर)

चौधरी उदय सिंह दलाल: * * * *

* * * * *

चौधरी संत कंवर: * * * *

* * * * *

श्री उपाध्यक्ष: कुछ रिकार्ड न किया जाये । (विधन) आप चैलेंजबाजी बाहर जाकर लीजिए ।

श्री मांगे राम गुप्ता: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। डिप्टी स्पीकर साहब, पहले तो चौधरी टेक राम ने ऐ इल्जाम मेरे ऊपर लगाया और उसके संबंध मे मैने हाउस के साने अपनी बात रखी की आज से दो साल पहले भी अगर मेरी लड़की की भाादी हुई हो तो मैं गुनाहगार हूं। उन्हें इसके लिये माफी मांगनी चाहिए। अब दलाल साहब ने सटटे के बारे मे बात कह दी। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, इस बारे मे तो मेरे खिलाफ हाई कोर्ट मे रिट हुई है। उन लोगों ने, जिनके पास इसकी मंजूरी है, हाई कोर्ट मे कहा है कि मंत्री पुलिस की मददसे हमारा काम बंद करवाना चाहता है लेकिन ये यहां इस तरह की बाते करते है । (गोर)

चौधरी उदय सिंह दलाल: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ यह बात कहता हूं। उनके पास लाईसेंस है या नही यह तो मुझे पता नही लेकिन इस बात का मुझे पता है कि 50 हजार रूपये महीने के वे इनको ओर इनके आदमियों को देते है। (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: दलाल साहब, यह आप लिख कर दे दीजिये।

चौधरी उदय सिंह दलाल: आप कोई इंक्वायरी बैठा दो। हम लिख कर भी दे देंगे।

श्री मांगे राम गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनका चैलेंज स्वीकार करता हूँ। आप कोई कमेटी बैठा दीजिये। अगर यह बात साबित हो जाये तो मैं इस्तीफा दे दूंगा वरना ये इस्तीफा दे दे।

चौधरी उदय सिंह दलाल: मैं स्वीकार करता हूँ। उस कमेटी के चेयरमैन डिप्टी स्पीकर साहब आप होंगे। दो आदमी आप अपने साथ और ले ले। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: दलाल साहब, आप बैठिये। (विघ्न)

चौधरी टेक राम: डिप्टी स्पीकर साहब, भिवानी के अंदर जितनी खाली जमीन थी जितने खाली प्लॉटस थे, उनको आज एक ही जाति के लोगों ने नाजायज तौर वर घेर लिया है। (विघ्न) वहां जो मंदिरों की जगह थी, तालाबों की जगह थी, उस सब जगह को घेर लिया गया है। चौधरी भजन लाल जी जब वहां गये थे तो इन्होंने वहा यह अनाउंस किया था कि वे प्लॉटस हरिजनों की बस्ती के लिये होंगे लेकिन एक मंत्री के आदमियों ने, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन प्लॉटस पर कब्जा कर लिया है। आज भिवानी में चारों तरफ ऐसे हालात हो रहे हैं। (विघ्न) 100 परसेंट में से 99 परसेंट एक ही जाति के आदमी हैं। एस0एस0एस0 बोर्ड में भी काफी घपला हुआ है। कोओपरेटिव बैंको में जो कुछ हुआ है उसकी ताईद तो दो तीन दिन पहले कांग्रेस के कुछेक भाइयों ने भी यहां की है। ऐजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया है कि प्राइवरी से मिडिल 210 और मिडिल से हाई 125 स्कूल

बनाए गए है। हायर सैकेंडरी कोई स्कूल मंजूर नहीं किया गया है। लेकिन मेरे हल्के मे न तो प्राईमरी स्कूल दिया गया है, न मिडिल स्कूल दिया गया है और न ही हाई स्कूल दिया गया है। मैं एजूके ान मिनिस्टर के नोटिस मे एक बात और लाना चाहता हूं। मुंढाल स्कूल के अंदर एक हैडमास्टर हैं उसकी बात इनके नोटिस मे भी आई हे, डी०सी० के नोटिस मे भी आई है लेकिन उस बारे मे कोई एक् ान नहीं लया गया। उस हैडमास्टर के खिलाफ स्कूल के बच्चों ने स्ट्राईक कर दी थी। रोजाना उसका काम था कि वह बच्चों से कहता कि जो मुझे भाराब की बोतल पे ा नहीं करेगा उसे मैं पढाऊंगा नहीं। उस हैडमास्टर कामें नाम नहीं लेना चाहता। लड़कों ने सात रोज तक स्ट्राईक की। डी०पी०आई० और डी०सी० साहब ने उसे तुड़वाया। भिवानी मे डी०सी० साहब की कोठी के सामने लड़कों ने धरना दिया। उन लड़कों ने लिख कर भी दिया कि अगर हैडमास्टर की ट्रांसफर न हुई तो हम वीरगति को प्राप्त हो जायेगी। एक लड़का उनमे पंडितों का था। वह स्कूल के अंदर इ तहार लगा कर आया। एक रोज वह हवालात मे भी रहा। वह लड़का मर गया यह लिख कर कि मेरा जो काम था वह मैंने कर दिया लेकिन इसके बावजूद भी उस हैडमास्टर की ट्रांसफर नहीं हुई। (विघ्न) ऐसी चीजे ऐजूके ान के महकमें मे नहीं होनी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं वाटर सप्लाई के बारे मे एक बात कहना चाहता हूं। मैं आपके द्वारा सरदार लछमन सिंह

जी से अर्ज करूंगा कि चौधरी देवी लाल जी के टाईम पर जो वाटर सप्लाई स्कीम मंजूर हुई थी, वह बंद पड़ी है। इसी प्रकार से बंसी लाल जी के टाईम पर जो स्कीम चालू की गई थी उनकी नालियों को भी आज तक साफ नहीं कराया गया। बापौड़ा, तिगड़ाना और मुंढाल में वाटर सप्लाई की स्कीम चालू है लेकिन उनकी नालियों को आज तक साफ नहीं करवाया। 52-52 गांवों की वाटर सप्लाई स्कीम है उनकी जो नहर की नालियां हैं। वे बिल्कुल साफ नहीं करवायीं। उन्हें जल्द से जल्दी साफ करवाया जाये।

कुछ मैं ट्रांसपोर्ट के विषय में भी अर्ज करना चाहता हूँ। 25 परसेंट ज्यादा टैक्स लगाया है। बसों में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। मुंढाल के एरिया में भिवानी से मुंढाल तक दो चार बसें और लगायीं जाये क्योंकि लोगों को काफी तकलीफ रहती है इन भावों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूँ।

श्री मूल चंद मंगला (पलवल): डिप्टी स्पीकर साहब, वित्त मंत्री महोदय ने जो सन् 1982-83 का बजट हाउस में पेश किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। यह बजट घाटे का, निराशाजनक, निकम्मा और बेबुनियाद है। यह संज्ञा में इस बजट को देना चाहता हूँ। साथ ही यह बजट किसान, मजदूर, हरिजन, साधारण व्यापारी, साधारण मुलाजिम या सरकारी मुलाजिम को कोई उत्साह या सुविधा देने वाला नहीं है। मैं यह कह सकता हूँ कि इसमें कजो आंकड़े पेश किये गये हैं वे थोड़े बहुत बढ़ा

चढ़ा कर पे 1 किये गये है जो आंकड़े बढ़ाये है उनसे पता चलता है कि आने वाले वर्ष में महंगाई होगी। इन आंकड़ों को देखने से यह भी पता चलता है कि इस बजट से आम जनता को लाभ नहीं होगा। इन्होंने इस बजट के पेज तीन पर लिखा है कि जरूरी चीजों दकी सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिये भी कदम उठाये गये है। सार्वजनिक वितरण पद्धति को मजबूत बनया गया जिसमें राज्य में जरूरी वस्तुओं को मुहैया कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई है। लेकिन मैं यह बात नहीं समझता कि वित्त मंत्री जी ने आम जरूरत की चीजे आम जनता तक कैसे पहुंचायी है? जनता राज में सभी चीजे मिलती थी। आज आम जनता के लिये मिट्टी कातेल, डीजल, सीमेंट उपलब्ध नहीं है। बाहरों में लोग लाइनों में खड़े रहते है। तमाम दिन लाइन में खड़े होने के पचात भी तेल नहीं मिलता। जनता पार्टी के राज में लोगो ने अपने राशनकार्ड फैंक दिये थे लेकिन अब फिर बनवाने पड़े है। ये कहते है कि वितरण प्रणाली ठीक है, यह गलत बात है। आज सीमेंट की कीमत 35 रुपये कट्टा है जबकि 70 रुपये में ब्लैक में मिल रहा है। आप यह कैसे कहते है कि वितरण प्रणाली ठीक है। सारे हरियाणा में हाय हाय मच रही है। सीमेंट के भाव बढ़ा दिये गये है। घी के टिन का भाव 30 रुपये ज्यादा हो गया। इस का कारण यह है कि सीमेंट और घी के कारखाने वालो से सरकारने पैसे लिये है इसलिये भाव बढ़ाये गये है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सिंचाई के विषय में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। रावी व्यास के पानी के बारे में ट्रेजरी बैंचिज के मेंबरान ने बड़ी तारीफ की है। इन्होंने वायदा किया है लेकिन वायदा पूरा होगा या नहीं होगा यह तो फिर ही पता लगेगा। आज हरियाणा असैम्बली में जो भाषण हो रहे हैं उसी तरह के भाषण पंजाब असैम्बली में भी हो रहे हैं। इस लिये मैं चाहता हूँ कि रावी व्यास पानी के बारे में आधे घंटे की बहस होनी चाहिए ताकि सही स्थिति का पता चला सके। अगर मुख्य मंत्री जी को इस बात पर विश्वास है कि ठीक फैसला हुआ है तो हमें इस पर बहस का मौका मिलना चाहिए लेकिन वे बहस का मौका नहीं देना चाहते। उन्हें इस बात का खदसा है कि अगर यहां हाउस में बात होगी तो हमारे पंजाब के भाई नाराज होंगे।

डिप्टी स्पीकर साहब, यहां बिजली के विषय में काफी कुछ कहा गया लेकिन आज किसान और घरेलू आदमी भी बिजली न मिलने के कारण परेशान हैं जिस आदमी का छोटा यूनिट है या बड़ा है वे भी सभी बिजली के बिना परेशान हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि बिजली का वितरण ठीक हो रहा है। मेरा हल्का किसानों का हल्का है। साल और छः महीनें हो गये हैं लेकिन बेचारों को बिजली के कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कनेक्शन न देना इस बात का द्योतक है कि बिजली व्यवस्था ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस महकमे में बड़ी धांधलेबाजी है। आप सुन कर हैरान होंगे कि भादी या दूसरे फंक्शनर होते

है उनमें कोई भी मीटर नहीं लगता है। हर साल कितने ही फंक्शन होते हैं। सभी लोग डायरेक्ट कनेक्शन लेते हैं। लाखों यूनिट बिजली यों ही जलाते हैं। भादी या दूसरे फंक्शन होते हैं उनमें अलग से मीटर लगना चाहिए लेकिन सरकार के भी कुछ ऐसे नियम हैं जिनके कारण वे सैपरेट मीटर इस परपज के लिये नहीं दे सकते। अगर ऐसे सख्त नियम हैं तो उन्हें तबदील करना चाहिए जिससे लोग अलग से, इस परपज के लिये मीटर लगवा सकें क्योंकि ऐसा करने से जो भी कंजम्पशन होगी उसका हिसाब किताब होगा और बिजली बोर्ड को भी आमदन होगी। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) स्पीकर साहब, पलवल के विषय में एक बात और कहना चाहता हूँ। पलवल में भूगर मिल लगाया जा रहा है। वह सैक्शन हो गया है। लाखों रुपये के भोयर हमने बिकवाये थे और पचास एकड़ भूमि मुफ्त देने का भी वायदा किया हुआ है लेकिन आज तक उस जमीन को सरकारने एक्वायर नहीं किया। क्या कारण है कि उसे एक्वायर नहीं किया जा रहा है। जब वहाँ चीनी मिल लगना है सैक्शन हो गया है फिर जमीन को एक्वायर करने में सरकार को क्या दिक्कत पेश आ रही है। इसलिये जमीन एक्वायर करके वहाँ जल्द से जल्द भूगर मिल लगाया जाये।

यहाँ पर रोजगार देने की भी बात कही गई। आज देहातों में पढ़े लिखे युवक बेकार फिर रहे हैं। यहाँ चण्डीगढ़ में हरियाणा के युवक इंटरव्यू देने आते हैं। उनकी एजूकेशनल क्वालिफिकेशन पूरा होने के बावजूद भी उन्हें सिलैक्ट नहीं किया

जाता है। अभी पिछले दिनों आई0टी0आई0 मे दाखिले की सिलैव न होनी थी। कुल 300 सीट्स थी। तीन सौ में से केवल 150 हरियाणा के लिये गये । मैं आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब हरियाणा के यूवक फिर रहे है तो उन्हे क्यों नहीं लिया गया। उनकी एजूके नल क्वालिफिके न पूरी है लेकिन वहां यू0पी0 और राजस्थान के लोग लिये गये है। यू0पी0 की एजूके न का स्टेंडर्ड हरियाणा से नीचा है। वहां के बच्चे यहां आ जाते है लेकिन हमारे बच्चे वहां जाते है तो उनका सिलैव न नहीं होता है। मैं कोई प्रांतीयता की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर यू0पी0 के बच्चे यहां दाखिल हो सकते है तो हमारे बच्चे भी वहां दाखिल होने चाहिए। ऐसा करने से हमारे बच्चे बेरोजगार रह जाते है और दूसरी स्टेट्स के बच्चे रोजगार पर लग जाते है। इसलिये इस खामी को दूर किया जाना चाहिए।

Mr. Speaker: Just a minute please. I want to reduce the time to seven minutes per member. टाइम चूंकि बहुत कम रह गया है, इसलिये अगर सब इससे सहमत हो, तो ऐसा कर लिया जाये।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री मूल चंद जैन: स्पीकर साहब, भाई खूर गीद अहमद जी यहां पर बैठे हुए है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वहां पर दो कालोनीज बसी हुई है। लेकिन गवर्नमेंट उस जगह को एक्वायर करने जा रही है। वहां पर लोगो ने अपने मकान बनाये

हुए है। वहां पर देहात के रहने वाले लोगो ने मकान बनाये हुए है लेकिन इन सब के बाबजूद सरकार ने दफा 4 का नोटिस इ जु कर दिया है। इससे लोग बहुत परे ान है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर जो दूसरी जमीन बेकार पड़ी है, उसको ले लिया जाये। जो कालोनी पहले से बसी हुई है, जिसके मकानों के नक्शे म्यूनिसिपल कमेटी से सैंक ांड है, उसको एक्वायर न किया जाये अगर आप ऐसा करेंगे तो लोगो को बड़ी भारी परे ानी होगी। लोगो मे इस वजह से बड़ी बेचैनी है। आखिर मे, मैं सड़कों के बारे मे एक बात कहना चाहूंगा। (विधन व भाोर) आखिरी बात कहकर मैं बैठ जाऊंगा। सड़कों के बारे मे मेरे हल्के मे पोजी ान ऐसी है कि एक गांव रायपुर है जो कि हथीन रोड़ पर है। केवल 250 मीटर का फाला है। वहां पर हमने काम के बदले अनाज कार्यक्रम के दौरान मिट्टी भी डलवाई हुई है। लेकिन वहां पर अभी तक सड़क नहीं बनी है, एक तो वह सड़क बननी चाहिए दूसरे आजादपुर जहां पर कि 400 घरों की आबादी है, वहां पर भी सड़क बननी चाहिए। (घंटी) अच्छा जी धन्यवाद।

कामरेड भांकर लाल (सिरसा): स्पीकर साहब, मैं तो सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि यह जो बजट हाउस मे रखा गया है, मैं इसकी मुखालिफत करता हूं क्योंकि यह बजट इलैक् ान को दृशिट मे रखते हुए पे ा किया गया है और यह सारे हरियाणा के साथ एक धोखा है। इस बारे मे, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वह यह कि सिरसा के अंदर जो कपास या

नर्मा पैदा होता है, वहां की जमीन उसकी पैदावार बहुत कम देने लग गयी है। अगर वहां पर भूगर मिल हरियाणा सरकार लगा दे तो वहां पर गन्ने की फसल बहुत ज्यादा पैदा होनी भूरो हो जायेगी। यह सारे जिले की मांग है कि वहां पर गन्ने की फसल बहुत ज्यादा पैदा होनी भूरो हो जायेगी। यह सारे जिले की मांग है कि वहां पर एक भूगर मिल जरूर लगनी चाहिए। एक बात मैंने कल भी हाउस में कही थी क्लास-I और क्लास-II के अंदर कर्मचारियों को प्रोमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। दूसरे सूबों में जैसे उनको प्रोमोशन के अंदर रिजर्वेशन मिल रही है, उसी तरह से हरियाणाके अंदर भी मिलनी चाहिये यहां पर यह रिजर्वेशन इन प्रोमोशन 1972 से बंद की हुई है। इस बारे में एक चिट्ठी चीफ सैक्रेटरी, हरियाणा सरकार की तरफ से सन् 1972 में ई.पू. हुई थी, उसके बाद से वह प्रोमोशन बंद है। जो रिजर्वेशन कास्टस और बैकवर्ड क्लासिफिकेशन के लिये 6.1 और 11.1 की रेटिंग के हिसाब से रिजर्वेशन हानी चाहिए वह नहीं है। इसलिये मेरा कहना यह है कि जैसे ऐक्सीशन से एस.ई. नायब तहसीलदार से तहसीलदार, थानेदार से डी.एस.पी. बनते हैं, उसी तरह से इनके अंदर भी सरकार की मर्जी के मुताबिक न बनाकर रिजर्वेशन के अनुसार बनाने चाहिये। मेरा कहना यह है कि चीफ सैक्रेटरी की उसचिट्ठी में जो फैसला किया गया है उसको वापिस लिया जाये। जिसे तरह से बैकवर्ड क्लासिफिकेशन और हरिजनों के लिये 100 में से 10 और 100 में से 20 पोस्टे रिजर्व होती है, उसी तरह से इनको प्रोमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। एक बात

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमें अपना खर्चा घटाना चाहिए। जितना भी हमारा खर्च बढ़ेगा उतने ही हरियाणा की जनता पर टैक्स लगेंगे। हरियाणा के अंदर यह जो जगह जगह पर पर्यटन स्थल बनाये जा रहे हैं यह भाराब खोरी के अड्डे हैं। सारे हरियाणा के अंदर जितने भी पर्यटन स्थल बनाये जा रहे हैं, यह भाराबखोरी के अड्डे हैं। सारे हरियाणा के अंदर जितने भी पर्यटन स्थल हैं, उनके ऊपर खर्च करने की हिम्मत हमारे हरियाणा जैसे गरीब प्रदेश के लोगों की नहीं है और न ही इसकी जरूरत है। इन होटलों में जो इतने महंगे हैं केवल अमीर लोग ही जाकर अथवा ही उड़ाते हैं। मैं खास तौर पर सिरसा जिले के बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ। न तो इस मुख्य मंत्री के काल में और न ही किसी पिछले मुख्य मंत्री के समय में वहाँ पर कोई विकास कार्य ठीक ढंग से हुआ है। इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मैं यह मानता हूँ कि इस सरकार ने अढ़ाई एकड़ तक के मालिक किसानों के खाल पक्के करने का खर्चा बिल्कुल माफ किया है। लेकिन उसे बड़े किसानों का नहीं किया है। इस वक्त हरियाणा की जनता की एक आवाज है कि पक्के खाल करने का खर्चा सरकार को हम नहीं देंगे। सरकार को खुद उसे बर्दाश्त करना चाहिए। यही नहीं, जो खाल पक्के किये गये हैं, वह तमाम के तमाम टूटे फूटे पड़े हैं। इसलिये मेरा सरकार से यह कहना है कि खालों को पक्के करने का तमाम खर्चा सरकार खुद बर्दाश्त करे।

श्री अध्यक्ष: कामरेड भांक लाल जी, आपका टाईम समाप्त हो गया है, आप वाईड अप करें।

कामरेड भांकर लाल: बहुत अच्छा जी, मैं अभी खत्म ही कर रहा हूँ। इस वक्त हरियाणा के अंदर जो मंत्री है या कारपोरेट्स के चेयरमैन है, चाहेक वे अब है या पहले रहे है, पिछले 5 सालों के अंदर उनकी जायदाद में कितनी बढ़ौतरी हुई है, इसका जायजा लिया जाये। इसके लिये एक कमीशन मुकर्रर किया जाये जो इस बात की जांच करे कि उनकी वाकई जायज है या नहीं। जहां तक मेरी जायदाद के ब्यौरे का ताल्लुक है मैं अब भी देने के लिये तैयार हूँ। पहले भी मैंने तो अपनी जायदाद का ब्यौरा दिया है और अब भी देने के लिये तैयार हूँ। आप कमीशन तो मुकर्रर करो। (व्यवधान व भाोर) अच्छा जी धन्यवाद।

चौधरी नारायण सिंह (पटौदी, एस.सी.): अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1982-83 का जो बजट वित्त मंत्री जी ने इस हाउस में पेश किया है, उस पर 3-4 रोज से बहस चल रही है दोनों तरफ के मेरे साथियों ने इसके हक में और विरोध में बोला है। जहां तक मेरा ख्याल है, यह बजट एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा बजट है जोकि वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। इसके अवास मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि चौधरी भजन लाल जी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद यही बजट नहीं, इससे पहला बजट भी ठीक बना है। हमारे अपोजीशन के भाई अब भी यह कहते हैं कि टैक्स इसलिये नहीं लगाये गये क्योंकि इलैक्ट्रॉनिजेशन पर आ रहे

है। यही बात 1981-82 का बजट पे 1 करने के बाद मे हुई डिस्कान के दौरान इन्होंने कही थी। दरहकीकत चौधरी भजन लाल और चौधरी खुरीद अहमद साहब, यह बात अच्छी तरह से जानते है कि हरियाणा की जनता बहुत गरीब है, यह टैक्सो का बोझ बर्दास्त नहीं कर सकती। मेरा तो विचार यह है कि इसी लिये टैक्स नहीं लगाये गये है क्योकि हमारी जनता इस बोझ को उठा नहीं सकती। मेरे हल्के पटौदी मे जब से यह मूलक आजाद हुआ, वहां पर सबसे पले कोई भी तरक्की याफता काम नहीं हुए थे। जब से चौधरी भजन लाल जी की सरकार आयी है मेरे हल्के मे कई तरक्की याफता काम हुए है। एक तो दो कालेज टेक ओवर किये गये है। दूसरे पटौदी को तहसील हैडक्वार्टर करा दे दिया गया है और वहां पर तहसील बैठा दी गई हैं। मैं इसके लिए अपनी सरकार का विशेष रूप से भुक्रगुजार हूं क्योकि 30 साल से हमारी यह मांग थी। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने सड़कें दीं। इसके लिए मैं सरकार का भुक्रिया आद करना चाहता हूं। स्पीकर साहब, पटौदी हलका में दो कमेटियां हैं एक तो फरुखनगर में है और दूसरी पटौदी में हैं। इन दोनों कमेटियों की हालत बड़ी खस्ता है। पिछले दिनों चौधरी भजन लाल जी वहां गए थे और इन्होंने वहां पर कुछ रूपया भी दिया था लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो वहां पर हौने चाहिए लेकिन वे पूरे नहीं हुए। इसलिए उन कमेटियों को और रूपया दिया जाना चाहिए। स्पीकर साहब, फरुखनगर में एक इमारत हैं। यह इमारत बहुत पुरानी है। मेरी प्रार्थना है कि आसार कदीमा को लिखा जाए

कि इस इमारत को गिरने से बचाया जाए। स्पीकर साहब, फरुखनगर से रेलवे स्टे 1 न तक स्ट्रीट लाइट नहीं हैं। वहां पर काफी अन्धेरा रहता है। आने जाने वाली सवारियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। भाहर ने ग्यारह हजार रूपया भी इकट्ठा करके स्ट्रीट लाइट के लिए दिया है इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कोई भी कमेटी स्ट्रीट लाईट लगाने की जिम्मेदारी ले और वहां पर स्ट्रीट लाईट लगाई जाए। स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना है कि पटौदी में कौमन लैटरीन बनाई जाएं और इस काम को जितना जल्दी हो सके पूरा किया जाए। स्पीकर साहब, वहां पर हरिजन बस्ती में से एक सड़क निकलती है इसके कारण वहां पर बहुत ज्यादा ऐक्सीडेंट होते हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस सड़क को वहां से हटा कर बस्ती से दूर हटाया जाए जिससे कि ऐक्सीडेंट न हो सके। मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

चौधरी पीर चन्द (रतिया, एस.सी.): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे टाईम देकर मुझ पर बहुत बडा अहसान किया है। 1982-83 का जो बजट चौधरी खुर पीद अहमद ने पे 1 किया है उसके लिए मैं उनका भुक्रिया आद करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं। जब मैं अपोजी 1 न में था उस वक्त भी बजट के ऊपर बोलने का मुझे मौका मिला था और अब पिछले दो तीन सालों से जब से चौधरी भजन लाल मुख्य मंत्री बने हैं, मुझे बोलने का मौका मिला है लेकिन जिस प्रकार का बजट दो

तीन साल से आ रहा है ऐसा बजट पहले नहीं आता था। इस बजट के अन्दर गरीब आदमी और हर कौमन आदमी का ध्यान रखा गया है। गरीब आदमी को ऊंचा उठाने के लिए इसके अन्दर प्रोजेक्ट रखी गई है। स्पीकर साहब, एस.वाई.एल. का झगड़ा काफी दिनों से चल रहा था और अब हमारी प्रधान मंत्री श्रीमति इन्दिरा गांधी ने पानी का फैसला करके हरियाणा के लोगों पर बड़ा भारी अहसान किया है इस पानी से हरियाणा के हर गरीब आदमी को फायदा पहुंचेगा। उनको नई जिन्दगी मिलेगी। स्पीकर साहब, यह केस पिछले ग्यारह साल से उलझा हुआ था। हमारे मुख्य मंत्री जी ने इसका फैसला कराने के लिए बड़ी मेहनत की और बड़ी दौड़ धूप की और इनकी मेहनत का ही फल हरियाणा को मिला है। स्पीकर साहब, पिछले अढ़ाई साल में हर गांव को इस सरकार ने पक्की सड़क से जोड़ दिया है यह भी बहुत सराहनीय काम है और अब किसी भी किसान को अपना माल मण्डी में ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। इस सरकार ने हर हरिजन बस्ती में लाईट देकर हरिजनों पर बहुत बड़ा अहसान किया है। गरीब लोगों को एक नई रोशनी दी है और गरीब लोगों को रोशनी में रहने का अधिकार दिया है। इस अहसान को गरीब आदमी कभी भूल नहीं पाएंगे।

स्पीकर साहब, हरिजन कल्याण निगम की राशि दो करोड़ से पांच करोड़ कर दी गई है और बैकवर्ड क्लासिज निगम को एक नया जीवन दिया है। राशि बढ़ने से जो हरिजन लोग हैं,

जो गरीब लोग है उनको अब ज्यादा कर्जा मिल सकेगा। यह गरीब आदमी को नई जिन्दगी देने की बात है। गरीब आदमी और बेरोजगार आदमी अब अपना रोजगार भुरू कर सकेगा। सरकार का यह भी एक बहुत सराहनीय काम है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के के बारे में भी बहुत सी बातें कहना चाहता था लेकिन समय कम है। अगर मुझे दो मिनट और दे दिए जाएं तो मैं अपनी कांस्टीटुएंसि के बारे में भी कुछ कह सकता हूँ। स्पीकर साहब, पहले जो सरकार आती रही हैं। उनके समय में सरकारी सर्विसिज में किसी भी क्लास के अन्दर हरिजनों का कोटा पूरा नहीं था और पहले हरिजनों के साथ बहुत ज्यादा गैरइन्साफी होती रही है लेकिन इस सरकार के आने के बाद काफी भाार्टफाल पुरी हुई है लेकिन अभी भी कुछ कमी है। मेरी सरकार से दरखाथ है कि इस भाार्टफाल को पूरा किया जाए और निगमों के अन्दर जो रिजर्वे नान नहीं है वहां पर भी रिजर्वे नान की जाए। मेरा वि वास है कि सरकार इस काम को अव य पूरा करेगी। स्पीकर साहब, सरप्लस जमीन को हरिजनों में बांटकर सरकार ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। जिन गरीब और हरिजनों के पास रहने का सहारा नहीं था, गुजारे का कोई सहारा नहीं था, ऐसा करने से अब उनका गुजारा चल सकेगा। काफी लोग कास्त करने वाले थे उनकी सरप्लस जमीन मिल जाने से अब वे का त कर सकेंगे। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि कई जगहो पर इन लोगों को कब्जा नहीं दिया गया है, बड़े लोगों ने उन जमीनों और प्लाटों पर कब्जा कर रखा है, जमीन बड़े लोगों से खाली करवाइ जाए ओर

हरिजनों को उसका कब्जा दिलवाया जाए। स्पीकर साहब, मेरा हल्का रतिया हमेशा से बैकवर्ड रहा है क्योंकि वहां पर किसी भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। वहां पर एक कालिज होना चाहिए। रतिया से पच्चीस किलोमीटर दूर फतेहाबाद है ओर तीस किलोमीटर टोहाना है और वहां पर कालिज हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर कालिज देकर एक सौ बीर गांवों को रियायत दी जाए। इसके साथ साथ स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना है कि रतिया को सब डिविजन बनाया जाए। स्पीकर साहब, इमना ही कहकर मैं समाप्त करता हूँ।

चौ. हुक्त सिंह (दादरी): स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है। स्पीकर साहब, इस बजट के बारे में कहा जा रहा है कि यह बजट गरीब लोगों और हरिजनों की बहबूदी का बजट है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं है और यह बहुत खोखला बजट है। मैं सदन को बताऊंगा कि किस तरह से हमारे वित्त मंत्री ने गरीब ओर मजदूर तथा किसानों के साथ अन्याय किया है। उनके लिये इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। स्पीकर साहब, रूलिंग पार्टी के लोग कहते हैं कि एम.आई.टी.सी. के किसान के खाल पक्के कर दिये और इससे इरीगेशन बढ़ेगी। स्पीकर साहब, जितनी भी नहरें पक्की की गई हैं या एम.आई.टी.सी. ने खाल पक्के किए हैं उनमें इतना घटिया मैटियरल लगा है कि उसकी वजह से सीपेज हो रही है और

किसानों की हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गई है। स्पीकर साहब, सरदार तारासिंह जी बड़े ही सज्जन आदमी हैं। मैं उनको आपकी मारफत यह बताना चाहता हूँ कि एम.आई.टी.सी. ने लोहरवाला गांव के पास से एक माईनर निकाली है, उसको आप चेक करवा लें आपको पता चल जाएगा कि पिछले तीन सालों से किसानों के खेतों की इरीगेशन नहीं हुई है। जो नाला है, उसमें सीमेंट बहुत कम लगाया गया है और जो उसमें ईटें लगी हैं, वह भी तीसरे दर्जे की लगी हुई हैं। एक फरलांग तक अगर उस माईनर को चलाए तो सीपेज शुरू हो जाती है, पानी लीक करना शुरू हो जाता है जिससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान होता है। इस तरफ सरकार ध्यान दे। इसी तरह से एक भागी माईनर बन रही है, वहां का भी मैं आपको बताता हूँ। वहां पर भी सरकारी माल की हेराफेरी हो रही है। एक किसान कहने लगा कि उसके सरसों के खेत में पता नहीं कौन आदमी पांच बोरी सीमेंट रख गया है। इस प्रकार से आप देखें कि इस तरह की सीमेंट में हेराफेरी हो रही है तो फिर उस माईनर पर कितना सीमेंट लगेगा और उसका बाद में क्या दर्शा होगा। इसलिये मिनिस्टर साहब, इन बातों की तरफ ध्यान दें ताकि किसानों को बाद में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े।

स्पीकर साहब, सरदार तारासिंह जी ने यह भी बताया कि किसानों को उनके ट्यूबवैल्ज पर 10 से 12 घंटे तक बिजली दी जाती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसानों को 5, 6

घंटों से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है। बारिश हो गई तो लोगों की फसलों को पानी मिल गया। उधर लोहारू लिफ्ट इरीगेशन जोकि बिजली से चलती है, वह बन्द हो गयी और इस तरह से किसानों की हजारों एकड़ में जो फसलें खड़ी थीं, वह बिल्कुल बर्बाद हो गयीं। सरकार इसको चैक करवा ले और जिन किसानों को नुकसान हुआ है, जिन किसानों की फसलें बिल्कुल तबाह हो गयी हैं, उनको सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाना चाहिये।

इससे आगे स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा दादरी मार्किट कमेटी की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि उस मंडी का बहुत बुरा हाल है। वहां पर किसानों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। जब किसान अपनी फसलों को लेकर के वहां पर आता है तो उसके ठहरने के लिये वहां पर कोई उचित प्रबन्ध नहीं है। उसके पशुओं के ठहरने का तथा उनको पानी पिलाने का वहां पर कोई इंतजाम नहीं है। वहां पर एक प्याऊ थी, वह भी बन्द है। वहां की मार्किट कमेटी की इन्कम से सरकार सड़कें बना रही है। चलो इस बात की मुझे खुशी है कि सड़कें तो बन रही हैं, मैं इसका विरोध नहीं करता लेकिन कम से कम किसानों को तो वहां पर हर तरह की सहूलियतें जैसे पशु बांधने तथा पानी पिलाने की मिलनी चाहिए। जो किसान हमारे खाने के लिए जिन्स वहां पर लाता है, उसको तो कम से कम हर तरह की सहूलियतें मिलनी चाहियें। इसलिये मेरा आपके द्वारा निवेदन है कि

सरकार इस तरफ ध्यान दे ताकि मार्किट कमेटियों में किसानों के हकों की रक्षा की जा सकें।

इससे आगे, मैं पशुपालन की बात कहना चाहता हूँ। यह ठीक है कि पशुओं के लिये सरकार ने जगह जगह पर डिसपैन्सरियां खोली हुई हैं जहां पर पशुओं का इलाज यिका जाता है वहां पर न तो इवाईयां हैं और न ही काबिल डाक्टर हैं जो कि किसानों के पशुधन का ठीक प्रकार से ध्यान रख सकें। ऐसी डिसपैन्सरियों खोलने का क्या फायदा? वहां पर दो सालों से मवेशियों की एक बीमारी चली हुई है और जब किसान अपने पशुओं को हस्पताल लेकर के जाता है तो किसानों को कह यिदा जाता है कि वहां पर दवाईयां नहीं हैं तो आप ही स्पीकर साहब, सोचिये कि किसान का एक ही पशुधन होता है अगर उसकी रखवाली भी हमारी सरकार न कर सके तो फिर उस सरकार का क्या फायदा? जो आजकल बीमारी पशुओं की चली हुई है, उस बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिये और सरकारी डिसपैन्सरियों में दवाईयां प्रोवाइड की जानी चाहिये और हरेक डिसपैन्सरी में काबिल डाक्टर भेजे जाने चाहियें। इन शब्दों के साथ, जो जो सुझाव मैंने यहां पर दिये हैं, आशा है कि सरकार इन पर अवश्य ही गौर करेगी। स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री लहरी सिंह मेहरा (रादौर, एस.सी.): स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का समय दिया।

स्पीकर साहब, यह जो 1982-83 का बजट 320 करोड़ रुपये का इस सदन में सरकार की तरफ से रखा गया है, यह गरीब आदमी के हक में और हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने के लिये इस सदन में हमारे वित्त मंत्री चौ. खुरशीद अहमद साहब, द्वारा पेश किया गया है। यह बजट सबसे बढ़िया बजट है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए, थोड़ी हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बजट की आपने भी ध्यान से पढ़ा होगा और यह देखा होगा कि पिछले तीन सालों से हरियाणा के अन्दर कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है और अब की बार भी कोई टैक्स नहीं लगाया गया है और जो थोड़ा सा घाटा दिखाया गया है, उसे राठी साहब पूरा कर देंगे।

स्पीकर साहब, अब मैं एग्रीकल्चर विभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर विभाग ने जितना काम इस पिछले साल में किया है, वह सचमुच ही सराहनीय है। मैं इसके लिये एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बधाई देता हूँ। पिछली बार जब चने का बीज नेशनल सीड कारपोरेशन से लाना था तो सेन्टर ने बीज का एक चौथाई छोड़कर तीन चौथाई बीज हरियाणा के लिये उपलब्ध कराया गया। इस सारे काम के लिये हमारे योग्य अधिकारियों को ही क्रेडिट जाता है।

इसके साथ साथ स्पीकर साहब, हरियाणा के लोगों के फायदे के लिये जिन्स को कम से कम दूरी से मण्डियों में पहुंचाने के लिये मण्डियों का निर्माण इस सरकार की देख रेख में हो रहा

है और वर्ल्ड बैंक के तहत साढ़े 23 करोड़ रूपये की सहायता से शाहबाद बबैन और दूसरी जगहों पर किसानों के लिये मण्डियों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे ऐसे तरक्की के काम हो रहे हैं फिर भी ये अपोजीशन वाले भाई कहें कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, ऐसा इनके लिये कहना शोभा नहीं देता। स्पीकर साहब, जगाधरी के अन्दर भी एक बड़ी मंडी का निर्माण हो रहा है। स्पीकर साहब, जगाधरी के अन्दर भी एक बड़ी मंडी का निर्माण हो रहा है। स्पीकर साहब, अब मैं अपनी सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। पहला सुझाव तो यह है कि जब जब रिजर्वेशन का सवाल आता है उस वक्त पूरी रिजर्वेशन नहीं दी जाती है। मेरे नोटिस में है कि 66 आदमियों मेंसे केवल तीन हरिजन ही लिये गये हैं। इसलिये मेरा अपनी इस सरकार को सुझाव है कि यह जो अप्पवायंटमेंट्स की गयी हैं, इनको कैंसिल किया जाए और दोबारा लोगों की भर्ती की जाए। इसी तरह से जो हैड कांस्टेबल को रिवर्ट किया जा रहा है, यह उनके साथ बड़ा भारी अन्याय है। स्पीकर साहब, पुलिस की भर्ती 6 परसेन्ट से 16 परसेन्ट तक पहुँच गयी है, यह एक बड़ी खुशी की बात है लेकिन जिन केसिज में पहले ही परमोशंज हो गई हैं, उनको पहले रेगुलर किया जाए और उनको रिवर्ट न किया जाए। यह मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, सुझाव है। बी-1 में जब तक किसी की रिजर्वेशन न होगी तो फिर वह सी-1 में कैसे जाएगा, इसलिये बी-1 में रिजर्वेशन होनी चाहिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनोंद): स्पीकर साहब, 1982-83 का जो बजट यह हाउस में जेरे गौर हे, मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूँ। स्पीकर साहब, वैसे तो अपोजीशन ने जितने भी एडजेकटिव इस बजट पर लगाने थे, वे लगा दिये हैं। मैं तो केवल यह बताना चाहता हूँ कि सरकार को यह देखना चाहिये था कि आया इस बजट के पेश करने से हम विकास के कार्यों की तरफ बढ़ें हैं कि नहीं? हमारे माननीय नेता बाबू मूल चन्द जैन जी ने बताया कि छटी पंचवर्षीय योजना के लिये 1800 करोड़ रुपये का कुछ प्रोवजन है जिस के हिसाब से हर साल 360 करोड़ रुपये का खर्च होना अनिवार्य है लेकिन इस सरकार ने इस साल केवल 319 करोड़ रुपये का ही बजट पेश किया है। इससे ही आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जितना इन्होंने एक साल के बजट में प्रोवजन रखना था, उससे कहीं कम खर्चा किया जा रहा है तो फिर ये डिवेलपमेंट के सारे कामों को किस प्रकार कर सकेंगे, कितना इनका ध्यान विकास की ओर हो सकता है। मैं बाकी सारी बातों को छोड़कर एक ही बात पर आता हूँ, वह हे पावर सैक्टर। पावर सैक्टर के लिये खुरशीद जी ने 94 करोड़ रुपया मकसूद रखा है ओर इस बारे में बड़ा जोर शोर से यहां पर कहा गया कि नाथपा-झाखड़ी प्रोजैक्ट पर काम चल रहा है मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ कि पीछे हमारे हाउस की पी.ए.सी. कमेटी श्री राव राम नारायण जी की अध्यक्षता में वहां पर गयी थी लेकिन मुझे इस बारे में बड़े ही दुख के साथ कहनापड़ता है कि वहां पर किसी किस्म का कोई काम शुरू ही नहीं किया गया है और उस

प्रोजैक्ट के साथ तीन और प्रोजैक्ट भी जोड़ दिये गये हैं। एक यमुना प्रोजैक्ट, दूसरा दादूपुर प्रोजैक्ट और तीसरा वैस्टर्न यमुना कैनल, फर्स्ट फेज ओर इनके लिये पैसा केलव उपलब्ध करवाया गया है 1 करोड़ 52 लाख। इस बात से ही आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि सरकार इन पावर सैक्टर्ज में जोकि हरियाणा की लाइफ लाईन है, इसके लिये कितनी चिन्ति है? बहुत सालों से ये मामला लटका हुआ था। हमारे वक्त में भी वह एग्रीमेन्ट हुआ था। चौ. बंसी लाल जी के वक्त में भी इस तरह का एग्रीमेंट हुआ था ताकि हरियाणा के हितों को लाभ पहुंचे हरियाणा के हितों को मसला न जाए लेकिन आज की सरकार ने नाथपा झाखड़ी का जो एग्रीमेंट किया है, उसमें एक क्लॉज रख दी गई कि हरियाणा 50 परसेन्ट पैसा अपने हिस्से का लगायेगा और केवल उसे इसके बदले में 42 परसेन्ट हिस्सा मिलेगा। स्पीकर साहब, 20 परसेन्ट बिजली इन्होंने नारायण दत्त तिवारी के दबाव में आकर उत्तर प्रदेश को मुफ्त दे दी।

12.00 बजे

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। जो व्यक्ति हाउस में अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। हमने तिवारी साहब के दबाव में आकर किसी प्रदेश को मुफ्त बिजली नहीं दी। मुफ्त बिजली देने का किसी को सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री वीरेन्द्र सिंह: चलो यह बात में नहीं कहता। स्पीकर साहब, नाथपा झाखड़ी प्रोजैक्ट के अलावा सरकार ने एस.वाई.एल. के एग्रीमेंट की खुशी में सरकारी बिल्डिंगों पर दीप मालाएं जलाई। एलाईनमेंट के बारे में मैं इस सदन में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि इस बारे में मुख्यमंत्री जी से मेरा वायदा है। एस.वाई.एल. के एग्रीमेंट के बारे में कहते हुए मुझे दुख होता है कि इन्होंने लोगों को बहुत गुमराह किया है। सवाल किसी फैसले का नहीं बल्कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन का है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 24 मार्च, 1976 को उसका एवार्ड दिया था। उसके हिसाब से 3.5 एम. ए.एफ. पानी हरियाणा प्रान्त को मिलना मन्जूर हुआ था। यह पानी 15.85 एम.ए.एफ. में से मिलना था। जब चौ. देवी लाल के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार आई तो हमने उस सारे मामले को देखा। हांलाकि उस पानी में से हरियाणा का क्लेम बहुत ज्यादा बनता था और इस बारे में उससे पहले तीन कमेटियां अप्वायंट हो चुकी थी। हर कमेटी ने 4.8 एम.ए.एफ. से हरियाणा का हिस्सा कम नहीं किया था लेकिन फिर भरी हमारे से पहले जाने वाली सरकार 3.5 एम.ए.एफ. पानी के लिये कमिट कर गई। उतने पानी के लिए हमने जदो जहद की। बहुत मीटिंग हुई और चौ. भजन लाल ही हमारे साथ शामिल होते रहे। हमने बहुत जदो जहद की, आखिर मजबूर होकर हमने सुप्रीम कोर्ट में दाबा दायर किया कि हरियाणा को उसका हिस्सा दिलाया जाए और उस नहर को एक सैन्ट्रल एजेंसी की तरफ से खुदवाया जाए। हमने कहा कि सारी कार्यवाही सैन्टर अपने हाथ में ले ओर जो नुकसान हरियाणा प्रान्त को हो

रहा है, जो नेशनल लौस भी है उसको पूरा किया जाए। हमें अफसोस है कि एक झूठा प्रचार करने के लिये और लोगों को गुमराह करने के लिए मुख्यमंत्री जी उस 15.85 एम.ए.एफ. पानी में से साढ़े तीन मिलियन एकड़ फीट पानी की बजाए 3.05 एम.ए.एफ. पानी करवा कर आ गए। ये चाहते हैं कि उसके लिये यहां हम भी मेज थप थपाएं। यहां पर एक बात और कही गई कि नई एलाइनमेंट के कारण 9 करोड़ रुपये बचा लिया गया है और 14 मील की लम्बाई घटा ली गई है। स्पीकर साहब, यह रूपया इसलिये नहीं बचा कि इन्होंने एलाइनमेंट बहुत बढ़िया करवा ली बल्कि वह रूपया इसलिये बचा कि इस नहर की कैपेसिटी पहले जहां 7500 क्यूसिकस होनी थी अब वह घट कर 6500 कर ली गई है। स्पीकर साहब, एक बाम में इसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि चलो अगर 8 तारीख को ये नहर का उदघाटन करवा दें तो बहुत बढ़िया बात होगी। अगर ये हमें भी बुलाएंगे तो हम भी उस मौके पर जरूर आएंगे।

चौ. भजन लाल: आप सबको अभी इनवाइट किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: मुख्यमंत्री जी तो इशारा कर रहे हैं कि चाहे इधर आकर बैठ जाओ। (हंसी)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, हम उधर जरूर जाएंगे लेकिन तब जाएंगे जब जनता हमें भेजेगी वरना नहीं जाएंगे।

स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि अगर ये एस.वाई.एल. के उदघाटन के मौके पर हमें बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे लेकिन वह नहर खुदनी चाहिए, इतनी अश्योरैन्स मैं मुख्यमंत्री जी से चाहता हूँ। इसके अलावा इन्होंने ओर भी बहुत बातें कहीं हैं लेकिन टाईम कम होने की वजह से मैं उनको जवाब नहीं दे सकता। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि पांच किलोमीटर जमीन हमारे कहने पर 1978 के फरवरी महीने में पंजाब सरकार ने एक्वायर की थी लेकिन ये एक भी किलोमीटर जमीन एक्वायर नहीं करवा सके। जहां पर यह उदघाटन होने जा रहा है वह वहीं जमीन है जो हमारे वक्त में एक्वायर हुई थी। अगर ये चाहते हैं तो मैं उस गांव का भी नाम बता सकता हूँ। स्पीकर साहब, यह बड़े अचम्भे और हैरानी की बात है कि यह सरकार निरे स्कैंडलों की ही सरकार है। आपको मालूम है कि एक ही स्कैंडल पर अन्तुले चला गया। दिल्ली से बम्बई कितनी दूर है लेकिन हरियाणा तो दिल्ली के चारों तरफ घिरा हुआ है। लेकिन चिराग तले अन्धेरा नजर आता है। यहां पर अम्बाला में बलविन्द्र कौर स्कैंडल हुआ, भिवानी में सैक्स स्कैंडल हुआ ओर यहां पर सीमेंट स्कैंडल हुआ। मैं कितने स्कैंडलों के नाम गिनाऊँ। यहां पर वातावरण स्कैंडलों से भरपूर हो चुका है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जो इस हाउस में सदस्य बैठे हैं उनमें से किसी भी सदस्य का नाम इस स्कैंडलों से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन इधर-उधर की बातें सारे हरियाणा में घूमी हुई हैं। बड़े बड़े लोग जो शक्ति में हैं उनका नाम किसी न किसी स्कैंडल से जुड़ा हुआ है। क्यों

नहीं मुख्यमंत्री जी अपोजीशन के लोगों को कन्फीडेंस में लेकर इस वातावरण को साफ करवाते, मुझे यह बात समझ नहीं आती। अब मैं इन स्कैंडलों को छोड़ते हुए ला एंड आर्डर की बात पर आता हूँ। मैं एक इंस्टांस दूंगा। बाबू मूल चन्द जैन जी ने भी सही फर्माया था कि मत प्राउड करो इस बात का कि हरियाणा में दूसरे प्रदेशों की निसबत ला एंड आर्डर बेहतर है। बेहतर तो इसलिये है कि यहां की जनता पीसफूल है। एक कोआप्रेटिव बैंक का डायरेक्टर अजीत सिंह ढांढा नाम का आदमी जीन्द से एक महीने से गायब है। पर्चा दर्ज है लेकिन यह सरकार क्यों नहीं उसको तलाश कर पा रही है। फिर ये कहते हैं कि हरियाणा के ला एंड आर्डर पर हमें घमंड करना चाहिए। जीन्द में ही एक भगवान दास ट्रक ओनर का एग्रीकल्चर विभाग के कर्मचारियों से बहुत झगड़ा हुआ है। जीन्द के यहां पर तीन-तीन मंत्री बैठे हैं लेकिन अभी तक उस ट्रक ओनर के सिर्फ तीन-तीन आदमियों को ही गिरफ्तार किया गया है और जो बाकी चार आदमी असली कलप्रिटस थे, वे जीन्द में ही रहते हैं लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। गिरफ्तार इसलिये नहीं किया जा रहा है कि भगवान दास की मुख्यमंत्री तक पहुंच है। सरकारी कर्मचारियों ने 60 आदमियों को तो हिसार जेल में भेज दिया गया है लेकिन उनको नहीं पकड़ा गया।

चौ. भजन लाल: सब गिरफ्तार कर लिये गये है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: मेरी इतलाह के मुताबिक तो कड़े नहीं गये। हो सकता है कल पकड़ लिये हों। स्पीकर साहब, इसी सदन में खास तौर पर चर्चा आई कि ये उदघाटन मंत्री और घोशणा मंत्री बन चुके हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि चौ. भजन लाल जी को अगर यह बहम हो गया है कि केवल पत्थर पर नाम लिखने से इतिहास में उनका जिक्र रहेगा तो वे गलती में हैं। इतिहास में जिक्र होता है आदर्श की पालना करने से, जन सेवा करने से, और देश भक्ति की परम्पराएं कायम करने से। केवल पत्थर लगाने से इतिहास में जिक्र नहीं होगा। जब पत्थर लगाने के लिये जगह खत्म हो जाएगी तो मुख्यमंत्री जी शौचाल्यों का उदघाटन करने लग जाएंगे। स्पीकर साहब, हरियाणा का वातावरण स्कैंडलों और करप्शन से बिल्कुल दूषित हो चुका है। मेरे पास एक कवि की लिखी हुई कविता की 6 लाईनें हैं। इन लाईनों से मैं हरियाणा के वातावरण का चित्र खींच सकता हूँ। वे लाईनें हैं:—

अलविदा हो हिन्द से इन्सान जन्नत को गए,

मुखलूक की इमदाद में बस तीन बेटे रह गए।

सबसे बड़ा रिश्वत अली बिचला सिफारिशखान है,

छोटा खुशामद बेग जिसकी निराली शान है।

कत्ल के भी जुर्म में रिश्वत अलि की जीत है,

सख्त हाकिम मोम हो गाता उसी के गीत हैं ।

नौकरी गर न मिले तो मिल सिफारिशखान से,

अक्त का चाहे खोज न हो, कर हकूमत शान से ।

छोटा खुशामद बेग है गोदी ले पुचकार कर,

जी हजूरी सीख ले चाहे कितने ही अत्याचार कर ।।

स्पीकर साहब, हरियाणा में यह वातावरण है । कांग्रेस पार्टी के दो एम.एल.एज. चौ. रिजक राम और चौ. सुरेन्द्र सिंह की यह हालत हो गई है कि इनका आज ही तवा बदल गया । इनके बारे में आज ही अखबार में खबर आई है कि इनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिसिप्लनरी ऐक्शन लेने के लिये नोटिस दिया जा रहा है ।

अजब दस्तूर जबांबन्दी है तेरी महफिल,

कि यहां कुछ कहने को तरसती है जुबां मेरी ।

स्पीकर साहब, मुझे नहीं पता था कि चौ. रिजन राम जी इतने कमजोर हो चुके हैं । कल तो इन्होंने एस.वाई.एल. के फैसले के बारे में बहुत बातें कहीं थी मैं इनको कहना चाहता हूँ कि यह फैसला भी गलत हुआ है । यह फैसला भी आज अखबार में कांग्रेस पार्टी के दो एम.एल.एज. के बारे में खबर आने के ठप्प हो गया । मैं इन दोनों एम.एल.एज. को अपने विपक्ष के नेता की इजाजत से

एक बा कहना चाहता हूँ कि यदि कांग्रेस पार्टी का ऐसा माहौल हो चुका है ओर इस पार्टी में इन दोनों एम.एल.एज. का दम घुटता है तो मैं इन दोनों सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि ये आज ही उधर की सीट खाली कर दें हम इनके लिये इधर पीछे सीट दे देंगे। बाकी एम.एल.एज. को भी मैं यह कहता हूँ कि दलबदली के कारण जिनकी आत्माएं घुट चुकी हैं उनके लिये 29 मार्च का सही टाईम है यदि वे अपने टैम्पर को साफ काना चाहते हैं तो श्री रामफल कोहली को राज्यसभा में चुनकर भेज दें ताकि हरियाणा में जो दूषित वातावरण पैदा हो गया है वह खत्म हो सके। स्पीकर साहब, बाबू जी ने प्रोहिबिशन पर बोलते हुए इनको कांग्रेस पार्टी की परम्पराएं याद दिलाई थीं और मुख्यमंत्री जी आज नैतिकता की बात करते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि यह तो वह कांग्रेस है जो नारे लगाती है कि देश की नेता इन्दिरा गांधी, यूथ कांग्रेस के नेता राजीव गांधी और बच्चों के नेता राहुल गांधी, भाड़ में जाए महात्मा गांधी।

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, मैं चौ. वीरेन्द्र सिंह का सम्मान करता हूँ इन्होंने यह कहा कि मैं, आपको अपनी पार्टी में आने के लिये यानी इधर आने के लिये आमंत्रित करता हूँ। मैं इनको एक बात साफ बताना चाहता हूँ कि इधर आने से जहन्नुम में जाना बेहतर होगा।

गृह मंत्री (श्री कन्हैयालाल लाल पोसवाल): स्पीकर साहब, चौ. वीरेन्द्र सिंह ने इतनी लाईने पढ़ी हैं मैं इनको सिर्फ दो लाईनों में ही इनको इनकी कारणदियां बताना चाहता हूँ:-

अपनी सेवा के जलाते हैं अंधेरे में चिराग

उनकी साजिश है कि जमाने में सदां रात रहे।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं भी इनकी सेवा में दो लाईनें कहना चाहता हूँ:-

बरबादी ऐ गुलशन के लिए एक ही उल्लू काफी था,

हर साख पे उल्लू बैठे हैं अंजामे गुलिश्ता क्या होगा।।

श्री कन्हैयालाल पोसवाल: हामने हय साख ही उड़ा दी है तो उल्लू बैठेगें कहां।

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, चौ. वीरेन्द्र सिंह जिस समय मंत्री थे उस समय लोगों के काम करने की बजाय लोगों के पास जाने के लिये आंखों में स्याही डाल कर जाया करते थे। (हंसी)

चौ. अजीत सिंह: स्पीकर साहब, मैं भी आपकी इजाजत से कुछ कहना चाहता हूँ:-

सोचा तो था इस गुत्थी को खोलोगे सुलझाओगे,

किसे पता था तुम कुर्सी की खातिर यों बिक जाओगे ।
चांद ईद का एक साल में एक बार आ जाता है,
हमें पता है बाद बजट के शकल नहीं दिखलाओगे ।
टैक्स बजट में नहीं लगाये तो भी कुछ एहसान नहीं,
बाद बजट के लोगों को तुम नोच नोच कर खाओंगे ।
वित्त मंत्री जी मेरे प्रश्नों का उत्तर दो इस जनता को,
घी के मटके लुढ़क लुढ़क कर कब तक आग
बुझाओंगे ।।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड न किया जाए । (शोर)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार तारा सिंह): स्पीकर साहब, बिजली और सिंचाई के मुतल्लिक काफी बातें हाउस के सामने आई हैं । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चौ. भजन लाल जी की सरकार के वक्त में पावर एंड इरीगेशन में जितने काम हुए हैं, चहो वह काम हाइडल प्रोजैक्ट का हो, चाहे थर्मल प्लांट का हो और चाहे ड्रेनेज का हो, चाहे आप्रेशन डिवीजन का हो, कोई भी काम हो यदि मैं सारे कामों के बारे में कहूंगा तो काफी समय लगेगा । मिनिस्टर आफ पार्लियामैट्री अफेयर्स ने मुझे यह कहा है कि सारी बातों का जवाब मैं खुद ही दे दूंगा । स्पीकर साहब, मैं ।

एक ही बात कहना चाहता हूँ कि दो तीन दिन पहले मेरे माननीय दोस्त चौ. सुरेन्द्र सिंह ने हाउस में कुछ जिक्र किया था। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। अगर वह बात कोई अपोजीशन के एम.एल.ए. कहते तो मुझे कोई दुख नहीं होता। वह बात कोई ऐसी नहीं है, यह बात पहले भी सदन में आई थी उसका मैंने जवाब दे दिया था। चौ. सुरेन्द्र सिंह जी ने एक बात यह कही कि मैंने जमीन की नाजायज गिरदावरी करवा रखी है। स्पीकर साहब, यह केस अदालत में है इसलिये मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं कहता। उन्होंने मेरे खिलाफ उस जमीन का अदालत में दावा कर रखा है। मैंने इस बात का जवाब पिछले सेशन में भी दिया था लेकिन अब मैं इतना ही कहूँगा कि यह मामला सबजूडिस है इसलिये मुझे इस बारे में ज्यादा बात नहीं कहनी चाहिए। इन्होंने दूसरी बात फर्टीलाइजर के बारे में कही। फर्टीलाइजर के बारे में मैंने पिछले सेशन में जवाब दे दिया था। स्पीकर साहब, उस समय आपने फर्टीलाइजर के मामले पर बहस करने के लिये आधे घंटे का समय भी मुकर्र किया था। बहस के दौरान चौ. वीरेन्द्र सिंह ने कहा था कि करनाल की अदालत में सरदार तारा सिंह की किसी वकील के साथ सांझेदारी है। स्पीकर साहब, मैं आज भी चैलेंज करता हूँ और यह कहता हूँ कि अपोजीशन लीडर श्री मूल चन्द जैन यह कह दे कि करनाल की अदालत में मेरी किसी वकील के साथ वकालत में सांझेदारी है या थी तो मैं आज ही इस्तीफा दे दूँगा और आयंदा के लिए पोलिटिकल कैरियर छोड़ने के लिये तैयार हूँ। इसके अलावा

स्पीकर साहब, जहां तक पेस्टीसाइड की बात है, इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी देर मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहा हूं उस समय में पेस्टीसाइड के बारे में कोई इस किस्म की बात नहीं आई थी। स्पीकर साहब, मैं एक एक फाईल को बड़ी गौर से देखता हूं। इन्होंने यहां पर बाजरे के बीज का भी जिक्र यिका था। मैंने भी इस बात को देखा था कि हर साल गुजरात से ही बाजरे का बीज क्यों मंगवाया जाता है। इस सम्बन्ध में, मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरान को बुला कर यह पूछा था कि गुजरात से बाजरा क्यों मंगवाते हैं। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि गुजरात एक ऐसी जगह है जहां मौसम के मुताबिक बीज उपलब्ध हो जाता है। अफसरान ने मुझे यह भी बताया था कि शंकर बाजरे का बीज सबसे बढ़िया बीज है। मैंने सैक्रेटरी लैवल के अफसरों को बुला कर बात की थी। इन्होंने यह भी कहा था कि छः और जगहों की दरखास्तें रिजैक्ट कर दी हैं। उनके सम्बन्ध में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने अपने कागज पत्र पूरे नहीं किये थे और न ही उन्होंने कोई सर्टिफिकेट साथ भेजा था।

Mr. Speaker: There is no need to go into details.

सरदार तारा सिंह: यहां पर एक बात भिवानी की भी आई थी। (शोर) अध्यक्ष महोदय, मैं उस बारे आज भी इन्कवायरी करवाने के लिये तैयार हूं। जो बात मेम्बर साहब ने मेरे बारे में कही है वह ठीक नहीं है। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इनके वक्त के जो केस

थे यानि इन्होंने जो किया था यदि उनको मैं चलाता तो ये सारी उम्र जेल में रहते कभी बाहर नहीं आते। इन लफ्जों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

Sh. Surender Singh: Point of order, Sir.

Mr. Speaker: It should be on personal explanation only.

Sh. Surender Singh: Sir, I will confine myself to that extent only.

Mr. Speaker: No counter-allegation should be levelled. Only personal explanation be made.

Sh. Surender Singh: All right, Sir. अध्यक्ष महोदय, अभी मिनिस्टर साहब ने बैठते हुए कहा कि यदि मैं उन केसों को चलाता तो मैं सारी उम्र जेल से बाहर नहीं आता। मैं इनको कहता हूँ कि ये बेशक उन केसों को चला लें, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो आरोप लगाये थे वे जनता पार्टी की सरकार पर लगाये थे। इस बात के अलावा मैंने और कोई बात नहीं कही थी। यह कह रहे थे कि मैंने ऐसा कोर्ट काम किया है तो मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अभी कहा है कि मैंने करनाल की कुछ बात कही थी और चार्ज लगाये थे। इस सम्बन्ध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सभी आरोप मैंने जनता पार्टी की सरकार पर लगाये थे। यदि ये

जनता पार्टी की सरकार के समय का कोई जवाब देते हैं तो इसमें, मैं क्या कर सकता हूँ।

वित्त मंत्री (चौ. खुरशीद अहमद): अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के 26 साथियों ने बजट की बहस में हिस्सा लिया। बहुत से साथियों ने बहुत अच्छे प्वायंट भी रखे हैं। लेकिन कई साथियों ने अच्छे प्वायंट नहीं रखे। उन्होंने चार अन्धों वाला काम किया। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। चार अन्धों को एक हाथी मिला। एक अन्धे को हाथी की टांग हिस्से में आई, वह कहने लगा कि यह खम्बा है। दूसरे अन्धे के हाथ में सूण्ड आयी, वह कहने लगा कि यह ट्रंक है। इसी प्रकार से बाकी के दो अन्धे भी अपनी-अपनी बात कहते रहे। यानि मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे कुछ साथियों ने कजअ पर इधन उधार की बातें कहीं हैं जिनका बजट से कोट सरोकार नहीं था। मैं अपने साथियों के कंफूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। मैं एक ही बात में उनकी सारी बातों का जवाब धीरे धीरे दे दूंगा। यह जो बजट पेश किया गया है यह हरियाणा के लोगों के हित के लिये पेश किया गया है। इस बजट को बिना टैक्स के लगाये प्रस्तुत किया गया है। इससे गरीब जनता पर कोई बोझ नहीं पड़ा। बहुत से साथियों ने यह भी कहा कि बहुत सा पैसा फिजूल खर्च किया जा रहा है। इस बारे में, मैं अपने साथियों को एक एक आइटम का जवाब दूंगा। स्पीकर साहब, 1977 से जब ये उधार वाले भाई आए हैं तब से औलावृशि और बाढ़ हर साल आती रही है। (शोर) स्पीकर साहब,

जिस दिन ये चले जाएंगे उस दिन बहुत सारे खर्चे अपने आप कम हो जाएंगे।

स्पीकर साहब, हमारे विरोधी पक्ष के नेता बाबू मूल चन्द जैन जी ने शुरू में एक बात कही कि नौन प्लान एक्सपेंडीचर में कमी करने की कोई कोशिश नहीं की गई। इस नौन प्लान एक्सपेंडीचर का मेजर पोर्शन वर्ष 1980-81 का रिवाइज्ड एस्टिमेट 370 करोड़ रुपये का बनता है जबकि वर्ष 1981-82 का 330.71 करोड़ रुपये बैठता है। इस प्रकार यह इन्क्रीज वर्ष 1981-82 के अन्दर 39.51 करोड़ रुपये होती है। स्पीकर साहब, आप देखेंगे कि तकरीबन 11.95 प्रतिशत रुपये की इन्क्रीज हुई है। स्पीकर साहब नेचुरल कलैमेटिज पर जो खर्च हुआ है वह 7.66 करोड़ रुपये बैठता है। हरियाणा रोड़वेज की बसों की जो कीमतें बढ़ी हैं यह दूसरे खर्च बढ़े हैं उन पर तकरीबन 3.39 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसी प्रकार से पैन्शनरी बैनिफिट्स पर 1.43 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इस प्रकार यह टोटल खर्चा 12.48 करोड़ रुपये बैठता है। यदि इसको निकाल दिया जाये तो फिर 27.03 करोड़ रुपये की बढ़ौतरी होती है जोकि 8.17 प्रतिशत आती है। इन 27.03 करोड़ रुपयों में से नौन प्लान खर्च में स्टाफ को डी.ए. देने में 14.59 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इनको निकाल कर बाकी 3.76 प्रतिशत बढ़ौतरी होती है।

This figure has accounted for the entire increase in expenditure in office expenses, new activities, strengthening and improvement of vital services (including Education, Police,

Health etc.) and for price rise. So this residual increase of 3.76% is negligible.

स्पीकर साहब, आप भी जानते हैं कि लोगों की जो समस्याएं हैं वे बगैर पैसे के हल नहीं हो सकती। इसलिये यह जो खर्च हुए हैं ये निहायत जरूरी थे। स्पीकर साहब, जो खर्च हुआ है वह उतना ही हुआ है जितना हर हालत में होना चाहिए था। इस प्रकार से वर्ष 1982-83 के अन्दर नौन प्लान एक्सपैन्डीचर में 4.30 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है। यह बढ़ौतरी फिक्स की हुई राशि से कम है और इस बात को 7वें वित्त आयोग ने भी माना है। ये नार्मज आल इण्डिया लैवल पर फिक्स किए हुए होते हैं। इसके अनुसार कुछ भी वेस्टफुल कहना उचित नहीं है। यह ठीक है कि सरकार ने 3.40 करोड़ रुपये का जो ओवर ड्राफ्ट रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने लिया था वह इसी साल पे करना पड़ा है जोकि पिछले साल से ज्यादा है। यह पैसा हमें इसलिये खर्च करना पड़ा कि कहीं पर ओलावृष्टि हो गठ और कहीं पर कहत पड़ गया जिसकी वजह से यह पैसा लेना पड़ा था। स्पीकर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह राशि नाजायज खर्च नहीं की गई। लोगों को सुविधया दने के लिये उन्हें राहत देने के लिये खर्च करनी पड़ी थी। जब कहीं पर ओलावृष्टि हो जाती है और किसानों को सहायता आदि दी जानी होती है तो हमें तुरन्त पैसा फील्ड में भेजना होता है। यह अलग बात है कि हम बाद में गवर्नमेंट आफ इण्डिया से वह पैसा ले लें। इसलिये हमें ओवर ड्राफ्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि हम किसानों को समय पर

पैसे नहीं देंगे तो उनमें असंतोश फैलेगा। किसानों की सुविधा के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। आप भी जानते हैं कि जब ओला वृष्टि हो जाती है तो फसलें सारी बर्बाद हो जाती हैं। लोगों को अपने पशुओं के लिये भूसा आदि खरीदना होता है। उनके पास पैसा नहीं पहुंचेगा तो उनका काम नहीं चलेगा, उनके पशु भूखे मर जाएंगे। जिस पर मुसीबत आई है उसको पैसा उसी वक्त देना होगा। इसी तरह से जो रिक्वरी होनी होती है उसको भी पोस्टपोन करना पड़ता है इन सब बातों का क्युमुलेटिव असर यह होता है कि अपने जरायों से हमें यह सब करना पड़ता है अगर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का ओवर ड्राफ्ट किसी दिन ज्यादा और किसी दिन कम भी हो जाए तो उस पर हमें इंस्ट्रूमेंट देना होगा। ये मजबूरियां हैं जिनसे हम ऐसकेप नहीं कर सकते। यह इसी साल का नहीं है। पिछले साल के अन्दर जो रिमशन देना पड़ा और ऐक्सट्रा पैसा देना पड़ा उसका हिस्सा भी इसमें शामिल है और तकरीबन एक करोड़ के करीब यह बनता है। इस सब बातों को देखते हुए ओवर ड्राफ्ट का इल्जाम हमारे ऊपर लगाना ठीक नहीं जंचता क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो लोगों को राहत नहीं मिल पाती। लोगों को राहत देने के लिए अगर सरकार को थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट भी देना पड़े तो उसमें कोई खराब बात नहीं है यह हमारी सरकार की पालिसी है।

श्री मूल चन्द जैन: क्या आप बताएंगे कि ओवर ड्राफ्ट की मात्रा कभी 70 करोड़ हुई है? (विघ्न)

चौ. खुरशीद अहमद: जब पैसा ऐसी चीजों पर खर्च करना पड़े जो एकदम आ पड़े तो उनके लिए रिलीफ ग्रांट करने के लिए हमें आवश्यक इन्तजाम करना पड़ता है। जब तकावी और दूसरे कर्जों को इल्तवा करना पड़े तो यह पैसा खजाने में दाखिल नहीं होता और ओवर ड्राफ्ट नैचुरली बढ़ेगा। मैं मानता हूँ कि ओवर ड्राफ्ट नहीं बढ़ना चाहिए लेकिन जैसा मैंने पहले अर्ज किया यह तभी हो सकता है यदि हम लोगों की सहूलियत की परवाह न करें। अगर हमने लोगों की भलाई के लिए काम करने हैं तो एक दिन के लिए, दो दिन के लिए या महीने के लिए ओवर ड्राफ्ट में एक दो करोड़ रुपया चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है।

स्पीकर साहब, कुछ दूसरे साथियों ने और बाबू मूल चन्द जैन जी ने भी यह बात कही कि गवर्नमेंट के खर्च में 70 करोड़ रुपये के रैवन्यू का कुछ पता नहीं लगता कि वह कहा गया। मैं उनका ध्यान बजट ऐस्टीमेंटस 1981-82 और बजट ऐस्टीमेंटस 1982-83 के रिवाइज्ड टेबल की तरफ दिलाना चाहता हूँ। उसमें हर चीज को ऐक्सप्लेन किया गया है। उसको देखने से इन्हें पता चलेगा कि टोटल वहीं 18.17 करोड़ पर आता है। स्पीकर साहब, नैक्सट इयर की रिकवरीज को डालते हुए ये उस टेबल को दुबारा देखें। इसे देखने से इनका कंप्यूजन दूर हो जाएगा। अगर ये उसे नहीं देखना चाहते तो मैं इनको यह पेपर भिजवा देता हूँ। (इस समय एक कागज बाबू मूल चन्द जैन जी को दिया गया।) इसको जोड़ तोड़ लगा कर ये देख लें। (विघ्न)

जिसको हिसाब किताब आता है वह इसे समझ जाएगा। आप इसे इम्तहान का पेपर ही समझ लीजिए। (विधन)

स्पीकर साहब, एक प्वायंट बाबू जी ने एन.आर.ई.पी. प्रोग्रम के बारे में कहा। इन्होंने कहा कि पिछले साल 5.20 करोड़ रूपया खर्च किया गया लेकिन इस साल करन्ट इयर में, केवल 1 करोड़ 78 लाख रूपया ही दिखाया गा है। मैं बाबू जी की इत्तलाह के लिए बतलाना चाहता हूं कि अगर ये सारे बजट ऐस्टिमेंटस को देखते, तमाम के तमाम हिसाब किताब को देखते तो इस तरह की बात न कहते। (विधन) अगर ये पेज 209, हैड 319 के प्लान्ड बजट के ड्राफ्ट को देखते तो इन्हें पता लगता कि 1.78 करोड़ तो हमारा है और 1.78 करोड़ सैन्टर का है। दोनों को मिलाकर यह 3.56 करोड़ बनता है। पिछले साल यह पैसा सैन्ट्रल एड और ज्यादा मिलने की वजह से बढ़ गया था।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर सहाब, अगर इनकी यह बात भी मान ली जाए तो भी यह पैसा पिछले साल के मुकाबले में डेढ़ करोड़ कम है।

चौ. खुरशीद अहमद: स्पीकर साहब, पिछले साल 1.60 करोड़ हमारा था और 1.60 करोड़ रूपया पहली बार गवर्नमेंट आफ इंडिया से आया था लेकिन मिडदयर में जब दुबारा जांच की जाती है उसमें हमें बाकी का फालतू पैसा मिला था। इस साल भी हमें उम्मीद है कि फालतू पैसा हमें मिलेगा। पिछले साल जो

टोटल पैसा 3.20 करोड़ बनता था वह इस बार 3.56 करोड़ है। उम्मीद है बाद में मिलने वाली सैन्ट्रल एड से यह 5.20 करोड़ से भी आगे बढ़ जाएगा।

स्पीकर साहब, एस.वाई.एल. के बारे में यह कहा गया कि इसके लिये सिर्फ 8 करोड़ रूपया रखा है। जनाब आपकी विसातत से मैं इन्हें यह बताना चाहता हूं कि इसके लिए मुख्तलिफ टाइम्ज पर पैसा दिया गया है। जब मेरे बुजुर्ग साथी मूलचन्द जैन जी सरकार में थे तो शायद 2 करोड़ रूपया इन्होंने दिया था। उसे बाद पंजाब सरकार को 10 करोड़ रूपया हमारी तरफ से और गया। 8 करोड़ रूपया यह रखा गया है। इस मद में तकरीबन 22 करोड़ रूपया इस साल की आज की तारीख तक मौजूद है। आप बजट स्पीच में देखेंगे हमने यह कहा है कि ओर भी साधन जुटाने के लिए हम तैयार हैं। अगर हमें दूसरे मदों से भी इसके लिये ऐडजस्टमेंट करनी पड़ी तो करेंगे। यह 22 करोड़ रूपया तो काम शुरू करने के लिए दिया है। पहले दिन ही अगर हमने 50 करोड़ रूपया दे दिया तो फिर ओवर ड्राफ की प्रॉब्लम आएगी। जैसे जैसे डिमांड आती जाएगी वैसे वैसे पैसा दिया जाएगा। मैं हाउस को यकीन दिलाता हूं कि एस.वाई.एल. का काम पैसे की वजह से रूकने नहीं दिया जाएगा। (प्रशंसा) इस वक्त हमारे पास इसका पूरा इंतजाम है और आगे भी पूरा इन्तजाम होगा। इस हालात में मैं यह कहूंगा कि आज की तारीख में जो पैसा गया है वह काफी

है और आयंदा जितना पैसा देना होगा, देंगे और इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे।

स्पीकर साहब, रैवन्यू रिसीट्स के बारे में एक बात और कही गई। इन्होंने कहा कि रैवन्यू रिसीट्स हाइली इनफ्लेटिड है लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हमने तो केवल 15.32 परसेंट इंक्रीज नैक्सट इयर के रैवन्यू रिसीट में बताई है जबकि यह ज्यादा भी हो सकती है। मैं इनको एक ही मद का उदाहरण देता हूँ। ऐक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में ऐक्चुअल रिसीट पिछले साल 11.40 परसेंट हुई थी लेकिन इस साल 31.25 परसेंट ऐक्चुअल रियेलाइजेशन हमने करके गवर्नमेंट को दी है। (प्रशसा) अगले साल के लिए अनुमान रखते हुए हम बड़े कंजरवेटिव रहे हैं लेकिन मैं हाउस को बताना चाहता हूँ कि इस साल की उपलब्धि को हम आयंदा भी मेनटेन करेंगे। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने इनफ्लेट करके दिखाई हो। (विघ्न) अगर इनका यह आर्गुमेंट भी मान लिया जाए कि इनफ्लेशन दिखाई है तो मैं इन्हें कहूंगा कि अगर इनफ्लेशन बढ़ेगा तो हमारी रियेलाइजेशन भी बढ़ेगी, वह भी कम नहीं होगी। उससे भी हमें पैसाबढ़ कर मिलेगा। बजाये इसके कि मैं इन्हें अपनी तरफ से कोर्ट चीज बताऊँ, मैं रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के डौकुमेंट्स से यह साबित करूंगा कि हरियाणा स्टेट के बारे में वे किस डिसिजन पर पहुंचे हुए हैं। स्टेट फाइनेंसिज के ऊपर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने एक कमेटी बनाई उन्होंने डौकुमेंट्स के जरिए तमाम

चीजों को स्टडी किया है। उन्होंने यह भी हिसाब लगाया है कि टैक्सिज की रियेलाइजेशन के बाद कौन कौन सी स्टेट्स के क्या क्या ऐक्चुअलज हैं। तो आज हम टोटल ऐक्चुअलज के हिसाब से रियेलाइजेशन टैक्सिज वगैरह को देखें तब सही बात का पता लगेगा। मैं तमाम चीजों की डिटेल् में नहीं जाना चाहता। एक चीज जो बाबू जी ने बार बार हाउस में दोहराया है कि कनसाइनमेंट टैक्स लगाया होता तो काफी आमदन हो सकती थी लेकिन इसके लगाने में एक कांस्टीच्युशनल दिक्कत है। उस कांस्टीच्युशनल दिक्कत को गवर्नमेंट आफ इण्डिया ही दूर कर सकती है। कांस्टीच्युशन में अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट एक्ट बनायें, तभी कनसाइनमेंट टैक्स लगाया जा सकता है। यह टैक्स गवर्नमेंट आफ इण्डिया की मंजूरी से ही लगाया जा सकता है। यूनिलेटरल फैसला लेकर हरियाणा गवर्नमेंट टैक्स लगायेगी तो लीगल अडचन हो सकती है और हमारी इकोनोमी पर असर पड़ेगा। अगर साथ वाली स्टेट्स की इन्डस्ट्री पर कनसाइनमेंट टैक्स नहीं लगेगा तो हम जो इन्डस्ट्री लगाना चाहते हैं वे दूसरी स्टेट्स में शिफ्ट कर जायेंगे।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, पिछले बजट भाषण के बारे में इन्होंने कहा कि हम कनसाइनमेंट टैक्स लगा रहे हैं और कांस्टीच्युशनल अमेंडमेंट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आज इन्होंने दूसरी स्टेट का मामला उठा दिया कि वे नहीं लगा रहे हैं इसलिये हम नहीं लगा रहे।

चौ. खुरशीद अहमद: स्पीकर साहब, हमारी अकेली स्टेट नहीं लगा सकती। दूसरी स्टेटस लगायेंगी तभी हम लगायेंगे। अगर हम कनसाइनमेंट टैक्स लगा देंगे तो जो हम इन्डस्ट्रीज यहां लगाना चाहते हैं वे दूसरे सूबों में चली जायेंगी। हमारा दूसरी स्टेटस के साथ बड़ा भारी कम्पीटिशन है। एक तरफ यू.पी. है। दूसरी तरफ चन्द फासले पर राजस्थान है। ये इन्डस्ट्री कहीं भी शिफ्ट हो सकती हैं। हमें पार्लियामेंट के एक्ट तक इंतजार करना होगा। पार्लियामेंट के एक्ट के बाद ही स्टेट इसको ऐडोप्ट कर सकती है।

स्पीकर साहब, जैन साहब ने हरियाणा प्लानिंग एन्ड फाइनेशियल परफारमेंस का जिक्र यिका कि किस तरह से 1800 करोड़ का पांच साला प्लान का टारगिट अचीव करेंगे। प्लानिंग के विशय में वक्तन-फवक्तन इन्होंने भी तजुर्बा यिका है चाहे वह थोड़े ही समय के लिये किया हो। फाईव ईयर प्लान के पहले तीन साल में 50 परसैन्ट या 1-2 परसैन्ट कम खर्च होता है जबकि 50 परसैन्ट पिछले दो सालों में खर्च होता है। स्टेटस जो भी प्लान बनाती हैं, सैन्टर को उसकी परफोरमेंस को चैक करने का अख्तियार है। स्पीकर साहब, रिजर्व बैंक आफ इंडिया की ओर से "ए स्टडी आफ दि फाइनेन्स आफ स्टेट गवर्नमेंटस" की किताब 10 फरवरी, 1982 को इशू की गई है। इसमें सभी स्टेटस की परफारमेंस डिस्कस की गई है। यह डाकुमेंट हमारा नहीं है बल्कि गवर्नमेंट आफर इंडिया का रिजर्व बैंक की ओर से इशू किया हुआ

है। मैं इसी डाकुमेंट के आधार पर अपनी स्टेट और दूसरी स्टेटस की परफारमेंस हाउस के सामने रखना चाहता हूँ। हरियाणा की परफारमेंस दूसरी स्टेट के मुकाबले में ज्यादा अच्छी रही है। इस डाकुमेंट में डिवेलपमेंट एक्सपैन्डीचर की फिगरज दी हुई हैं। सन् 1979-80 के अकाउन्टस की स्टडी के आधार पर 22 स्टेटस की एवरेज 73.2 परसेन्ट डिवेलपमेंट एक्सपैन्डीचर की है जबकि हरियाणा की 79.7 परसेन्ट है। सन् 1980-81 की सभी स्टेटस की एवरेज 72.7 परसेन्ट है और हरियाणा की रिवाइज्ड एस्टीमेटस के आधार पर 79.01 परसेन्ट इसी प्रकार से तमाम स्टेट की एवरेज बजट एस्टीमेटस के अनुसार 1981-82 का डिवेलपमेंट एक्सपैन्डीचर 72.4 परसेन्ट था जबकि हरियाणा का 78.06 परसेन्ट था। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि डिवेलपमेंट एक्सपैन्डीचर के मामले में हमारी स्टेट किसी भी साल में दूसरी स्टेटस के मुकाबले में कम नहीं है। इसी किताब की दूसरी स्टेटमेंट पढ़िये। वह प्लान एक्सपैन्डीचर के विषय में है कि दूसरी स्टेटस के मुकाबले टोटल प्लान एक्सपैन्डीचर हमारा कितना हुआ? 22 स्टेटस का प्लान एक्सपैन्डीचर 1979-80 का 33.6 परसेन्ट था जबकि हरियाणा का 37.07 परसेन्ट था। फिर 1980-81 का तमाम स्टेटस का रिवाइज्ड एस्टीमेटस के आधार पर 34.3 परसेन्ट खर्च हुआ जबकि हरियाणा का 40.3 परसेन्ट हुआ। 1981-82 का बजट एस्टीमेटस के अनुसार तमाम स्टेटस का प्लान एक्सपैन्डीचर 36.1 परसेन्ट था जबकि हरियाणा का 43.1 परसेन्ट था। सर, दूसरी स्टेटस के मुकाबले में हरियाणा का प्लान एक्सपैन्डीचर भी ज्यादा है। इसी डाकुमेंट के

आधार पर सन् 1979-80 के अकाउन्ट्स में हरियाणा का प्लान एक्सपैन्डीचर सीर स्टेटस के प्लान एक्सपैन्डीचर का 3.31 परसेन्ट था। फिर सन् 1980-81 में यह परसेन्टेज 3.45 परसेन्ट हो गई। सन् 1981-82 के एप्रूव्ड आउटलेज के अनुसार 3.53 परसेन्ट हो गई। जब इन सारी फिगरज को कम्पेअर करते हैं तो उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि हमारा प्रान्त तमाम चीजों को देखते हुए प्लानिंग में और किसी दूसरी चीज में दूसरी स्टेटस के मुकाबले कम कम नहीं हैं। हमारी परफोरमेंस आल इण्डिया एवरेज के हिसाब से प्लान एक्सपैन्डीचर में ज्यादा है जबकि हमारी पापुलेशन का लैवल 1.91 परसेन्ट बनता है। उसके हिसाब से देखा जाये तो हमारी परफोर्मेंस सारे हिन्दुस्तान की एवरेज से बहुत ज्यादा है यानी दुगुनी तीगुनी जाकर पड़ती है। बाबू जी ने कई चीजों के बारे में जो खासतौर पर एतराज यिका था वह मैंने आपके सामने रख दी हैं कि हमारी सरकार क्या कुछ कर रही है। बातें तो और भी बहुत सारी कही गयी थी लेकिन उसमें एक बात एम्पलायमेंट के बारे में भी कही गयी थी। उसके बारे में सरकार पहले से कई तरह के कदम उठा रही है। चौ. सुरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि बेकारी बहुत ज्यादा है लेकिन पता नहीं वे कहां से फिगरज लाये हैं। हमारे पास 31 दिसम्बर, 1981 तक टोटल रजिस्ट्रेशन 3.77 लाख हैं जबकि चौ. सुरेन्द्र सिंह जी ने 5.70 लाख बताया है। मैं उन्हें कहूंगा कि वे दोबारा चैक कर लें हमारी पापुलेशन जिस हिसाब से बढ़ी है उसी हिसाब से एम्पलायमेंट एक्सचेंजिज में नाम रजिस्टर्ड हुए हैं। हमें खुशी है कि पोहलू

साहब भी हमारी बात को ऐप्रीशिएट कर रहे हैं। बहुत सी छोटी छोटी बातों को भी यहां पर उछाला गया है। कोआप्रेसन डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट के बारे में कहा गया। इसका जवाब कोआप्रेसन मिनिस्टर साहब ने दे दिया है। सब साथी जानते हैं ओर जिन्होंने कोआप्रेटिव मिनिस्टर के इलैक्शन लड़े हैं यह बैकस के डायरेक्टर रहे हैं, उनको पता है कि बोर्ड आफ डायरेक्टर ही सारा फैसला करता है। हमारी तरफ से एक एम.डी. बैठता है या एकाध अफसर और जाता है। सारा काम स्वयं बोर्ड आफर डायरेक्टर ही करता है। बोर्ड ही भर्ती करता है। श्री रणसिंह मान भी बोर्ड आफ डायरेक्टर के चेयरमैन रहे हैं। इन्होंने भी भर्ती की थी। इनके बोर्ड पर सरकार का कितना अंकुश था? गंगाराम जी भी हाउस में नहीं हैं, उनको भी पता होगा कि भर्ती करते वक्त सरकार का कितना अंकुश था। हां, अगर भर्ती करने में चेयरमैन या बोर्ड आफ डायरेक्टरर्ज कोई गड़बड़ी करता है, तो सरकार उसकी इन्क्वायरी करवा सकती है। (व्यवधान व शोर)

श्री रण सिंह मान: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, वित्त मंत्री जी ने जो कुद यहां पर कहा है, मैं उसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि प्रैक्टिकली सब परपजिज के लिये सरकार का उसके ऊपर दखल होता है। (व्यवधान व शोर)

चौ. खुरशीद अहमद: मैं मानता हूं कि पूरा दखल होता है लेकिन तब दखल होगा जब कोई आदमी वहां पर गड़बड़ी कर

लेगा। तो ही उसकी हम इन्क्वायरी शुरू करवा सकते हैं। सरकार किसी भी मैलाफाइडी काम के बारे में आटोनौमस बोर्डज को डायरैक्शन दे सकता है। मैं यह नहीं समझता कि अगर कोई बोर्ड का बोनाफाइडी एक्शन होगा, उसके बारे में भी सरकार कोई कार्यवाही करेगी। सरकार ने बोर्डज को यह पावर्ज दे रखी है कि वह लोगों के साथ न्याय करें और अगर कोई बोर्ड न्याय करने की बजाये, कोई गलती करता है या गड़बड़ी करता है तो हम उनके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। हमने अब तक का रिकार्ड देखा है। हमने बहुत से आफिसरों को नोटिस भी दिये हुए हैं और एक्शन भी लिया जायेगा। ऐसा तभी किया जाता है अगर कोई एक्शन मैलाफाइडी हो। अगर उनका कोठ एक्शन बोनाफाइडी हो, तो सरकार उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। एक बात का मुझे बड़ा अफसोस है कि बाबू मूल चन्द जैन जी ने अपने मुंह से ठाकुरवाद और विश्नोईवाद की बात कहीं। (व्यवधान व शोर)

श्री मूल चन्द जैन: आप कमीशन क्यों नहीं बिठाते।

चौ. खुरशीद अहमद: कमीशन कौन से बोर्ड के खिलाफ बिठाये।

श्री सुरेन्द्र सिंह: सारे बोर्डों और कार्पोरेशन्ज पर कमीशन बिठाओ।

चौ. खुरशीद अहमद: मैं यह समझता हूँ कि इनके ऊपर तो सोहबत का असर है (व्यवधान व शोर) मैं सारी की सारी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ (व्यवधान व शोर)

चौ. संत कंवर: हम तो यह कहते हैं कि अगर आपने जाति-पाति न फैलाई हो, ठाकुरवाद बिश्नोईवाद या पैसावाद न फैलाया हो तो आप पहले कोआप्रेसन डिपार्टमेंट पर ही कमीशन बिठा दो। खुल्लम खुल्ला इस बात की इन्क्वायरी हो जाये तो तथ्य सामने आ जायेंगे।

डा. मंगल सैन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर सहाब, जब एक मामले में अपोजीशन की तरफ से मांग होती है, ट्रेजरी बेंचिज के एक आनरेबल मैम्बर भी मांग करते हैं और वजीर सहाब भी तैयार हैं तो कमीशन बिठाने में क्या हर्ज है। (व्यवधान व शोर)

चौ. खुरशीद अहमद: स्पीकर साहब, संत कंवर जी तो इस बात में बड़े माहिर हैं कि किसी चीज का किस तरह से मुख्तसिर में जवाब दिया जा सकता है। जब ये जाट हाई स्कूल, रोहतक में पढ़ते थे तो यह उस पेज को किताब से फाड़ दिया करते थे जो मास्टर पढ़ा चुकता था ताकि मास्टर कहीं उसमें से कुछ पूछ न बैठे। जहां तक बाबू मूल चन्द जैन जी का सम्बन्ध है, उनकी तो हवाई बातें हैं। (व्यवधान व शोर) बाबू मूल चन्द जैन जी ने एक वर्कचाजर्ड एम्पलाईज के बारे में जिक्र किया। उन्होंने

यह भी कहा कि वर्क चार्ज्ड एम्पलाईज के बारे में गवर्नमेंट की नीति साफ नहीं है। (व्यवधान व शोर)

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, मंत्री जी बेरोजगारी के बारे में सिर्फ आंकड़े देकर ही चुप हो गये, हमारी असली बातों का तो जवाब दें।

चौ. खुरशीद अहमद: उसका हल भी बात दूंगा। आप सब रखिये। स्पीकर साहब, वर्क चार्ज्ड एम्पलाईज के बारे में जो इन्होंने कहा है, उस बारे में हमारा कहना यह है कि हम इस बारे में पहले ही फैसला कर चुके हैं कि जिनकी सर्विस 31 दिसम्बर, 1981 को 4 साल की हो जायेगी उनकी रैगुलेराईज कर दिया जायेगा और पे-कमीशन ने जो हर आदमी के लिये तनख्वाह रिकमेंड की है, आटोमैटिकली उसके लिये यह एन्टार्टल होंगे। एक बात मैं संत कंवर जी से और कहूंगा कि वे बजट फाड़ने के अलावा भी कुछ सीख लें। संत कंवर जी यही नहीं कि आपने बाबू मूल चन्द जैन जी का बजट फाड़ा, आप हमारा भी बजट फाड़ सकते हो, लेकिन मैं यह कहता हूँ कि इसके अलावा भी कुछ अच्छी बातें सीख लें। इन सब दिक्कतों के बावजूद भी हमने जनता को हर तरह से रिलीफ देने की कोशिश की है। जितनी चीजें हम उनके लिये कर सकते थे, की हैं। तमाम की तमाम चीजें हमने उनको मुहैया की हैं। यह हमारे पूरे साल की परफोरमेंटस है।

वधवा साहब ने एक बहुत बड़ा गिला हमसे किया कि हरियाणा गवर्नमेंट ने 80 परसेंट बजट एडमिनिस्ट्रेशन पर लगाया है और 20 प्रतिशत बजट डिवैल्पमेंटल एक्टिविटीज पर लगाया है। जनाब, अब मैं संत कंवर जी की तरह से इनको क्या कहूं। किताबें तो ये बहुत पढ़ते हैं लेनिक उल्टी पड़ गये हैं। हकीकत यह है कि हरियाणा की इस बात को रिजर्व बैंक ने भी माना है कि 78 प्रतिशत हमारा खर्चा डिवैल्पमेंटल एक्टिविटीज पर हुआ है। (व्यवधान व शोर) स्पीकर साहब मैं आपको यह बता सकात हूं कि हमारे बजट का 78 प्रतिशत डिवैल्पमेंटल एक्टिविटीज पर खर्च हुआ है और 20 प्रतिशत नान-डिवैल्पमेंटल एक्टिविटीज पर खर्च हुआ है। इस चीज को देखते हुए आज बजट की स्थिति यह है कि डिवैल्पमेंट के लिए हम टॉप प्रायोरिटी पर खर्च कर रहे हैं और बाकी खर्च उसके बाद आते हैं। इसके बाद चौ. राम लाल वधवा जी यह कहने लग कि पब्लिक डैट बहुत ज्यादा हो गया है।

चौ. राम लाल वधवा: यह तो आपके आंकड़े दिये हैं, यह कौन सी किताब में दिये हुए हैं।

चौ. खुरशीद अहमद: यह हर किताब में दिये हुए हैं हर किताब से बात साबित हो जाएगी कि 20 प्रतिशत जो खर्चा आपने डिवैल्पमेंट के कामों पर बताया है, वह किसी भी किताब में नहीं है बल्कि वह आपके अपने दिमाग की देन है। मैं पब्लिक डैटस के बारे में चौ. राम लाल वधवा जी ने एतराज उठाया कि पब्लिक डैट बहुत ज्यादा हो गया। पब्लिक डैट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया

जाए, यह तो मुमकिन नहीं है। स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से हाउस के सामने एक बात रखना चाहूंगा कि किसी भी स्टेट की डिवैल्पमेंट के काम पब्लिक डैट के बगैर नहीं होते। यह फार्मूला सारी स्टेट में आप्रोट करता है। वैसे चौ. राम लाल वधवा जी तो प्लानिंग बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन भी रहे हैं। नैशनल डिवैल्पमेंट काँसिल की जब भी मीटिंग होती है तो आम तौर पर डिप्टी चेयरमैन आफ दी प्लानिंग बोर्ड हर मीटिंग को अटैण्ड करता है। उन्होंने भी एक दो मीटिंगें अटेंड की होगी। उस में हर स्टेट इस चीज को रखती है कि हमें पलां पलां चीज के लिए इतना लोन चाहिए। पब्लिक लोन जो गवर्नमेंट लेती है, उसको गवर्नमेंट आफ इंडिया मौनिटर करती है। वह स्टेट गवर्नमेंट को इस आधार पर इजाजत देती है कि उसकी रिपेईंग कैपेसिटी कितनी है। हरेक गवर्नमेंट अपना काम चलाने के लिए पब्लिक डैट की इजाजत गवर्नमेंट आफ इंडिया से लेती है। गवर्नमेंट आफ इंडिया को और रिजर्व बैंक को भरोसा है कि हमें पब्लिक डैट की इजाजत मिलती है और वह इजाजत लेकर हम अपनी गवर्नमेंट के सारे डिवैल्पमेंट के कामों को चलाते हैं। अगर हम ऐसा न करें तो हमें टैक्स लगाने पड़ेंगे और गरीब आदमियों की गर्दन दबोचनी पड़ेगी। हम यह जानते हैं कि हमारे प्रदेश के लोग गरीब हैं, इसलिये हम यह चाहते हैं कि उस पर टैक्स न ही लगाना पड़े तो ठीक है

(व्यवधान व शोर) हमारे साथी राव बंसी सिंह ने बड़े कस्ट्रेक्टिव सुजैशन्ज दिये हैं। उन्होंने बहुत सी बातें कहीं। एक

बात उन्होंने यह भी कही और मेवात में बैकवर्ड एरिया के बारे में बहुत वकालत की कि जो एरिया होडल से लेकर (व्यवधान व शोर)

चौ. राम लाल वधवा: पर कैपिटा इन्कम की बात भी कह दो।

चौ. खुरशीद अहमद: पर कैपिटा इन्कम के करों में एक बात चौ. राम लाल वधवा जी ने कही कि हमारे बजट एट ए ग्लान्स में जो यह फिगर दी जाती थीं, वह इस साल नहीं आयीं। वह इसलिये नहीं आयी क्योंकि गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने सारी स्टेटस को यह हिदायत की कि पर कैपिटा इन्कम का अब तक कौलकुलेशन के लिये जो बेस ईयर था, वह 1960-61 रहा है इस साल वहां से यह आया है कि 1970-71 को बेस ईयर मानकर फ़ैसला करना पड़ेगा। स्पीकर साहब, सारे आंकड़े इक्टठे करने हैं। ऐसे तो कहा नहीं जा सकता कि जैसे इन्होंने कह दिया कि केवल बीस परसेन्ट डिवैल्पमेंट के काम पर खर्च किया जाता है। 1970-71 के आंकड़े गवर्नमेंट आफ इण्डिया से लेने हैं और अपने यहां पर भी वैरिफाई करने हैं। पापूलेशन भी देखनी है (शोर व व्यवधान) इस बेस को मानते हुए हमारे यहां स्टेटिस्टिक्स कलैक्ट करने का काम तकरीबन पूरा हो चुका है जब हमारे पा आल इण्डिया स्टेटिस्टिक्स आ जाएगा तो हम गजट नोटिफिकेशन भी कर देंगे और आपको भिजवा देंगे अगर 1960-61 के बेस पर देना होता तो नई फिगर कलैक्ट नहीं करनी पड़ती लेकिन अब बेस भी बदलना पड़ गया है इसलिये इस काम में कुछ देर लग सकती है।

We will have to go into deeper calculations which may be presented to Mr. Wadhwa if he can follow them. राव बंसी सिंह ने दो तीन डिमांडज अपने एरिया के बारे में रखी है। स्पीकर साहब, मैं हाउस को बताना चाहता हूँ कि सरकार उन पर गौर कर रही है। इन्होंने मिनी सीमेन्ट फ़ैक्टरी के बारे में कहा। उस बारे में रिसर्च कर ली जाएगी और जब कोई नतीजा उसका आएगा और अगर वह रैमूनरेटिव स्कीम होगी तो गवर्नमेंट उसको एग्जामिन करा कर जो भी उचित कार्यवाही होगी वह कराएगी।

स्पीकर साहब, इन्होंने अपने एरिया के बारे में कहा कि वह बैकवर्ड एरिया है और साथ उसके लिये एक डिवैल्पमेंट बोर्ड की स्थापना की मांग की है। स्पीकर साहब, उसके लिए एक कमेटी बन गई है और वह देखेगी कि उस इलाके के लिए क्या करना है। गवर्नमेंट जो नई स्कीम वहां के लिए जुटा सकेगी वह जुटाएगी।

स्पीकर साहब, हमारे सामने एक मसला जो बारबार आ रहा है और जिसको स्वामी जी ने उठाया है उसके बारे में, मैं कहना चाहता हूँ। स्वामी जी ने कहा कि बजट के साथ वह इंफरमेशन नहीं लगी जिससे पता लगे कि हरिजनों को क्लास बन, टू, थ्री और फोर में कितनी नौकरियां दी गई हैं। मैं स्वामी जी से कहना चाहता हूँ कि अगर वह पेज 550 पर देखे तो उनको यह सारी इंफरमेशन मिल जाएगी जिसको वह चाहते हैं

स्वामी अग्निवेश: स्पीकर साहब, पेज 550 पर जो आंकड़े दिए हैं, वे तो 1980 के हैं। मार्च 1981 तक के आंकड़े नहीं दिए हैं। मैं खुरशीद जी से कहूंगा कि वे भी देख लें।

चौ. खुरशीद अहमद: उसके बाद के आंकड़े अगले साल आएंगे। (शोर एवं व्यवधान)।

Mr. Speaker: This statistical return has nothing to do with the Budget.

स्वामी अग्निवेश: अध्यक्ष महोदय, वे तो पुरानी फिगरज बता रहे हैं (शोर एवं व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष: वे फिगरज गलत नहीं बता रहे हैं। 1980 तक की फिगरज हैं और 1981 तक की फिगरज कम्पाइल नहीं की हैं।

चौ. खुरशीद अहमद: स्वामी जी आप 1981 की फिगर अपने साल देख लेना। स्पीकर साहब, स्वामी जी ने जनरेलाइज किया और कहा कि हरियाणा में बौंडिड लेबर है। स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार का इस मामले में यह स्टैन्ड रहा है कि हरियाणा में बौंडिड लेबर नहीं है और उसके लिए कमेटी भी बनी हुई है। विजिलेंस कमेटी के बारे में कहा गया कि वह फलां तारीख को बनी। मैं कहना चाहता हूँ कि यह एक हकीकत है कि एक कमेटी अवश्य है फिर वह चाहे किसी भी तारीख को बनी हो। स्पीकर साहब, कमेटी को एक केस के बारे में स्पेसिफिकली बताया कि लाडवा के भट्टे पर मजदूर गए और फिर वहां से वापिस चले

गए। स्पीकर साहब, कुछ लेबर तो नवम्बर, 1981 में आई और कुछ लेबर दिसम्बर, 1981 में आई वह 16 फरवरी, 1982 की शाम को वापिस चली गई और दूसरी 24-25 फरवरी को वापिस चली गई। इन दो चार महीने में इस लेबर को कैसे बाँडड लेकर कहा जा सकता है। स्पीकर साहब, हरियाणा में बाहर से जो लेबर आती है वह पहले ही अपने राशन पानी के लिए थोड़ी बहुत पैसा लेती है तभी वह अपने घर को छोड़कर आती है भट्टे आमतौर पर जंगल में होते हैं। इन भट्टों में काम करने के लिए जो भी आएगा वह कुछ न कुछ एडवान्स लेकर ही आएगा। यह कोई शहर की मजदूरी तो है नहीं कि सुबह से शाम तक काम करने के बाद वह शाम को मजदूरी लेगा। अगर किसी को जंगल में लेकर जाएंगे तो जरूर ही वह एडवांस लेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये मजदूर वालन्टरी आते हैं कोई जबरदस्ती तो उनको लाता नहीं है फिर मेरी समझ में नहीं आता कि सिर्फ एडवान्स ले लेने से कोई बन्धुता मजदूर कैसे बन गया। लेबर मिनिस्टर ने बताया था कि हालत यह है कि अगर किसी ने दो दिन का एडवान्स ले लिया तो उसको भी कह दिया कि यह बन्धुवा मजदूर है। ऐसी परापोजीशन कि दो दिन का एडवान्स ले लेने से बाँडड लेबर हो जाए, मेरी समझ में स्पीकर साहब, यह बात नहीं आती। अगर ऐसी बात होती रही तो फिर भट्टों का काम तो सारा सस्पैन्ड करना पड़ेगा

..

स्वामी अग्निवेश: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ओर मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की रिपोर्ट भी है कि वे बन्धुवा मजदूर है इनको सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की इज्जत करनी चाहिए चाहे सुप्रीम कोर्ट के अन्तरिम आर्डर हैं (शोर एवं व्यवधान)।

चौ. खुरशीद अहमद: सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फाइनल जजमेंट मेरे सामने होता तो माना जा सकता था (शोर एवं व्यवधान)।

स्वामी अग्निवेश: अन्तरिम आर्डर हैं।

चौ. खुरशीद अहमद: अगर सुप्रीम कोर्ट में यह केस चल रहा है ओर इसी बात पर चल रहा है जिनका स्वामी जी ने जिक्र यिका ओर इनको सुप्रीम कोर्ट के हर आर्डर का पता है सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनको यह भी पता है कि जबानी क्या आर्डर है ऐसी हालत में इनको हाउस के जिक्र नहीं करना चाहिए था। जब इन्होंने जिक्र कर ही दिया तो मैं उस हद तक ही जवाब दूंगा जो सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक नहीं रखता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अन्तरिम आर्डर में कहा है “the writ petition is adjourned to 2nd April, 1982” अभी तो यह ऐवीडेन्ट नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बौंडिड लेबर माना भी है या नहीं। मैं तो उसी हद तक जवाब दूंगा जिस हद तक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है

स्वामी अग्निवेश: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, ये हाउस को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास 5 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये हाउस को मिसलीड करने की कोशिश न करें। इनके खिलाफ प्रिविलिज बनता है। (शोर एवं व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफर आर्डर नहीं है। अगर प्रिविलिज बनता है(शोर एवं व्यवधान)।

स्वामी अग्निवेश: अध्यक्ष महोदय, बॉडिड लेबर रिलीज की गई है (शोर एवं व्यवधान) यह गलत कह रहे हैं। इनके खिलाफ प्रिविलिज बनता है

श्री अध्यक्ष: अगर प्रिविलिज बनता है तो बनाकर दीजिए I will examine it.

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर चाहे अन्तरिम हो या फाइनल हो, क्या अन्तरिम आर्डर को इनको औनर नहीं करना चाहिए?

13.00 बजे

श्री अध्यक्ष: जो अन्तरिम आर्डर इन्होंने पाया है I have neither read the interim order of the Supreme Court nor it has been put up to me. I will be the last person to give ruling on Supreme Court Order. (interruptions by Dr. Mangal Sein) This is n point of order please.

चौ. खुरशीद अहमद: स्पीकर साहब, जब यह केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो इनको यहां पर नहीं लाना चाहिए था। (शोर एवं व्यवधान)।

स्वामी अग्निवेश: अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट में कोई ओर मसला था (व्यवधान)

Ch. Khurshid Ahmed: He is trying to mislead the House. He is misleading. (interruptions)

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अगर कोई मसला सुप्रीम कोर्ट में है और वह सब-जूडिस है तो उसका जिक्र इस हाउस में कतई नहीं अना चाहिये।

चौ. खुरशीद अहमद: स्पीकर साहब, स्वामी जी ने यहां गुलाबों नामक एक लड़की का जिक्र किया कि उसकी पुलिस की मार के कारण डैथ हो गयी लेकिन जो पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक तो यह है "No injuries were found, death was caused due to T.B." स्पीकर साहब, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि टी.बी. के मरीज की मौत एक दिन में नहीं हो जाती। उन्होंने पिछले दो महीनों से हमारे हरियाणा की धरती पर कदम रखा था और वह कई सालों से बीमार आ रही थी जिसके कारण उसकी डैथ हो गई। It is a slow consuming death.

स्वामी अग्निवेश: अध्यक्ष महोदय, इनसे पूछा जाए कि उसकी जांच के लिये क्या प्रबन्ध किया गया था? (शोर एवं व्यवधान)।

Mr. Speaker: I would request the Hon. Minister not to devote any time on a subject which has not relevancy to the Budget before the House.

चौ. खुरशीद अहमद: इसी वजह से स्पीकर साहब, मैं इस बात का जिक्र करना चाहता था कि बॉन्डिड लेबर की प्रोब्लम हरियाणा के अन्दर एक ड्रामे के सिवाये और कुछ नहीं है और इन सारी बातों को हरियाणा के बाहर भी ड्रामाटाइज किया गया है। स्पीकर साहब, अगर इस तरह का वाक्या था तो पहले इस मामले की शिकायत डी.एम. के पास जाती ताकि हकीकत देखी जा सकते लेकिन जिस तरीके से ऐसी बात को उछाला गया है, यह कोई उचित बात नहीं है।

स्पीकर साहब, इसी तरह से एक और बात वधवा साहब ने यहां पर कही है और सरकार की डिवेलपमेंट के कामों पर बडी नुक्ताचीनी की लेकिन उन्होंने कोई ऐसी तजवीज नहीं बतायी कि जिसकी वजह से स्टेट के रिसोर्सिज बढ़ सकते हो, जिससे न ही टैक्स लगाना पड़े और नही सरकार को कज्र लेना पड़े। हालांकि वधवा साहब प्लानिंग बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन भी रहे हैं। उन्हें कोई ऐसा तजवीज सरकार को बतानी चाहिये थी कि जिससे कि स्टेट की इन्कम बढ़े और डिवेलपमेंट के काम भी चलते रहें। इसी

तरह से चौ. रिजक राम जी ने कई एक बातें कही और बार बार एक बात को दोहरा यिदा कि सरकार का कितना एक्सपैन्डीचर प्लान पर और कितना नान-प्लान पर हुआ। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा तकरीबन दुगुना हो गया। इसलिये मैं उनकी जानकारी के लिये यह बताना अपना फर्ज समझता हूं कि दो सालों के अन्दर अन्दर 80 परसेन्ट के करीब हमारा डिवलपमेंट पर खर्च हुआ, और दूसरी तरफ 20 से 22 परसेन्ट के दरिम्यान हमारी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिये खर्च किया जाता है इसके साथ ही चौधरी साहब ने यह कहा कि सरकार को ईडा से लोन लेना चाहिये था, वर्ल्ड बैंक से क्यों लिया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम बाहर से जो लोन लेते हैं चाहे वह ईडा से हो, चाहे वर्ल्ड बैंक से हो, उस पर रेट आफ इंट्रस्ट यूनीफार्म होता है। सैन्टर्लगवर्नमेंट भी वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है और उसी रेट आफ इंट्रैस्ट से हमारे ऊपर इंट्रस्ट लगता है। मैं इनकी जानकारी के लिये यह भी बता देना चाहता हूं कि हम चाहे ईडा से लोन लें, चाहे वर्ल्ड बैंक से लोन लें, हम भारत सरकार द्वारा यह लोन लेते हैं।

इसके बाद हमारे माननीय बुजुर्ग चौ. हुड्डा साहब ने बोलते हुए कई बातों का जिक्र इस हाउस में किया। वे बेसिक चीजों पर ज्यादा जोर दे रहे थे उन्होंने बड़े ऊंचे विचार सदन के सामने रखे हैं जिसकी कि हमारे जैसा आदमी तो समझ नहीं सका। हां एक बात जो उन्होंने ड्रेनों के बारे में कही, वह जरूर

हमारी समझ में आ गयी यह तो वह बात हुई कि लिखे ईसा और उसको पढ़े खुदा इसी तरह कहे हुड्डा और समझे खुदा (शोर एवं व्यवधान)।

चौ. संत कंवर: स्पीकर साहब, यह बहुत बुरी बात है कि हमारे एक माननीय सदस्य, जोकि इस समय हाउस में उपस्थित भी नहीं हैं, के बारे में ऐसा कहा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: संत कंवर जी, वे तो हुड्डा साहब की तारीफ कर रहे हैं।

चौ. खुरशीद अहमद: स्पीकर साहब, मैंने तो उनकी तारीफ ही है कि वे इतनी ऊंची फिलौसफी की बातें यहां पर करते हैं कि चौ. संत कंवर की समझ में आ जाएं यह तो अगल बात है लेकिन हमारे जैसे आर्डीनरी दिमाग में वह बातें नहीं आई हैं, न ही आ सकती है (हंसी)। हुड्डा साहब, तो भारतवर्ष से शुरू होकर एकदम चाईना पहुंच जाते हैं। कुरानशरीफ से एकदम आसमान में आ गये थे (शोर) लेकिन हमारे दिमाग में तो कुछ नहीं आया। जो उनकी ड्रेनों के सम्बन्ध में बात थी, वह जरूर हमारी और हमारे इस सदन के दूसरे सदस्यों की समझ में आ गयी है अगर हुड्डा साहब, यहां पर विराजमान होते तो वे सरकार को पालिसी को जरूर ही ऐप्रीशिएट करते – (शोर एवं व्यवधान)

स्पीकर साहब, हमारे आदरणीय बाबू मूलचन्द जैन जी ने भी अपने भाषण में बोलते हुए काह कि ट्रिब्यून जो अखबार है,

वह बहुत बड़ा अखबार है, उसाके सरकार ने एडवरटाईजमेंट देने कन्द कर दिये, उस अखबार के साथ डिसक्रिमीनेशन बर्ती गई है। स्पीकर साहब, मैं इस बार में आंकड़े आपके सामने यहां पर रखना चाहता हूं कि इंगलिश डेली को, जिनमें ट्रिब्यून अखबार भी है, उसको हमने 12 लाख 2 हजार 992 रूपये की एडवरटाईजमेंटस दी हैं जबकि बाकी टोटल अखबारों को 15 लाख 25 हजार 607 रूपये की एडवरटाईजमेंटस दी हैं अगर बाबू जी इसी को ही डिसक्रिमीनेशन कहते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि अकेले ट्रिब्यून को 12 लाख 2 हजार 992 और बाकी के सारे अखबारों को 15 लाख 25 हजार 607 रूपये का एडवरटाईजमेंट दी गई हैं। बाबू जी खुद ही फिगर्ज को देखकर इस बात का अन्दाजा लगा सकते हैं। यह फिगर्ज अप्रैल, 1981 से फरवरी 1982 तक की हैं।

Sh. Mool Chand Jain: Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister is bagging the question.

जब से अखबार में प्लेटस की लिस्ट छापी गयी है तब से सरकार ने ट्रिब्यून अखबार के साथ इस तरह का एक्शन लेना शुरू किया है।

चौ. खुरशीद अहमद: जो लिस्ट मैंने बनायी है, वह जनवरी में ही छप चुकी है। आज अगर चण्डीगढ़ में एक ही पेपर की मानोपली हो तो हम माल लेते कि हमने उसी पेपर्ज को एडवरटाईजमेंट दे दिया लेकिन यहां चण्डीगढ़ से तो कई ओर नेशनल पेपर्ज भी निकलते हैं, दूसरे भी निकलते हैं तो उन सब

को इग्नोर करके हम एक ही अखबार को पैट्रोनार्ज करें तो यह बात स्टेट पालिसी के विरुद्ध होगी।

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, क्या यह बात सच नहीं है कि * * * *

श्री अध्यक्ष: ऐसी कोई बात रिकार्ड न की जाए।

चौ. खुरशीद अहमद: स्पीकर साहब, जिस पेपर की ऐप्रोच इतनी है जो हमारी चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर (शोर एवं व्यवधान) आज के अखबार में उसने एक खबर छाप रखी है (शोर एवं व्यवधान)

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, आप एफ.एम. साहब को रोकिये। उन्हें किसी अखबार के खिलाफ यह नहीं कहना चाहिए कि वह अखबार तोड़ मरोड़ कर खबरे देता है जबकि वे अपने आपको यहां पर डिफेन्ड नहीं कर सकता। उस अखबार ने इनकी सही खबरों को शाया किया है तो इसलिये इस सरकार को परेशानी हुई है (शोर एवं व्यवधान) इनको किसी एक पेपर के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए।

Ch. Khurshid Ahmed: The hon. Member himself pleaded for that paper and I am only replying to that.

स्पीकर साहब, आज इस अखबार में एक खबर छपी है, उस बारे में, मैं बताना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट में रिट तो दायर हुई हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ ओर उसमें छाप रखा है हुड्डा के

खिलाफ। कितना बायसड पेपर है यह स्पीकर साहब? इस तरह से पेट्रनाइज करके उस पेपर पर डा. मंगल सैन अपना ही रंग चढ़ाते जा रहे हैं (शोर)

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय बहस का जवाब दें, यह सबजैक्ट अन्डर डिस्कशन नहीं है।

चौ. खुरशीद अहमद: स्पीकर साहब, मैं जनाब से बता रहा था कि वह कितना बायसड पेपर है।

चौ. संत कंवर: स्पीकर साहब, इसी ट्रिब्यून अखबार ने आज गंगा राम जी के बारे में एक बात लिखी है। फाइनेंस मिनिस्टर यह ठीक कह रहे हैं कि वह ऐसी वैसी बातें लिखता है।

चौ. खुरशीद अहमद: जनाब, हमारे साथी चौ. जगजीत सिंह पोहलू ने बजट की बहुत सी प्रोपोजल्ज के बारे में कहा कि गैप ज्यादा है, वह तो हम मीट कर लेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि यह इलैक्शन बजट है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इलैक्शन के बावजूद भी यह डिवैल्पमेंट का बजट है। पोहलू साहब यह मानेंगे कि कैथल में कोयल के नाम से उनकी सुविधा के लिए हम टूरिस्ट कम्पलैक्स बना रहे हैं। इसके बाद एक सवाल मेरे साथी कैप्टन मांगे राम जी ने फौजियों के बारे में उठाया।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: अगर हाउस सहमत हो तो सदन की बैठक का समय दस मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए?

आवाजें: ठीक है जी बढ़ा दो।

श्री अध्यक्ष: बैठक का समय दस मिनट के लिये बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1982-83 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

चौ. खरशीद अहमद: जनाब, मैं कैप्टन साहब की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जो ऐक्स सर्विसमैन 70 साल के ऊपर की उम्र के हैं उनको हमारी तरफ से 50 रू. महीना फाईनैशियल असिस्टेंस दी जाती है लेकिन हम यह समझते हैं कि यह राशि कम है इसलिये हमने 1.12.81 को गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखा कि यह राशि 50 रू. से बढ़ाकर 100 रू. कर दे ताकि हम हरियाणा के सैनिक बोर्ड की रिलीफ कमेटी की तरफ से उनको यह राशि दे सकें। जिस वक्त भी यह मंजूरी आ जायेगी, हम उसी वक्त ऐसा कर देंगे। हम तो यह चाहते हैं कि हमारे फौजियों को आखिर तक बढ़िया से बढ़िया सहूलियतें मिलें। हरियाणा का सैनिक बोर्ड फौजियों को जितनी सहूलियत देता है उसको देखकर गवर्नमेंट आफ इंडिया के रिप्रजेंटेटिवज ने सैनिक बोर्ड की मीटिंग में हमारी बहुत प्रशंसा की है that ex-servicemen are being looked after better than in any other State. कैप्टन

मांगे राम जी न एक यह भी मांग की कि फौजियों के लिये डिफेंस कालोनीज बनाई जाएं। जहां पर ऐसी ज्यादा मांग है हमने फौजियों के लिए अलग से कलौनीयां बनाई हैं। जैसे गुड़गांव में हमने उनके लिए अलग से कालोनी बनाई है ओर इसका एक सैक्टर अब फरीदाबाद में बनाने जा रहे हैं। रोहतक के फौजियों ने हमसे कहा था कि हम कालोनी को खुद डिवैल्प करेंगे लेकिन शायद उनसे बात नहीं बनेगी। अगर वे हमें इसके लिए कहेंगे तो हम रोहतक में भी गवर्नमेंट की तरफ से उनको डिफेंस कालोनी बना कर देंगे। हमें अपने फौजियों पर मान है जिन्होंने अपने जान हथेली पर रखकर हमेशा हमारे मुल्क की हिफाजत की है। रेवाड़ी के अन्दर भी ऐसी कालोनी अन्डर प्रोग्रैस है।

जनाब, उसके बाद जो और बातें हमारे सामने बाकी साथियों ने रखीं, मैं उनके बारे में भी बताना चाहता हूँ। श्री देवी दास का प्वायंट था कि जो मंडियां दिल्ली के नजदीक पड़ती हैं, वहां से माल निकल कर दिल्ली चला जाता है और मंडी वालों को इससे नुकसान होता है। दूसरी तरफ यह बात आई कि गेहूं बाहर नहीं जाने दिया जाता। मैं यह बताना चाहता हूँ कि गेहूं बाहर जाने पर आज कोई पाबन्दी नहीं है। देवीदास जी और संत कंवर जी आपस में फ़ैसला करके बता दें कि क्या ठीक है और क्या गलत है। उसके बाद गया लाल जी ने बोलते हुए हमारे सामने कुछ मुश्किलें रखीं कि आर.आई. इंडस्ट्री के लिये बैंको से लोन लेने के लिए मुश्किल पड़ती है और दूसरे लोन भी कम मिलता है

एक उन्होंने यह भी कहा कि रूरल सबसिडी कम रखी गई हैं। उन्होंने कहा था कि केवल 10 लाख रू. इस काम के लिए रखे गये हैं। शायद उनको फिगर देखने में गलती हुई है। वह रकम 27 लाख रू. के करीब है, जो इस काम के लिये बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इस रकम को यूटीलाईज करने का सवाल भी गया लाल जी ने उठाया कि बैंकों में इस तरह की काफी दिक्कत आती है। बैंकों के साथ हमारी तालमेल कमेटी की मीटिंग हुई थी और मुख्यमंत्री जी द्वारा इम्प्रेस करवाने के बाद उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि जितनी भी एप्लीकेशज पेंडिंग पड़ी हैं उनको इस साल के अन्त तक सार्ट आडट कर देंगे। जिनकी एप्लीकेशज मुकम्मल नहीं हैं उनको मुकम्मल करवा देंगे। जनाब, जहां दूसरे और मसलों का ताल्लुक है उनमें दवाइयों और बाजरे वगैरह की जो तमाम खरीदों फरोख्त होती है उसके बारे में भी बात आई। इसके बारे में मैं कफद नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि इस बात का जवाब पहले ही आ चुका है। एक बात रघुनाथ गोयल जी ने वाटर सप्लाई स्कीमों के बारे में कही। उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जो स्कीमें उनके हल्के में सैक्शन हुई हैं उनके लिये पैसा भी एलोकेट किया जाएगा और अगले साल में उनको पूरा भी किया जाएगा। उसके लिये बजट में बहुत पैसा रखा हुआ है। गोयल सहाब बहुत बढ़िया आदमी है और बैठे भी आल इण्डिया लीडर के साथ है इसलिये उनकी बात तो हमें माननी ही पड़ेगी। जनाब, एक बात मेरे साथी राजेन्द्र सिंह जी ने कही कि फरीदाबाद में जुडिशियल कम्पलैक्स की तामीर जल्द की जाए। उसके सारे नक्शे

वगैरह बन चुके हैं और हम उस पर बहुत जल्द काम शुरू करेंगे। एस.वाई.एल. का जो फैसला हुआ है उसके बारे में भी उन्होंने हमें एप्रीशिएट किया है, मैं इसके लिये उनका धन्यवाद करता हूँ कि वे बजट को बहुत अच्छी तरह से समझ पाए हैं। एक उनका प्वायंट यह था कि यू.पी. बार्डर के साथ जो जमना लगती है उस पर यू.पी. साइड से बांध बनने शुरू हो गये हैं, हमारी तरफ से भी बांध बनने चाहिए। कमेटी की तरफ से हमारे सामने यह मामला रखा गया है। एक लम्बा बांध हमारी मुहब्बत पुर के सापा उनके पैरलल जाएगा। उस पर हमारे काम चालू कर दिया है ताकि हमारे लोगों को भी किसी तरह की डिफीकल्टी न आए।

जनाब, उसके बाद कामरेड शंकर लाल जी ने एक बात कही कि जो प्रोमोशन का मामला था उसमें कुछ आदमियों की रिवर्शन का खतरा बन गया है। यह बात चौ. लहरी सिंह जी ने भी रखी थी। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कुछ रिट पैटीशंज की वजह से जोकि अभी कोर्ट में पैडिंग हैं और जिनकी मैरिटस में मैं नहीं जाना चाहूंगा के कारण यह दिक्कत आई है। गवर्नमेंट इस प्वायंट पर लड़ रही है और हरिजन व बैकवर्ड क्लासिज की डिफीकल्टी को दूर करने की कोशिश करेगी, उनकी प्रोमोशन को बरकरार रखा जाएगा। जो प्रोमोशन दी गई हैं, सबको डील करेंगे।

इस बजट के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिन माननीय सदस्यों ने स्पैसीफिक प्वायंटस रखे थे उनको मैं

एक-एक करके डील कर चुका हूँ। मैं जनरल बजट के बारे में यही कहूंगा कि इसकी तमाम कंसैटस को देखते हुए नचुरल क्लायमिटीज की ओर दूसरी तमाम चीजों के बावजूद हम अपनी सेविंग प्रोसैस पर हैं। मैं बाबू जी की कथनी से सौ फीसदी यकीन करता हूँ कि बहुत अच्छा बजट पेश किया है। बाबू जी ने यह भी कहा है कि यह बजट हरियाणा स्टेट की तरक्की के लिय निहायत शानदार बजट साबित होगा। इसलिये मैं सारे हाउस से प्रार्थना करता हूँ कि इस बजट को पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: अब सदन सोमवार 29 मार्च, 1982 प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है।

13.30 बजे

(तत्पश्चात् सदन सोमवार 29 मार्च, 1982 प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुआ)